अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 7 नवंबर 2024

एक मतपत्र बंदूक की गोली से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। -अब्राहम लिंकन।

मीडिया के एक वर्ग के पूर्ण समर्थन के बावजूद कमला हैरिस जनता के बीच अपनी बात स्पष्ट ढंग से नहीं पहुंचा सकीं। जबकि, ट्रंप मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब रहे कि वह अमेरिका के लिए क्यों जरूरी हैं। भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए ट्रंप सरकार के साथ संबंधों को दिशा देनी चाहिए।

आखिरकार ट्रंप

आर्थिक अनिश्चितताओं से ग्रस्त वैश्विक परिदृश्य में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो यह निश्चित ही ऐतिहासिक क्षण है, जिसका असर न सिर्फ अमेरिका, बल्कि वैश्विक राजनीति खासकर भारत पर भी पड़ेगा। हालांकि, दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच जैसी कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, वैसी दिखी नहीं। निर्णायक माने जा रहे सात स्विंग राज्यों में भी ट्रंप का जलवा कायम दिखा। दरअसल, महंगाई, बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय युद्धों में अमेरिका की निष्क्रियता जैसे मुद्दों के चलते सत्तारूढ़ पार्टी पहले ही दबाव में थी। ट्रंप की आक्रामक घोषणाओं के चलते चुनाव के करीब तीन महीने पहले पार्टी के अंदरूनी विरोध के चलते जो बाइडन को चुनावी मैदान छोड़ना पड़ा था, जबकि चार वर्ष तक सत्ता से बाहर रहने और तमाम विवादों के बावजूद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सबसे पसंदीदा नेता बने रहे, जिससे अमेरिकी राजनीति में उनके कद का ही पता चलता है। परेलू मीडिया के एक वर्ग के पूर्ण समर्थन के बावजूद कमला हैरिस जनता के बीच अपनी बात स्पष्ट ढंग से नहीं पहुंचा सकीं। लेकिन दूसरी तरफ, ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब रहे कि वह वैश्विक युद्धों को तो रुकवा ही सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के पुराने गौरव को भी वापस बहाल करा सकते हैं। अवैध आप्रवासन भी एक बड़ा मुद्दा था, जिसके बारे में ट्रंप का रुख एकदम स्पष्ट था कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकावासियों के लिए है। हालांकि उनका यह कहना कि राष्ट्रपति बनने पर वह अमेरिका में आने वाली सभी वस्तुओं पर दस फीसदी आयात शुल्क लगाएंगे और उनकी संरक्षणवादी नीतियां भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। दरअसल, ट्रंप की जो राजनीतिक शैली है, उससे कई बार उनके सहयोगी राष्ट्र भी असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन, ट्रंप ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और हाल ही में दिवाली के अवसर पर

शुभकामनाएं देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को एक बार फिर अपना मित्र बताया, उससे भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से उम्मीदें बंधती ही हैं। इसके अतिरिक्त, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार का समर्थन पा रही कनाडा की वूदो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। जाहिर है, ट्रंप की वापसी अपने साथ नए राजनीतिक अवसरों को भी लाई है। चूंकि चीन के संतुलन में अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। ऐसे में, वैश्विक समीकरणों में आए हालिया बदलावों के मद्देनजर भारत के लिए जरूरी है कि वह रणनीतिक संतुलन और नीतिगत सतर्कता बनाए रखते हुए ट्रंप सरकार के साथ संबंधों को आगे बढ़ाए।

जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा

महंगाई, अवैध आप्रवासन, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में अशांति को लेकर ट्रंप की स्पष्टवादिता ने ही उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका को फिर महान बनाने के वादे को पूरा करने की चुनौती तो होगी, लेकिन भारत की नजर इस पर होगी कि वह द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह से आगे ले जाते हैं।

अमेरिकी चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली स्पष्ट जीत के पीछे महंगाई, बेरोजगारी, अवैध आप्रवासन, व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी अशांति को लेकर उनकी स्पष्टवादिता को ही श्रेय दिया जाना चाहिए। वहीं, कमला हैरिस महत्वपूर्ण मौकों पर कई मुद्दों पर अपनी कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सकीं। वह राष्ट्रपति जो बाइडन की छाया से ही आगे नहीं निकल सकीं। इतना ही नहीं, जो भारतवंशी पहले कमला हैरिस की ओर झुकाव रखते थे, वे भी ट्रंप की ओर हो गए।

कमला के भारतवंशी होने की वजह से अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ गए थे, लेकिन पिछले चार वर्षों में उपराष्ट्रपति रहते हुए वह कभी भारत नहीं आईं। हैरिस का झुकाव भारतवंशियों के बजाय अप्रीकी समुदाय के साथ ज्यादा रहा। दूसरी ओर, ट्रंप ने खुलकर हिंदुओं का पक्ष लिया। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो भारतवंशी समाज पहले डेमोक्रेट्स के पक्ष में रहता था, वह भी रिपब्लिकन की ओर खिसक गया। डेमोक्रेट्स का झुकाव अवैध प्रवासियों की ओर था, जो उनको वहां की नागरिकता देने के साथ ही वोट देने का अधिकार भी देना चाहते थे। ट्रंप ने इस पर सख्ती करने का वादा किया और जीत के बाद भी इस वादे को पूरा करने की बात भी कही है।

शशांक
पूर्व विदेश सचिव

बाइडन अंत तक खुद राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने बेशक रहे, लेकिन सच तो यही है कि वह पहली ही बहस में ट्रंप से पिछड़ चुके थे। जी-20 या जी-7 जैसे अहम सम्मेलनों में भी बाइडन के हावभाव ही उनके दुश्मन बन गए थे। तिस पर जब पार्टी ने दबाव बनाया, तब वह पीछे हटे और कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया। कमला को चुनाव प्रचार करने का कम समय मिला और वह अपनी ऐसी कोई छवि नहीं बना सकीं कि वह बाइडन से इतर कुछ नया करेंगी। दूसरी तरफ,

ट्रंप अपने रुख पर कायम रहे, जिससे वह मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके।

अमेरिका के चुनावी नतीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी कमला के बजाय ट्रंप को ज्यादा पसंद किया जाना, यही दर्शाता है कि ट्रंप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत ही होंगे। उनके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। व्यापार टैरिफ को लेकर भले ही ट्रंप ने कहा है कि वह भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इस मसले को भारत कूटनीति के जरिये निपटा लेगा। दरअसल, ट्रंप का मुख्य उद्देश्य चीन पर नकेल कसना है। ट्रंप के कार्यकाल के पिछले चार वर्षों को देखा जाए, तो उनके भारत से ताल्लुकात ठीक रहे थे। भारत-चीन संबंधों को अमेरिका के नजरिये से देखें, तो अमेरिका की शुरू से ही चीन को लेकर स्पष्ट नीति रही है, सत्ता में चाहे डेमोक्रेट्स रहें या रिपब्लिकन। अमेरिका चीन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। ट्रंप भी उसे जारी रखना चाहेंगे, लेकिन वह भारत के हितों को महत्व देंगे।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बना रहा है। यह भारत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए चीन पर नियंत्रण के लिए भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध होना आवश्यक है। अमेरिका भी समझता है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण साझीदार है। बाइडन के समय भी भारत को तवज्जो मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी संसद में भाषण दिया था, लेकिन बाइडन के कार्यकाल में कुछ ऐसे मुद्दे थे, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं थे। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप कनाडा ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए से मिले स्रोतों के आधार पर लगाया था। उसने खबर भी अमेरिकी अखबार में छपवाई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भी बाइडन सरकार ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। संभावना है कि ट्रंप के आने के बाद से इस तरह की बातें नहीं होंगी। कनाडा के भारत के प्रति रुख में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं।

अमेरिका की हर गतिविधि का असर वैश्विक और भू-राजनीतिक संबंधों पर होता है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तो उनके कार्यकाल में दुनिया में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बाइडन के रहते रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। पश्चिमी एशिया में हालात बिगड़ गए। नाटो के अस्तित्व पर भी सवाल उठे। अब ट्रंप के सामने चुनौती यह होगी कि उन्होंने जो वादे किए हैं, उन्हें किस तरह पूरा करेंगे। अमेरिका में महंगाई रोकने के लिए उन्होंने करों में कटौती का वादा किया, जिसे वह पद संभालते ही पूरा कर सकते हैं। वह अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा सकते हैं। चीन समेत अन्य देशों से आयात होने वाले सामान पर भी वह टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इन तीन स्रोतों को पूरा करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे मुश्किल चुनौती यह है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राइल का गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला तथा ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उनको वह किस तरह रुकवाते हैं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान यही वादा उनके पक्ष में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को तत्काल रुकवा देंगे। पश्चिम एशिया के हालात पर भी नियंत्रण कर लेंगे।

वहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस और उनकी पार्टी इस मामले में पिछड़ गई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से मुस्लिम देशों के कई लोग यूरोप पहुंच गए हैं। इसके लिए यूरोप वाले डेमोक्रेट्स और उनकी नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। भले ही यूरोपीय देश खुलकर कुछ न कहते हों, लेकिन डेमोक्रेट्स की कई नीतियां ऐसी रहीं, जो अमेरिका के साथ ही दुनिया भर में उनके खिलाफ होती चली गईं। इन सबका फायदा अंततः ट्रंप को ही मिला है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

मार्कस ऑरेलियस

प्रत्येक कार्य को इस तरह करें जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो, और भावनाओं को अपने मन पर हावी न होने दें, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा।

हम इस धरा पर कुछ पल के लिए

इस संसार में हर चीज बहुमूल्य है। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, जो आपसे प्रेम भी करेंगे और घृणा भी। हम लोगों के प्रभाव में आकर अधिकांश समय चिंतित रहते हैं। इंद्रियों पर भी विचार करें, विशेषकर उन पर जो हमें सुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। विचार करें कि कितनी जल्दी सभी चीजें विलीन और विघटित हो जाती हैं। शरीर और पदार्थ स्वयं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं।

विचार की शक्ति मनुष्य को यह दिखा देगी कि ये चीजें कितनी घृणित और तुच्छ हैं, और कितनी जल्दी वे मुरझा जाती हैं और मर जाती हैं। उस मनुष्य की जिज्ञासा से अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता, जो सर्वत्र घूमता है, जो अनुमान

द्वारा अन्य लोगों के विचारों में प्रवेश करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त रहता है, किंतु यह नहीं समझता कि अपने भीतर के देवत्व का सम्मान करना तथा उसकी सेवा करना ही पर्याप्त है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस धरा पर हम कुछ पल के लिए ही हैं। खुद को यह नहीं भूलने दें कि कितने जान बचाने वाले डॉक्टर भी मर गए, कितने मृत्युशय्या पर अपनी भौंहें सिकोड़ते हुए, कितने ज्योतिषी, दूसरों के अंत और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करते हुए, कितने दार्शनिक, मृत्यु और अमरता पर अंतहीन विमर्श करते हुए, कितने योद्धा, हजारों लोगों को हताहत करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कितने ऐसे अत्याचारी लोग जो स्वयं को अमर समझते रहे और जीवन और अपनी शक्ति का क्रूर तरीके से दुरुपयोग करने के बाद मिट्टी में विलीन हो गए। हर एक इन्सान आज नहीं तो कल विलीन हो जाएगा, इसलिए इस बात पर चर्चा न करें कि एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए।

मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अपितु इस बात से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि वह कभी जीना शुरू ही न कर पाए। हर चीज हमारे विचारों पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में खुशी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, जबकि हम बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आप किसी बाह्य वस्तु से परेशान हैं, तो यह पीड़ा उस वस्तु के कारण नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपके आकलन के कारण है। आपमें इसे किसी भी क्षण वापस लेने की शक्ति भी है। इसलिए अपने भीतर विचारों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। दरअसल, समय एक नदी की तरह है, जो घटनाओं को पार करती है और इसकी धारा बहुत तेज होती है। जैसे ही कोई चीज नजर आती है, वैसे ही वह बह जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। यदि आप प्रत्येक कार्य को इस तरह करें, जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो, और अपनी भावनाओं को अपने मन पर हावी होने न दें, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा।

एक छोटा कदम बढ़ाएं

सूत्र

मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना या भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीने में है। हमारी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हर दिन, एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं और जल्द ही आप खुद को उस जगह से मीलों दूर पाएंगे, जहां से आपने शुरुआत की थी।

स्मृति-शेष

जैसा गाया वैसा जिया

महाकवि लोकगायिका शारदा सिन्हा का जीवन भी उनकी गायकी की तरह ही निश्छल रहा, जो सादैव उनके व्यवहार में झलकता था।

मैं स्कूल में थी, उस समय दोहे और कविताएं गाने की तरह गाने की आदत थी। मेरे पिताजी ने देखा कि मैं इतनी छोटी उम्र से कविता को गेय बना के याद कर रही हूं, तो वह समझ गए कि मेरे भीतर शायद कोई गायिका है। उन्होंने इसे सराहा और मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में हर घर में हारमोनियम और तबला होता था और बच्चों को संगीत के बुनियादी सुर सिखाने के लिए संगीत शिक्षक रखे जाने का भी रिवाज था। मेरी संगीत शिक्षा शास्त्रीय संगीतकार पंडित रामचंद्र झा जी के सानिध्य में शुरू हुई।

उन्होंने ही मुझे प्राथमिक स्तर पर आवश्यक बुनियादी रागों की शिक्षा दी। हालांकि, लोक संगीत को आकार देने का पहला चरण मेरे भाई की शादी से शुरू हुआ था। मुझे याद है, जब मेरे भाई की शादी थी, तब मेरे भाई और भाभी ने मुझसे गाने को कहा, जो एक रस्म का हिस्सा था। मैंने झट से मैथिली में एक गीत बना लिया, 'द्वार के छकाई नेग पहिले चुकाइहो हो दुलरुवा भैया, तब जइहा कोहबर आपन, हो दुलरुवा भैया'। आगे चलकर यह गीत ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड होने वाला पहला संस्कार गीत बना। मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि आप कई क्षेत्रीय भाषाओं में गाती हैं, तो आपकी पंसदीदा भाषा कौन-सी है? इसका जवाब देना वाकई मुश्किल लगता है। मैं बिहार के मिथिला क्षेत्र से हूं और मेरी मातृभाषा मैथिली है। लेकिन मुझे भोजपुरी से भी उतना ही प्यार है। मैं अपने भोजपुरी गीतों में मैथिली की धुन भरने की कोशिश करती हूं। ये जो रिश्ता है, वह एकदम कृष्ण का देवकी-यशोदा के साथ जैसा है। मुझे डर है कि आने वाली पीढ़ियां भोजपुरी के असली सार को नहीं समझ पाएंगी। यह एक सुंदर और लचीली भाषा है, जिसमें अपनी भावनाएं हैं। इसमें शब्दों के बिना लेकिन कुछ भावों के साथ संदेश देने की शक्ति है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के भोजपुरी गाने हैं, उसमें असली सार नहीं है। टैलेंट हंट में जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें काफी संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि नकल कर के सिर्फ गीतों को गाकर गायक बनने का ख्वाब न पालें। हो सकता है यह तुरंत सफलता दिला भी दे, लेकिन यह लंबा नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य रखें और जो गाएं, उसे अपने जीवन में निभाएं भी। मैं तो इसी राह पर चली। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, गाना आपकी आवाज में आसानी से समा जाएगा।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

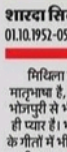

शारदा सिन्हा
01.10.1952-05.11.2024

मिथिला मेरी मातृभाषा है, लेकिन भोजपुरी से भी उतना ही प्यार है। भोजपुरी के गीतों में भी मैथिली की धुन भरने की कोशिश की।

आंकड़े

दलहन उत्पादन

दालों को सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। भारत दलहन के उत्पादन में दुनिया भर में शीर्ष पर है।

भारत	27.8%
कनाडा	6.7%
चीन	5.2%
नाइजीरिया	4.6%
रूस	4.3%

आंकड़े वैश्विक स्तर पर दलहन उत्पादन के, प्रतिशत में | स्रोत : FAO

विष्णुस्वामी ने भगवान की प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक भक्ति की। अंत में जब उन्होंने अन्न-जल त्याग दिया, तो भगवान को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा।

विष्णुस्वामी

विक्रम संवत 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के राजा के मंत्री के यहां विष्णुस्वामी का जन्म हुआ था। यज्ञोपवीत संस्कार के कुछ ही दिनों बाद विष्णुस्वामी को सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान हो गया था। उन्होंने मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी का विचार किया, लेकिन उनको अपने अभीष्ट के दर्शन नहीं हुए।

इसके बाद विष्णुस्वामी ने उपनिषदों के अनुसार भगवान की भक्ति की। कई वर्ष बीत जाने पर भी विष्णुस्वामी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने अन्न-जल त्याग दिया। सातवें दिन वह भूख-प्यास से काफी व्याकुल हो गए। अंत में उन्होंने तय किया कि भगवान की प्रतीक्षा में वह चिरहर की अग्नि में खुद को भस्म कर देंगे। इसी दौरान उनका हृदय प्रकाशमान हो गया। आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि भगवान उनके सामने थे। भगवान ने विष्णुस्वामी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। विष्णुस्वामी ने भगवान से कहा कि उन्हें उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह है। भगवान ने उनका संदेह दूर करते हुए उपनिषदों को गुह्यतम तत्व का रहस्य बताया और कहा कि अपने मन में संदेह को स्थान न दो। अक्षिशीष और अनिर्वचनीय परम तत्व मैं ही हूं। विष्णुस्वामी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप सर्वदा मुझे दर्शन दें। एक मूर्तिकार को बुलाकर मूर्ति बनवाई और भगवान उसमें समा गए। विष्णुस्वामी आजीवन 'श्रीकृष्ण तवास्मि' मंत्र का जाप करते रहे।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 अक्तूबर, 1961

पंचतत्व में विलीन हुए महाकवि निराला

महाकवि निराला का देहावसान

हिंदी के महान विद्वान और अपने युग के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 62 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। निराला जी पिछले एक वर्ष से बीमार थे।

क्या एआई किसी की आत्मकथा लिख पाएगा

मशीन कई तरह के काम कर सकती हैं, लेकिन भावनाएं, एहसास और इन्सानी खयालात की उससे उम्मीद करना तर्कसंगत नहीं है।

श्यौराज सिंह 'बेचैन' — **तकनीकी**

पिछले महीने गोवा विश्वविद्यालय के द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में 'मुखरधारा और दलित साहित्य' पर बीज वक्तव्य देने, सत्र की अध्यक्षता करने और बतौर 'विजिटिंग प्रोफेसर' साहित्य, पत्रकारिता, आत्मकथा और कविता आदि प्रमुख विधाओं पर आठ व्याख्यान रिकॉर्ड कराने का सतत संयोग बना। सेमिनार में डॉ. शरण कुमार लिंबाले ने दिलचस्प संयोग साझा किया, 1986 में मैं मराठी साहित्य की परीक्षा दे रहा था।

प्रश्न 'अक्करमासी' (आत्मकथा) पर पूछे गए, लेकिन जब परिणाम आया, तो मेरे अंक सबसे कम थे। मैंने परीक्षा नियंत्रक से जिरह की, 'मेरी आत्मकथा पर मुझसे अच्छा और कोई कैसे लिख सकता है। मैंने तो वह भी लिखा है, जो आत्मकथा लिखते हुए छूट गया था।' तो इसका जवाब मिला कि पाठ से इतर जानकारी मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हो सकती। 'अक्करमासी' के प्रकाशन को चालीस साल पूरे हो गए, परंतु दूसरी आत्मकथा मशीन तो क्या, इन्सान भी नहीं लिख पाए।

तो क्या मौलिकता के चरकस कृत्रिम मेधा साहित्यिक उत्पादन के खाली स्थान भर देगी? पाठक और श्रोताओं की प्रश्नाकुलता स्वाभाविक थी। यह विमर्श ऐसे समय में हो रहा था, जब अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन होपफील्ड और ब्रिटिश कंप्यूटिंग जैफ्री हिंटन को संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग या कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। स्वाभाविक तौर पर दावे किए जाने लगे कि एआई बौद्धिक क्षमता में इन्सान को मात दे सकती है। साहित्यिक विमर्श के क्षेत्र में भी इस बहस ने जगह ले ली। एक पक्ष ने इसे 'मशीनी क्रांति' कहा, तो दूसरे पक्ष ने इसे भ्रांतिपूर्ण खतरा माना। पर तकनीक क्रांति के भावी योगदानों की संभावनाओं और हमारी निर्भरताओं को तार्किक व वस्तुगत ढंग से झुठलाया नहीं जा सकता। मानवीय ज्ञान के विकास को याज्ञाएं समय सापेक्ष चमत्कार जैसी भी हुआ करती हैं।

ऐसे में यह प्रश्न भी उठा, कि 'गैर-दलित, परकाया प्रवेश कर दलित साहित्य क्यों नहीं लिख सकते?' जब मशीन से मनुष्य की कहानी लिखने की उम्मीद की जा रही है, तो इन्सान से नाउम्मीदी क्यों? जब विषय के तौर पर प्रोग्रामिंग के परिणामस्वरूप मशीन लिख सकती है, तो दलित लेखक व गैर-दलित अन्योन्यग्रंथित विषयक साहित्य क्यों नहीं लिख सकते? अन्यथा इन पंक्तियों के लेखक को 'जिंदगी को इंढ़ते हुए' आत्मकथा लिखने की जरूरत क्या थी? बीती सदी के अस्सी-नब्बे के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आ रहा था, तो ये आशंकाएं भी उभर रही थीं, कि कंप्यूटर सी हाथों का काम छीन लेगा। लेकिन कंप्यूटर से भी रोजगार उत्पन्न हुए। ज्ञान-कौशल से संपन्न दो-तीन पीढ़ियां आ गईं। हां, जिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें तकनीक प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण जिंदगी भी सुलभ नहीं हुई। उनके लिए अवसर कम हुए और एआई की आमद से भी ऐसी ही आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं।

भावनाएं, एहसास और इन्सानी खयालात की मशीन से उम्मीद करना तर्कसंगत नहीं है। मशीन का प्रेम इजहार, इन्सान की प्रेमाभिव्यक्ति की जगह नहीं ले सकता। पश्चिमी देशों में चर्चा है कि मशीन सेकंडों-मिनटों में कविता-कहानी लिख सकती है, जबकि इन्सान लिखने-सोचने में अधिक समय लेता है। यहां तो कोई आत्मपरक कहानी दशकों तक स्मृतियों में पड़ी रहकर कागज पर उतरती है। कहानीकार डेविड मीन्स ने सही कहा है, 'एआई यंत्र मेरी बिल्ली पर कहानी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी यादें मेरी कल्पना के 'लताड़' में बसती हैं।' यहां प्रसंगवश हम सह-संवेदना को परखने की चेष्टा करते हैं। दस अक्तूबर को इन पंक्तियों का लेखक पूना में 'मैपल पॉड' के संस्थापक-निदेशक आयुष सिंह के निवास पर ठहरा था। यह फ्लैट प्रथम तल पर था और आगे करीब साठ मीटर के आंगन में घास, फूल खिल रहे थे। आयुष ने बेली, मेची और चैपे नामक तीन बिल्लियां पाली हैं। हमने दरवाजा खोला और बिल्लियों को खेलने-कूदने के लिए आजाद कर दिया। करीब एक घंटे बाद आयुष ने पूछा, 'चैपे कहां है? यहां तो दो ही दिख रही हैं, वह नीचे गिर गई होगी, उसे बाज या चील उठा ले गई होगी, अथवा नीचे गिरते ही कोई व्यक्ति उठाकर ले गया होगा। वह पंद्रह हजार की बिक जाएगी। वह मेरे लैपटॉप से सटकर ही बैठती थी। उसे मैं अपने बिस्तर में सुलाता था, उसे अब नींद कैसे आएगी?'

आयुष को बिल्लियां पालने का शौक ब्रिटेन की चेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के समय से है। हमें लगा, यह तो अनजाने ही बड़ी गलती हो गई। नींद तो 'बिल्ली-प्रेमी' आयुष के साथ-साथ मेरी भी उड़ गई, क्योंकि मैंने ही उन्हें आजाद करने का सुझाव दिया। आयुष की फॉलिंग्स कहानी का एक-एक वाक्य ऐसे रच रही थी, जैसे इन्सानी लगाव का भाव समा रहा हो। आयुष की एक कहानी *'अंधेरे में लड़की'* 2017 में *'हंस'* में भी छपी थी। यों मशीन, जानवर, इन्सान और संवेदना सब की नई-नई परिभाषाओं की दरकार थी।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बृहस्पतिवार • 7 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

निजी बनाम सार्वजनिक

नागरिकों के संपत्ति के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच ने दो के मुकाबले सात के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि संविधान के अंतर्गत सरकारों को जन कल्याण के लिए हर निजी स्वामित्व वाले संसाधन को अधिगृहित करने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से ध्वनित होता है कि विश्व व्यवस्था बदल रही है, देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है और इसी के साथ निजी संपत्ति रखने से संबंधित विचार भी बदल गए हैं। इसे दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि अदालत ने इस फैसले ने देश के संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को शिथिल किया है। सत्तर और अस्सी के दशकों में रूस, चीन समेत पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में समाजवादी-मार्क्सवादी सरकारें थीं जिनका विश्वास था कि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए संपत्ति का पुनर्वितरण आवश्यक है।

लिहाजा, सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का समाजवादी विचारों के प्रति विशेष आकर्षण था। इंदिरा गांधी ने इसी विचार से प्रेरित होकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स के अधिकार को निरस्त किया था। आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। शायद इसी पृष्ठभूमि में 1978 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया होगा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का जनहित में अधिग्रहण कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारों से प्रेरित था। हालांकि संविधान पीठ के दो जजों ने अलग से अपना फैसला दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पीठ के सात जजों से आंशिक तौर पर असहमति व्यक्त की जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने सात जजों के फैसले के सभी पहलुओं से असहमति जाहिर की। बहरहाल, समाज परिवर्तनशील है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में संपत्ति के अधिकार के नये सिद्धांत विकसित हो रहे हैं। परिवर्तन का स्वागत करने वाला समाज ही गतिशील और आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।

चली गईं शारदा

पांच नवम्बर की देर रात जब भोजपुरी कोकिला एवं गायकी की समृद्ध परंपरा कही जानी वाली शारदा सिन्हा के न रहने की खबर आई तो संसार चलते-चलते अचानक से ठहर गया। संपूर्ण मैथिली-भोजपुरी समाज के अलावा समूचे संसार के लिए शारदा सिन्हा का बिसर्जन गहरा आघात है। पूर्वांचल की बगिया से कोयल के उड़ जाने जैसा है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का नश्वर दुनिया को अलविदा कह देना। संगीत की दुनिया में शारदा का न रहना, 'कोयल बिना न सोभे बगिया', जैसा माना जाएगा। आठ भाइयों के बाद वह जन्मीं। जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। जन्म के दो वर्ष के भीतर ही उन्होंने गाना गुनगुनाना आरंभ कर दिया था। 15 वर्ष में उनकी खनकती आवाज के लोग दीवाने हो गए थे। जब उनकी शादी हुई, तो सास को कतई पसंद नहीं था कि उनकी बहू गाना-वाना गाए। लेकिन नियति को शायद यही पसंद था। भारी विरोध के बाद भी उन्होंने गायन यथावत रखा। जब देश-विदेश से प्रशंसाएं मिलने लगीं तो सास ने भी कह दिया, बहु तुम अच्छा गाती हो, गाती रहो। जब लीन होकर पूरे मदहोश में वह गाती थीं तो लगता था कि उनके कंठ में स्वयं सरस्वती बैठी हुई हैं। शारदा सिन्हा के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अंशुमन सिन्हा और एक बेटी वंदना। शारदा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन भी इसी वर्ष हुआ। उनके जाने के बाद से वह पूरी तरह टूट गई थीं। सलमान खान और भाग्यश्री अभिनीत फिल्म 'मैंने प्यार किया' में गाया गाना....'कहे तोसे ये तोहरी सजनिया' ....इतना फेमस हुआ कि उन्हें रातोंरात बड़ा फिल्मी सिंगर बना दिया। शारदा सिन्हा को राजनीति के आँफर भी बहुतेरे मिले। लेकिन शारदा सभी आँफरों को ठुकराती गईं। कई मर्तबा उन्होंने कहा भी कि उन्हें राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं। छठ के गानों के अलावा भी उन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक से एक हिट गाने दिए। शारदा का जन्म बिहार के जिले सुपौल के हुलास गांव में हुआ था। विवाह बेगूसराय में हुआ। वह गायिका के साथ-साथ प्रोफेसर भी रहीं। बीएड की पढ़ाई के अलावा म्यूजिक स्ट्रीम में पीएचडी करके समस्तीपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर बनीं। कॉलेज से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने संगीत की फ्री शिक्षा देना जारी रखा। उनके न रहने से एक युग का अंत हुआ है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी मीठी, मधुर, सुरीली आवाज श्रोताओं के कानों में सदा गुंजेगी।

कटाक्ष/ सहीराम

सुरक्षित-असुरक्षित

जी यूं तो देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन समस्या यह है कि विपक्ष वालों के चुनाव में उतरने मात्र से वह असुरक्षित हो जाता है। लेकिन असुरक्षा तो असुरक्षा है न साहब, सो विपक्ष वालों के चुनाव में उतरने मात्र से प्रधानमंत्री को लगने लगता है कि देश तो भैया असुरक्षित हुआ जा रहा है। नहीं-नहीं, उतना नहीं कि उन्हें फौज को अलर्ट करना पड़े, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस-प्रशासन को अलर्ट करना पड़े। बस, वे तो उसे इतना सा ही असुरक्षित होने की छूट देते हैं कि मतदाताओं के मन में बैठ जाए कि देश असुरक्षित हुआ चाहता है और वे विपक्ष वालों को वोट न दें। सो, प्रधानमंत्री को आगाह करना पड़ता है कि अगर विपक्ष वाले आ गए तो महिलाओं का मंगलसूत्र ले जाएंगे। शहरों में झपटमार महिलाओं की चेन झपट ले जाते हैं। चिंता उसकी नहीं है। हो सकता झपटमारों का लेवल थोड़ा ऊंचा हो। प्रधानमंत्री ऊंचे लेवल की बात नहीं करते। सिर्फ अपने लेवल की बात करते हैं जैसे नोटबंदी में उन्होंने महिलाओं से आटे-चावल के डिब्बों में छुपाए उनके नोट ही निकलाए थे, चेन नहीं झपटी थी। मंगलसूत्र को भी वख्श दिया था, शायद इसलिए कि यह बाद में विपक्ष वालों पर इल्जाम लगाने के काम आएगा। सो, अभी रहने दो। लोक सभा चुनाव ने उन्हें यह मौका दिया। इतना कि मंगलसूत्र की चिंता जता कर उन्होंने महिलाओं को रसोई की चिंता से मुक्त कर दिया।

फिर उन्होंने किसानों से कहा कि विपक्ष वाले तुम्हारी एक भैंस ले जाएंगे। गाय का जिक्र इसलिए नहीं किया कि गौरक्षक गौमाता की रक्षा में इतने सन्नद्ध रहते हैं कि फिर इंसानों को भी नहीं बख्शते। किसानों पर अपनी भैंस बचाने की चिंता इस कदर सवार हुई कि फिर उन्होंने न एमएसपी याद किया और न ही मंडियों में अपनी फसल की बेकद्री को। खैर जी, अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आ गए तो तुम्हारी बेटियों भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मतदाताओं को बेटियों को बचाने की चिंता में इतना डाल दिया कि अब वे कठुआ से लेकर हाथरस तक अपनी बेटियों की असुरक्षा को भूल जाएंगे। वे बीएचयू के रेप कांड को भूल जाएंगे। सारे बलात्कारियों और हत्यारों को भूल जाएंगे और बस, घुसपैठियों से अपनी बेटियों की रक्षा में लग जाएंगे। चुनाव का क्या है जी, चुनाव तो वे जीत ही लेंगे।

अनमोल वचन

सच्चे वीर को युद्ध में मृत्यु से जितना कष्ट नहीं होता उससे कहीं अधिक कष्ट कायर को युद्ध के भय से होता है।
-भर्तृहरि

शारदा सिन्हा : लोक संगीत का सूर्य

श्रद्धांजलि

आलोक पराड़कर

समय बदलते रहे, बच्चे बड़े और बड़े बूढ़े होते गए, नये-नये गैजेट्स आते रहे, संगीत उद्योग करवट लेता रहा, बहुत सारे गायक-गायिकाओं के गीत गूंजते रहे लेकिन शारदा सिन्हा लंबे समय तक लोगों की पसंद बनी रहीं। उनके नाम को सम्मान के साथ लिया और सुना जाता रहा था तो इसकी कई वजहें भी थीं। संगीत की विभिन्न विधाओं की जानकारी होने, संगीत की शिक्षिका होने के बावजूद उन्होंने लोक संगीत की माटी से जुड़े उसके सौंधेपन, उसकी अनगढ़ता, उसके खुरदुरे शिल्प को बड़े जतन से बचाए रखा। यही कारण था कि जब वे गातीं तो लोक उससे जुड़ जाता था, अपने बीच का लगता रहा। वे साली-साल घर-घर में पटना से वैदा बुलाती रहीं, बंगाल से सिंदूर मंगवाती रहीं, तनी ताक तक द बलमुवा की मिन्नत करती रहीं, लोग थे कि इस पुकार में अपने स्वर मिलाते रहे, मुस्कुराते और लजाते रहे। जगदंवा घर में दियरा.., शिव मानत नहीं.. जैसी भक्ति रचनाएं वर्षों तक लोगों की प्रार्थनाओं में शामिल रहीं। शारदा सिन्हा ने केकरा से कहां मिले...से जो लोकप्रियता पाई थी, वह उनकी लंबी संगीत यात्रा

में कभी कम होती नहीं दिखी। वे हर घर-परिवार में कई-कई पीढ़ियों तक शामिल रहीं, उसके सुख-दुख को स्वर देती रहीं। भोजपुरी समाज की कल्पना शारदा सिन्हा के बीच अधूरी-सी लगती है। उनके गीतों ने न सिर्फ लोकप्रियता की ऊंचाई को छूआ, बल्कि उस लोकप्रियता को लगातार कायम भी रखा।

लेकिन जमाना कितना भी बदला, बोल्ड और बिंदास हुआ, भोजपुरी को व्यावसायिक फायदे का चस्का लगा, अश्लील, फूहड़ और द्विअर्थी चाशनी गीतों में मिलाई गई, शारदा सिन्हा के निश्चय को कोई डिगा नहीं सका। उन्होंने अपने गीतों में मर्यादा से कोई समझौता नहीं किया। भोजपुरी पर कीचड़ उछाले जाते रहे लेकिन शारदा सिन्हा का आंचल कभी मैला नहीं हुआ। उन्होंने फिल्में चुनीं तो राजश्री बैनर की और जब कभी किसी और के लिए भी गाया तो शालीनता से समझौता नहीं किया, हिंसा और गालियों से भरी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में भी वे तार बिजली...ही गाकर लौट आईं।

शारदा सिन्हा ने एक बार बताया था कि छठ के गीतों को पहले-पहल रिकार्ड कराने जब वे गईं तो एचएमवी वाले तैयार नहीं थे। वे इन गीतों को समझते नहीं थे। वे इन्हें नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार इनकी भाषा बहुत कठिन थी। 1978-79 में गाया था उन्होंने -'अंगना में पोखरी खनाय...'। जब यह आया तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। 2016 में एक बार फिर कॉलिंमान बना जब उन्होंने 'पहिले पहल...' गाया। छठ की एक घटना के बारे में उन्होंने बताया था, 'एक बार की बात है कि पटना में बहुत इच्छा हुई कि छठ करूं। सीधा पल्ला करके, सिर पर आंचल लेकर जाने की सोची जिससे लोग पहचान न सकें। कुछ मीडिया वाले भी साथ हो गए, बोले कि हम आपको ले चलेंगे। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला मुझे दिखीं जो दंडवत प्रणाम करते छठ की पूजा को जा रही थीं। मेरी इच्छा उन्हें प्रणाम करने की हुई लेकिन मैं जैसे ही उन्हें प्रणाम करने को झुकी, लोगों ने मुझे पहचान लिया। फिर तो सैकड़ों लोग मुझे ही प्रणाम करने लगे। मैं बुरी तरह घिर गई, बहुत घबरा गई। किसी प्रकार पुलिस आदि की मदद से मुझे निकाला जा सका। उसके बाद मैं कभी घाट पर नहीं गई।' वह कहती थीं, 'छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ ही डूबते सूर्य की भी पूजा होती है। ऐसा हमारे यहां ही होता है। उगते सूर्य को तो दुनिया प्रणाम करती है, इसको लेकर मुहावरा भी है लेकिन डूबते सूर्य की पूजा हमारी परंपरा में है। अंधकार के बाद फिर प्रकाश आता है। उजाले की, प्रकाश की प्रत्याशा, उसकी उम्मीद में अंधकार को भी प्रणाम करते हैं। डूबते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं कि आपको फिर उगकर हमें प्रकाशित करना है। यह हमारी आशा है, हमारे मन का विश्वास है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश को आना है। सूर्य को डूबना है लेकिन अगले दिन उगकर हमें फिर प्रकाशित करना है।'

शारदा सिन्हा को राजनीति के ऑफर भी बहुतेरे मिले। शायद ही कोई ऐसा छोटा-बड़ा सियासी दल हो, जिसने उनको अपने यहां आने का निमंत्रण न दिया हो? लेकिन वे सभी ऑफरों को सहर्ष ठुकराती गईं। कई मर्तबा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी कि उन्हें राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं। समाज ने उन्हें छठ कोकिला की उपाधि दे रखी थी जिसे वह सबसे बड़ा सम्मान ताउम्र मानती रहीं। छठ पर अपनी मीठी आवाज से संगीत प्रेमियों की जुबान पर ऐसे चढ़ी कि कभी उतर ही नहीं पाई। शारदा सिन्हा के गीत केवल डूबते-उगते सूर्य की पूजा के पर्व के गीत तो हैं ही, उन गीतों के पास बैठ कर हमारे जीवन का अंधेरा भी दूर होता है।

वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत समाधान बन कर उभरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति

- आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत समाधान बन कर उभरी है
- बीते एक दशक में भारत से आयुष उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। जरूरी है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन (नवाचार) पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए
- आज आयुष के हर्बल उत्पाद 100 से ज्यादा देशों में पहुंच चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और दक्षिणाई देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं की खासी मांग है
- आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर बल देता है।

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

जो छद्म नारीवादी भारत में पसंद के कपड़े पहनने की आजादी के नाम पर हिजाब को सही साबित करने में लगी थीं, वे अब हिजाब के खिलाफ ईरान में महिलाओं के संघर्ष पर क्यों मौन हैं।

ऋचा अनिरुद्ध, पत्रकार
@richaanirudh

ईमानदारी और शुचिता बेहद जरूरी

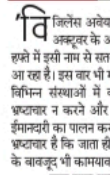

राजनीति डॉ. घनश्याम बादल

'विजिलेंस अवेयरनेस वीक'। जी हां, हर साल देश अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवम्बर के पहले हफ्ते में इसी नाम से सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह मनाता आ रहा है। इस बार भी मना। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भ्रष्टाचार न करने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी का पालन करने की शपथ दिलाई जाती है। मगर भ्रष्टाचार है कि जाता ही नहीं और जागरूकता है कि आने के बावजूद भी कामयाब होती नहीं दिखती।

कुछ साल पहले ही अण्णा हजारे का आंदोलन भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़ा चर्चित रहा और लगा कि आंदोलन से देश की हालत एवं हालात बदलेंगे पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इससे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में सीना ठोक कर कहा था-'न खाऊंगा न खाने दूंगा'। मगर हालत में बहुत ज्यादा बदलाव कहीं नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हटाने के फेल्यौर ने कई सवाल खड़े किए हैं। भले ही संविधान के अनुसार भ्रष्टाचार के लिए यहां कोई जगह नहीं है, मगर भ्रष्टाचार की बीमारी इतने गहरे पैठ गई है कि उसके इलाज के लिए छोटे-मोटे चीरे से काम नहीं चलने वाला। देश सचमुच इस बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो उसे कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी।

आम आदमी से बात करें तो वह साफ कहता है कि भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। एक वाक्य 'ईमानदार वही है जिसे मौका नहीं मिला' कहीं खूल कर तो कहीं दबी आवाज में सुना जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नया हो, भ्रष्टाचार की पदचाप तो यहां अस्सी के दशक से ही सुनाई देने लगी थी। जब पाँचर, राजनीति, ओहदा, सामर्थ्य और भ्रष्टाचार कमोबेश एक दूसरे के पर्याय बन कर उभरते चले गए। याद कीजिए, 1974 में इंदिरा गांधी पर स्टेट बैंक से पैसे निकालने का आरोप, जब कहा गया कि नटवर लाल ने उनकी आवाज की नकल करके यह कृत्य किया था। तब इंदिरा पर किसी ने भी शक नहीं किया था, पर बाद में उनकी ईमानदारी की छवि में भी दम नहीं रहा। 1989-1991 में तो सीधे-सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ही हर्षद मेहता और लक्खू भाई पाठक मामलों में कठघरे में आ गए। उन्हें वेईमान तो

सिद्ध नहीं किया जा सका पर आम आदमी ने शक किया। इससे पहले भी राजीव गांधी पर बोफोर्स मामले में कमीशन के आरोप लग चुके थे, फिर फेयरफैक्स लांकर वीपी सिंह को लपेटने की कोशिश हुई पर चली नहीं जबकि क्वात्रोचि और बोफोर्स का भूत लंबे समय तक जिंदा रहा।

इसके बाद तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार के संदर्भ में वेशर्मी के युग की शुरुआत हो गई। एक दो करोड़ को तो नेता भ्रष्टाचार मानते ही नहीं। करते हैं कि अमुक की हैसियत इतनी है कि इतनी छोटी सी रकम के लिए नहीं गिरेगा यानी गिरावट भी अब हैसियत के अनुसार होने लगी है। हालांकि भ्रष्टाचार ने केंद्र और राज्यों में समय-समय पर अनेक लोगों, नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों की बलि भी ली हैं पर भ्रष्टाचार ने केवल बना और बचा ही रहा अपितु बढ़ता भी गया है, और हालात यहां तक पंहुच गए हैं कि राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों पर हर कोई उंगली उठाता दिख रहा है। कितना अच्छा होता कि लोग इस दोषारोपण पर विश्वास न कर पाते पर आज ऐसे हालात हैं, तो इसके बारे में भी हमें सोचना ही होगा कि आखिर, ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए कि बजाय आरोप लगाने वाले पर शक करने के, लोग जिन पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं।

नेताओं और उनके इर्द गिर्द जुटे अधिकारियों, दलालों, ठेकेदारों की बेतहाशा बढ़ती संपत्ति लोग देख रहे हैं। यह भी कि थोड़े दिन पहले ही सत्ता या राजनीति में आए लोग अचानक कैसे करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं। खैर, समय-समय पर आंदोलन आएंगे और जाएंगे पर यक्ष प्रश्न तो वही है कि भ्रष्टाचार का अजदहा कब और कैसे मरेगा? और मरेगा भी या हमें ही मार कर दम लेगा। इस बात पर चिंतन करने का वक्त अब से बेहतर कब होगा? यह हम सोचें और सोचें मात्र नहीं वरन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकें। ऐसा कुछ करें कि नये लोगों को सीख मिले, पुराने सुधरें और देश का उत्थान हो। जरूरी है नेता ही नहीं अपितु हम यानी आम आदमी भी खुद के अंदर झांके। केवल, रजाई, दारु, जाति, धर्म, संप्रदाय से विरत हो अच्छे और सच्चे लोगों को ही संसद और विधानसभाओं में भेजें। माना भूख है, गरीबी है, डर है, पर हर डर के आगे जीत है। वही जीत पाने का वक्त है आज। यदि भ्रष्टाचार के बेलगाम घोड़ों को रोकना है तथा देश को शुचिता के रास्ते पर डालना है तो सतर्कता एवं जागरूकता को जीवन का अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। जीवन में शुचिता तथा ईमानदारी एवं निस्पृहता को सर्वोपरि स्थान देना पड़ेगा तब कहीं जाकर सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह जैसे औपचारिक अभियान यथार्थ के धरातल पर उतर पाएंगे।

दृढ़ संकल्प डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

संकल्प शक्ति का अर्थ है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय! संकल्प शक्ति से व्यक्ति की कार्यक्षमता और आत्म-प्रेरणा में वृद्धि होती है, जो उसे सफलता की ओर अग्रसर करती है। जी हां, जीवन के अवसाद के घेरे में से बाहर निकलने के लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। विषाद से ग्रस्त अर्जुन को उपदेश

देते समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन की संकल्प शक्ति को जाग्रत करने के लिए कहा था-'हे अर्जुन! बुद्धि को एक जगह स्थिर करो, उसे एक विषय में दृढ़ करो क्योंकि अस्थिर विचार वाले नासमझ पुरुषों की फैली हुई बुद्धि किसी भी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंच पाती।' जीवन के मार्ग में हर क्षण कठिनाइयों का प्रतिकार करने की अदम्य शक्ति आवश्यक है, विशेषकर इस मार्ग में मनुष्य के मन में अटल और दृढ़ निश्चय होना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि यदि मनुष्य के मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। इस संबंध में लोग पूछ सकते हैं, 'दृढ़ संकल्प के क्या लाभ हैं, और इसके बिना क्या हानियां हैं?' इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महंतस्वामी महाराज कहते हैं-'जीवन में संकल्प की दृढ़ता उस व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य तत्व है, जो साधना मार्ग या किसी भी पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। हमारा अनुभव है कि जो व्यक्ति एक ही क्षेत्र पर मन केंद्रित करता है, तो उसकी सफलता निर्विवाद होती है। साथ ही, यदि दृढ़ निश्चय न हो तो वह अनेक प्रकार के संकल्पों के साथ सांसारिक पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत सारे छेद वाली बाल्टी की तरह, उसमें पानी कभी नहीं भरेगा।' इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं-यदि व्यक्ति एक ही क्षेत्र पर दृढ़ निश्चय करता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश फैला हुआ होता है और उसल कांच के द्वारा उस फैले हुए प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर अग्नि प्रकट कर सकते हैं अन्यथा चिलचिलाती गर्मी में भी वह पदार्थ नहीं जल सकता। इसलिए मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले उसे एक जगह केंद्रित करना होता है। इसके लिए ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और आत्म-विश्वास को मजबूत करना आवश्यक होता है।

रीडर्स मेल

लंबे समय तक टीसेगी यह हार

खेल में जीत-हार होती रहती है लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने हमें हमारे घर पर ही धोया है, वर्षों याद रहेगा। तीन मैचों की शृंखला शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी टीम भारत को भारत में ही इस तरह पटखनी देगी। एक समय था जब भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी का माहिर माना जाता था पर अब उनमें वह काबिलियत नहीं रही और आम से दिखने वाले विदेशी गेंदबाजों को हम खतरनाक बना देते हैं। पूरी शृंखला में एक भी बार नहीं हुआ कि जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम पर हावी दिखी हो। हम तीन मैचों की 6 पारियों में एक बार भी 100 ओवर नहीं खेल पाए। न ही 300 रनों का आंकड़ा छू पाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बुरी फॉर्म के बाद इन दिग्गज बल्लेबाजों को अपने टेस्ट मैचों के भविष्य पर सोचने की जरूरत है। क्रिकेट पर टिके रहने की कला, जो द्रविड़, पुजारा, लक्ष्मण सरीखे बल्लेबाजों में थी, उनमें बेहद कम दिखाई दी। यह कमी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी टीस देगी।

बाल गोविंद, नोएडा

साइबर अपराध पर अंकुश जरूरी

गलत राह पर चलने का अंजाम बुरा होता है, सब जानते हैं लेकिन कुछ लोग अंजाम की फिक्र किए बिना गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं साइबर क्राइम वाले लोग। पैसे की लालच और शॉर्टकॉट के चक्कर में कुछ लोग इसमें ऐसे जकड़ते चले जा रहे हैं कि उन्हें लगता भी नहीं कि वे जुर्म कर रहे हैं। जिनका पैसा चुरा रहे हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, कोई बेटी की विवाह के लिए पैसे जमा करता है, तो कोई इलाज के लिए, तो कोई पढ़ाई के लिए। यह बात वे तनिक भी नहीं सोचते। बिना मेहनत और कम समय में अत्यधिक पैसा कमाने के फेर में वे पैसे की कीमत नहीं समझते और नशा एवं ने जाने क्या-क्या शौक पाल लेते हैं। प्रशासन और बैंकों द्वारा लोगों को जागरूक करने के बाद भी आये दिन अखबारों में साइबर ठगी के मामले देखने को मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग सका है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

खड़गे की नसीहत

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं को खुले मंच से नसीहत देते हुए कहा है कि वादा वही किया जाए जो पूरा किया जा सके। मेरा मानना है कि खड़गे का बयान राष्ट्रीय हित में है। राजनीतिक दलों को रेवड़ी संस्कृति खत्म करनी चाहिए। वेशक, भाजपा ने इस बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन यह बयान हकीकत से परे नहीं है। राज्य सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी के कारण आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। राज्य के ईंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनावश्यक मुफ्त की योजनाओं पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात हुई थी लेकिन आज तक नहीं हटाए जा सके हैं।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, गौरा-दरियापुर, पुलिस लेबेल-सादपुर, पानसुरा, पटना से मुद्रित तथा पटुर्वा तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
[संयुक्त संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *]
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6471
आर.एन.आई. नं. बीआरबीएबी/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 225

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल

डॉनल्ड ट्रंप चार साल के अंतराल के बाद दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। इस जीत ने सर्वेक्षणों को धता बता दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव के पहले की आशंकाओं को रेखांकित किया है। यह मुकाबला किसी भी लिहाज से करीबी नहीं था। ट्रंप न केवल रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले राज्यों में जीते बल्कि उन्होंने स्विंग स्टेट्स (ये राज्य जिनका रुझान स्पष्ट नहीं) में भी जीत हासिल की। 2016 के उलट ट्रंप ने पॉपुलर वोट में भी जीत हासिल की। 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा चुनाव जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रिपब्लिकन ने पॉपुलर वोट में जीत हासिल की हो। कमला हैरिस ने चुनाव के 107 दिन पहले अपना प्रचार अभियान शुरू किया था जो विश्व युद्ध के बाद के दौर में किसी प्रतिभागी का सबसे छोटा चुनाव अभियान था लेकिन उन्होंने जो गति हासिल की थी, उसे देखते हुए भी ट्रंप की जीत उल्लेखनीय है। हैरिस ने ट्रंप से अधिक धन जुटाया और खर्च किया तथा पूर्व राष्ट्रपतियों और ट्रंप के पहले प्रशासन के दिग्गजों से लेकर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री तथा टेलर स्विफ्ट एवं ओपरा विनफ्रे जैसे सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली लोग उनका समर्थन कर रहे थे। उनकी कमजोरी इस बात में निहित है कि उन्होंने खुद को बाइडनॉमिक्स से जोड़ा। सर्वेक्षणों ने लगातार बताया कि बाइडन की आर्थिक नीतियां न केवल अलोकप्रिय रहीं बल्कि उनका एजेंडा भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं था और गर्भपात के अधिकारों तथा नए परिवारों के लिए कर राहत के सिवा उसमें कुछ खास नहीं था। ट्रंप की अलोकप्रियता को लेकर उनका आत्मविश्वास भारी पड़ गया और वह इतनी आश्वस्त हो गईं कि उनके प्रचार अभियान की आरंभिक ऊर्जा बाद में नजर नहीं आई।

इसके विपरीत उनके प्रतिद्वंद्वी ने अपने चिरपरिचित एजेंडे को नहीं छोड़ा: सख्त आव्रजन नियंत्रण, अमीरों तथा बड़े कारोबारी घरानों को कर राहत, दूसरे देशों के साथ विद्वेष, लैंगिक भेदभाव और संरक्षणवाद। हत्या के प्रयास के बाद उन्होंने जो अनुकरणीय साहस दिखाया उससे भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। सीनेट पर कब्जे के बाद कांग्रेस में रिपब्लिकन की संभावित पूर्ण विजय के बाद उन्हें पहले दो वर्षों में ही अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर मिल जाएगा।

अमेरिकी मतदाताओं को अपने चुनाव का परिणाम मिलेगा लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के अनुभव शेष विश्व को खुश होने की वजह नहीं देते। आर्थिक मोर्चे पर बाइडन ट्रंप की टैरिफ वाली नीतियों के आसपास ही दिखे। परंतु ट्रंप अपने चुनावी वादे को पूरा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वह आक्रामक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देंगे तथा चीन की वस्तुओं पर 60 फीसदी तथा अन्य देशों पर 10 फीसदी शुल्क लगाएंगे। करों में कटौती का भी वादा किया गया है और इससे बजट घाटा बढ़ सकता है। इससे मुद्रास्फीति का दबाव बनेगा और मांग तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर होगा। विश्व अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते सालों में मजबूत हुए हैं। परंतु ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का तात्कालिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा इस पर नजर रखनी होगी। उच्च टैरिफ निर्यात को प्रभावित कर सकता है, खासतौर पर फार्मा उद्योग के लिए। इसके अलावा आईटी उद्योग भी एच1बी वीजा नीतियों को सख्त बनाए जाने से मुश्किलों का सामना करेगा। चीन पर संभावित उच्च शुल्क भारत के लिए जरूर अवसर हो सकता है। देखना यह होगा कि भारत नए हालात से कैसे निपटता है।

भूराजनीति के लिए भी ट्रंप का दूसरा कार्यकाल सकारात्मक नहीं नजर आता। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास के बीच लड़ाई चल रही है और पुतिन के प्रति ट्रंप का पक्षपात और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को लेकर उनकी अवज्ञापूर्ण भूमिका यूक्रेन के लिए बुरी खबर हो सकती है जो हथियारों के लिए नाटो पर निर्भर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते इस बात से पता चलते हैं कि अमेरिका ने 2017 में यरूशलम को इराजयल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। यह फिलिस्तीन के लिए अच्छी खबर नहीं। जलवायु परिवर्तन के एजेंडे की बात करें तो ट्रंप का पेरिस समझौते से हटना और पर्यावरण नियंत्रण समाप्त करने की बात कहना भविष्य के बारे में बताता है। लब्बोलुआब यह कि आर्थिक मंदी, संघर्षों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में ट्रंप की मजबूत जीत अनिश्चितता को और बढ़ाने वाली है।

विनय सिन्हा

भारत का ऊर्जा भविष्य और छोटे परमाणु संयंत्र

देश की ऊर्जा सुरक्षा के नजरिये से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर आदर्श हैं परंतु सही नीतियों के जरिये उन्हें समर्थन मिलना भी आवश्यक है। बता रहे हैं लवीश भंडारी

स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर या एसएमआर में भारत की ऊर्जा की तस्वीर बदल देने की क्षमता है। लेकिन अभी की स्थिति में भारत में एसएमआर से बिजली बनाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करने से पहले काफी कुछ किया जाना है। मगर यह अहम क्यों है? क्योंकि आगे चलकर भारत को हर आठ से 10 वर्ष में अपना बिजली उत्पादन दोगुना करना होगा। पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती तो होती है मगर उसका भंडारण सस्ता नहीं होता। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा मौसम पर निर्भर रहती है और रोजाना इसमें बदलाव होता रहता है। ऐसे में भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसके पास दूसरे स्रोतों में विविधता लाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है।

इसमें दो राय नहीं है कि विविधता लाने से जोखिम कम होता है और बिजली की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव भी कम होता है। लेकिन यह काम चतुराई से किया जाए तो बिजली उत्पादन की लागत भी कम हो सकती है। अन्य ऊर्जा स्रोतों में जियोथर्मल यानी भूतापीय और टाइडल अर्थात ज्वार से ऊर्जा बनाना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। जैव ईंधन बहुत महंगे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जरूरी लगता है। इससे उत्पादन स्थिर होता है और चौबीसों घंटे रहता है, जिस कारण यह और भी आकर्षक विकल्प बन जाता है।

किंतु बड़े परमाणु बिजली संयंत्रों के साथ दिक्कत यह है कि इनके निर्माण में बहुत समय लगता है। ये करीब एक दशक में तैयार होते हैं और इनके लिए बहुत जमीन की जरूरत होती है। इनका निर्माण शुरू होने के साथ ही कई एहतियात बरतने होते हैं। अगर 300 मेगावॉट से कम क्षमता वाली परमाणु परियोजनाओं की बात करें तो तकनीकी बदलाव और नियमों को दुरुस्त बनाने से ये व्यावहारिक विकल्प बन गई हैं।

कम लागत और छोटे आकार के कारण 300 मेगावॉट से कम की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की तादाद बढ़ी है। इससे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपूर्तिकर्ता भी नई जुगत भिड़ाने के लिए मजबूर हुए हैं। वे इन्हें मॉड्यूल यानी हिस्सों में तैयार करते हैं, एक जगह बनाते हैं और वहां से परियोजना स्थल पर ले आते हैं। ऐसा करने पर लागत और भी घट सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि इन संयंत्रों को एक दशक के बजाय अब तीन-चार साल में रही लगाया जा सकता है। तकनीकी नवाचार के कारण पहले से कम जमीन की जरूरत पड़ती है और 10 से 20 एकड़ में संयंत्र लग जाता है।

सुरक्षा के दो खास इंतजाम इन्हें पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। इनमें कोई गड़बड़ होने पर बाहरी हस्तक्षेप के बिना आंतरिक स्तर पर ही सुरक्षा उपाय समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कारण इन्हें बंद पड़े ताप बिजली संयंत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है और वहां पहले से मौजूद बिजली वितरण व्यवस्था तथा दूसरे बुनियादी ढांचे का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में तीन प्रमुख लाभ हैं: कम जगह की जरूरत, जल्दी पूरा होना और अधिक सुरक्षा। इन तीनों के कारण लागत भी कम हो जाती है। ये फायदे देखकर आप सोच रहे होंगे कि भारत को एसएमआर के जरिये परमाणु बिजली गतिविधियों को रफ्तार देनी चाहिए। मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

भारत मोटे तौर पर दो राहें चुन सकता है: पहली, खुद एसएमआर तैयार करना और दूसरी, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते करना। पहले देसी विकल्प पर विचार करते हैं। भारत लंबे समय से देसी क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हाल में 700 मेगावॉट क्षमता पर जोर है मगर 220 मेगावॉट के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) में भारत को गहरा अनुभव है। अगर भारत 100 मेगावॉट क्षमता से कम के व्यवहार्य विकल्प तैयार कर पाया तो उसके कई दूसरे औद्योगिक इस्तेमाल भी संभव हो जाएंगे। इससे हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत के मौजूदा परमाणु प्रतिष्ठान समय पर उत्पादन कर सकेंगे या नहीं। अतीत से संकेत लें तो इस क्षेत्र में अंतहीन विलंब होते हैं और एक दशक और इंतजार करना बहुत भारी पड़ेगा। 700 मेगावॉट के रिएक्टर को ही ले लीजिए। उसकी 10 अतिरिक्त इकाइयों के लिए 2017 में योजना बनाई गई थी और पांच साल के भीतर उन्हें स्थापित कर दिया जाना था। मगर ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि भारत के परमाणु प्रतिष्ठान सुरक्षा और परिचालन की कसौटी पर बहुत कामयाब रहे हैं मगर समय का पाबंद होने के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतीत में नवाचार और वृद्धि सीमित रहने का ठीकरा बाहरी प्रतिबंधों पर फोड़ा जा सकता था मगर हाल के दिनों में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में 220 मेगावॉट से कम क्षमता के संयंत्रों में नवाचार की गति बढ़ाने के लिए उचित वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधन देने होंगे।

अब दूसरे रास्ते पर विचार करते हैं यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध एसएमआर तकनीक को अपनाने की। कोरिया, अमेरिका, रूस और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत में इस अवसर से जुड़ना चाहती हैं। भारत की कई निजी और सरकारी कंपनियों की भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है। इनमें स्टील संयंत्र, डेटा सेंटर, क्लीन हाइड्रोजन उत्पादक और बिजली उत्पादक शामिल हैं। किंतु 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम कहता है कि इन संयंत्रों का संचालन भारतीय न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ही कर सकता है। इसमें बदलाव करना होगा तथा अन्य नियामकीय तथा अन्य संस्थाओं में थोड़े परिवर्तन करते हुए उनके दावे की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम 2010 में छोटे परमाणु संयंत्रों की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने होंगे। अभी यह कानून परियोजना चलाने वाले पर 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी लगा देता है। मगर एसएमआर आकार में छोटे होते हैं, इसलिए राशि भी उसी हिसाब से कम करनी होगी। सीएलएनडी के साथ यह दिक्कत भी है कि आपूर्ति करने वालों की असीमित देनदारी का खतरा हो जाता है। परमाणु उपकरण प्रदान करने वालों के लिए लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। तीसरी बात, आपराधिक यानी फौजदारी जवाबदेही से जुड़ी अस्पष्टता भी दूर करनी होगी।

देश का मौजूदा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन बना था और इसलिए नियामकीय तथा निगरानी प्रणाली में कई बदलाव करने होंगे ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसके लिए परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड की भूमिका बढ़ानी होगी और उसे निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर नियामकीय अधिकार देना होगा। साथ ही उसे सांगठनिक रूप से भी मजबूत करना होगा। कई सुरक्षा उपायों को भी संस्थागत स्वरूप देना होगा। इसके लिए गहन निगरानी, नियामकीय और प्रवर्तन क्षमताएं तैयार करनी होंगी, खास तौर पर रेडियोधर्मी विकिरण वाले कचरे के निपटान तथा संयंत्रों को बंद करने के मामले में।

आखिर में एसएमआर बड़ा नवाचार है और भारत के लिए उपयुक्त भी है बशर्ते सही नीतिगत, सांगठनिक, नियामकीय और निगरानी व्यवस्था लागू हो तथा वैश्विक तकनीक के साथ देसी नवाचार के लिए भी खुला नजरिया हो। देसी नवाचार हो या अंतरराष्ट्रीय तकनीक लाना, दोनों तरीके कारगर हैं और खुशकिस्मती से ये एक-दूसरे से अलग भी नहीं हैं।

(लेखक सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस के प्रमुख हैं)

बिक्री के आंकड़े उपभोक्ता मांग का आईना नहीं

यह कंपनियों के तिमाही नतीजे आने का दौर है और कंपनियों के मुनाफे या घाटे के आंकड़ों के साथ ही शेयर बाजार के जानकार, कारोबारी खबरें देने वाला मीडिया तथा कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) बताने लगते हैं कि उपभोक्ता मांग कैसी है और लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं। अक्सर ये अनुमान विश्लेषकों के पसंदीदा क्षेत्रों जैसे एफएमसीजी, कार या स्मार्टफोन में बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों का प्रदर्शन देखकर लगाए जाते हैं। लेकिन अच्छा तब होता, जब ये सारी बातें यह समझने के बाद कही जातीं कि परिवारों में रोजगार की स्थिति क्या है, आय कितनी है, क्या धारणाएं हैं और किन चीजों पर खर्च किया जा रहा है।

कंपनियों के नतीजों को समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि उपभोक्ताओं की मांग पर कौन से कारक असर डाल रहे हैं। इससे हमें सही जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं करने पर अलग-अलग दिशाओं की ओर संकेत कर रहे आंकड़े भ्रम को और बढ़ा देते हैं। कंपनियों की बिक्री पर इस बात का असर भी पड़ता है कि वे क्या चुनती हैं मसलन किस क्षेत्र में दांव लगाया जाएगा, होड़ किस तरह की जाएगी और योजनाओं को किस तरह अमल में लाया जाएगा। इसलिए कंपनियों की बिक्री को केवल उपभोक्ताओं की मांग का आईना नहीं माना जा सकता। पिछली कुछ तिमाहियों में प्रमुख रुझान यह था कि उपभोक्ता प्रीमियम उत्पादों की ज्यादा मांग कर रहे हैं। इस तिमाही में ग्रामीण मांग का पटरी पर लौटना और शहरी मांग में नरमी रहना नया रुझान है।

प्रीमियम होने के मायने

प्रीमियम होना यानी महंगे और बेहतर उत्पादों की बिक्री बढ़ना कई तरह से होता है इससे हमें खरीदारी के मामले में उपभोक्ताओं की पसंद के बारे में काफी अंदाजा मिल जाता है। कई बार कंपनियां अधिक आय वाले ग्राहकों पर ध्यान देने की नीति बनाती हैं। ये ग्राहक ज्यादा महंगा और उम्दा सामान खरीदते हैं क्योंकि अब अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, जिसकी वजहें सभी को मालूम हैं। अगर कंपनियों की रणनीति काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर उपभोक्ता दिक्कतों में पड़े हैं या उनकी आय पहले की तरह नहीं बढ़ रही। मुमकिन है कि कंपनियों की प्रीमियम उत्पादों की रणनीति कारगर नहीं हो रही हो क्योंकि हर क्षेत्र में होड़ बढ़ती जा रही है। अक्सर किसी श्रेणी में प्रीमियम उत्पाद साफ तौर पर दूसरे उत्पादों के मुकाबले बहुत तेजी से बिक रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि अमीर उपभोक्ताओं की आमदनी फिर बढ़ने लगी है। हो सकता है कि अमीर लोग दूसरों से ज्यादा खरीदारी कर रहे हों या यह भी हो सकता है कि उपभोक्ताओं की नजर में वह श्रेणी वाकई प्रीमियम बन रही हो। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से प्रीमियम श्रेणी की अगुआ कंपनी की बिक्री भी बढ़े। हाल ही में एक खबर थी कि त्योहारी दिनों की शुरुआत में नए स्मार्टफोन की मांग 3-4 प्रतिशत कम हो गई। मगर उपभोक्ताओं का तेजी से बढ़ता एक वर्ग अपने मौजूदा फोन को छोड़कर महंगा और बेहतर फोन खरीद रहा है। यह बात अलग है कि नया फोन खरीदने के बजाय वह रीफर्बिश्ड (ग्राहक द्वारा लौटाया गया नया फोन या मामूली खामी सही होने के बाद आया फोन) या सेकंड हैंड फोन ले रहा है। उपभोक्ताओं में यह चलन बना हुआ है। अब वे ऑनलाइन पढ़ाई करने, काम करने या मनोरंजन के लिए बेहतर डिवाइस तलाश रहे हैं। इनके जरिये वे अपना समय भी बचाना चाहते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कमाई बढ़ाने या परिवार के साथ अधिक समय बिताने में किया जा सके। इसी तरह बाजार में गारंटी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली सेकंड हैंड कार मिलने लगें तो नई और महंगी कारों की बिक्री कम हो सकती है।

रमा बीजापुरकर

ग्रामीण क्षेत्र में सुधार

पिछली कुछ तिमाहियों के बरअक्स इस तिमाही में कहा जा रहा है कि गांवों में बिक्री तेजी से बढ़ी है जबकि शहरों में एफएमसीजी की बिक्री में थोड़ी कमी आई है। लेकिन इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि अच्छी बारिश, बुनियादी सुविधाओं में बढ़त और सरकारी खर्च के कारण अब गांवों में मांग बढ़ती रहेगी। बड़ी एफएमसीजी कंपनियां थोक बिक्रेताओं को लांघते हुए छोटे गांवों में अपना माल सीधे पहुंचाकर कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशती रही हैं। पहले छोटे गांवों में सीधे माल पहुंचाना मुनाफे का सौदा नहीं था मगर अब गांवों में लोग कम रहते हैं, अच्छी सड़कें और लॉजिस्टिक्स सेवा कम हैं डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से लागत कम हो रही है। इसलिए कारोबार के नजरिये से यह सही लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी शायद उतनी नहीं बढ़ी है लेकिन गांवों में बिक्री बढ़ सकती है क्योंकि लोग सामान खरीदने लगेंगे और बड़ी कंपनियां छोटी और क्षेत्रीय कंपनियों के बाजार में सेंध लगा देंगी।

क्या इस बात के ठोस सबूत हैं कि गांवों में लोगों की आमदनी बढ़ी है? कुछ आंकड़ों के मुताबिक खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन खेती से होने वाली आमदनी नहीं बढ़ रही है जिससे यह पता चलता है कि गांवों में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे आंकड़े बताते हैं कि मिश्रित खेती के कारण लोगों की आमदनी बढ़ रही है। सीएमआईई के आंकड़ों से आमदनी में कमी का रुझान पता चलता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले निर्माण क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं। नाबार्ड का सितंबर 2024 का ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं धारणा सर्वेक्षण बताता है कि पिछले एक साल में 80 प्रतिशत घरों में खर्च बढ़ा है लेकिन सिर्फ 37.6 फीसदी घरों की आमदनी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कर्ज में इजाफे और घरेलू बचत में कमी का नतीजा हो सकता है। इस पर अभी चर्चा जारी है और कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

शहरी मांग का जायजा

शहरी इलाकों में मध्यम स्तर की बाजार श्रेणी में उत्पादों की बिक्री घटने के पीछे उपभोक्ताओं से जुड़े कई कारण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण मूलतः शहरी आबादी का सर्वेक्षण होता है। उसमें बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में लगभग हर मोर्चे पर उपभोक्ताओं की धारणा और विश्वास में कमी देखी गई है। आमदनी के हिसाब से तीसरे और चौथे समूह के सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवारों के पास भी अतिरिक्त धन बहुत कम है। जब महंगाई बढ़ती है तब पैसा भी ज्यादा खुला होता है, इसलिए वे कम खरीदारी करते हैं। कुछ कंपनियों के यह बुरी खबर है लेकिन कुछ के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि लोग इसकी वजह से सस्ता सामान खरीदने लगते हैं। इन कंपनियों पर शायद शेयर बाजार के जानकार ध्यान नहीं दिए हैं। भारतीय उपभोक्ता बाजार अब पहले से ज्यादा जटिल हो गया है। पुराने तरीके और सोच अब कारगर साबित नहीं होंगे। हमें बाजार को गहराई से समझने की जरूरत है और कारण तथा प्रभाव के बीच के संबंध को भी समझना होगा।

आपका पक्ष

जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों, कम उत्सर्जन वाले उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही वनीकरण में वृद्धि हो सके। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे साल दुनिया को परेशान करता रहा है। जलवायु परिवर्तन सर्वविदित है। वर्तमान में यह वैश्विक समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता बन गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान एक डिग्री बढ़ गया है। यह संख्या भले ही छोटी लगती हो, परंतु मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। देखा जाए तो हम सभी एक ट्रिपल ग्रह संकट के बीच में जीवन व्यतीत कर रहे हैं:

हिमालय पर स्नो कवर यानी बर्फ से ढका क्षेत्र इसी साल फरवरी की तुलना में 32.2 प्रतिशत बचा है

जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षरण, प्रदूषण और अपशिष्ट। ये संकट पूरी तरह से दशकों के अथक और लगातार उपभोग और उत्पादन के कारण उत्पन्न हुए हैं। ऐसे समय में जब हमारी पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है तब धरती के तापमान को संतुलित रखा जाना सभी का संयुक्त दायित्व है। अगर सभी देश जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए अपने मौजूदा वादों को पूरा करें तो विश्व में तापमान वृद्धि 1.8 डिग्री तक सीमित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह संकट सिर्फ अन्य देशों का है भारत में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हिमालय पर स्नो कवर यानी बर्फ से ढका क्षेत्र इसी साल फरवरी की तुलना में 32.2 प्रतिशत बचा है। अतः हमें प्रगति और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के प्रयास भूमि पर रहकर ही करना होगा।

सीमा श्रीवास्तव, भोपाल

हादसों से लें सबक

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ओवरलोड बस के गहरी खाई में गिरने से लगभग 35 से अधिक लोगों की जान चली गई और कुछ गंभीर घायल हो गए। यह अत्यंत दुखद घटना है। इससे पहले भी देश के कुछ राज्यों में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन ओवरलोड बसों के दुर्घटना के मामलों से सबक नहीं लिया गया। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित होती है। बसों में ओवरलोड सवारियों की निगरानी तंत्र की विफलता के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। पुलिस को भी नाकों पर बसों में ओवरलोड की जांच करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को भी ओवरलोड बस दिखने पर उसे रोक देना चाहिए। सरकार को बस अड्डों तथा नाकों पर बसों की ओवर-लोडिंग की सख्त निगरानी के आदेश देने चाहिए। ओवरलोड और ओवरस्पीड हमेशा ही दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों में कई हादसे हो चुके हैं जिससे कई लोगों की जान चली गई है। कुछ समय पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में 2022 में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा जारी किया था जो बड़ी चिंता का विषय है। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

बिहार कोकिला के नाम से प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार गुरुवार को पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका मंगलवार रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था। वह 72 साल की थीं। गायिका का पार्थिव शरीर बुधवार को दिल्ली से पटना लाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे।

दैनिक जागरण
पुरुषार्थ और पराक्रम ही विजय का मंत्र है

फिर आ गए ट्रंप

अंततः अमेरिकी जनता ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाना पसंद किया। ट्रंप ने आसानी से जीत हासिल कर एक नया इतिहास बनाया। वह लंबे समय बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने, जिन्होंने एक बार चुनाव हारने के बाद जीत हासिल की। इतिहास रचने का अवसर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास भी था। वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती थीं, लेकिन हिलेरी क्लिंटन की तरह वह भी नाकाम रहीं। हिलेरी को भी ट्रंप ने हराया था और कमला हैरिस को भी। यह साफ है कि राष्ट्रपति जो बाइडन की विरासत उन पर भारी पड़ी। यदि बाइडन कमजोर राष्ट्रपति साबित नहीं हुए होते और उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के साथ वैश्विक समस्याओं और विशेष रूप से यूक्रेन एवं गाजा युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई होती तो शायद कमला हैरिस की राह आसान होती। कमला हैरिस को इसका भी नुकसान उठाना पड़ा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने शरणार्थियों और अवैध रूप से आए लोगों के प्रति उदार रवैया अपना रखा था। भारत एवं अश्वेतों मूल की महिला होने के नाते वह महिलाओं और विदेशी मूल के नागरिकों को उतना आकर्षित नहीं कर पाईं, जितना मानकर चला जा रहा था। यह भी उनकी पराजय का कारण बना। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि वह अमेरिकी जनता की उस तरह नब्ज नहीं पकड़ सकीं, जैसी ट्रंप ने पकड़ी। ट्रंप एक मजबूत नेता की अपनी छवि उभारने, अमेरिका के साथ दुनिया की समस्याओं के समाधान में सक्षम साबित होने का संदेश देने के साथ यह भरोसा दिलाने में भी समर्थ रहे कि वह महंगाई से जूझती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसमें उनकी व्यापारी वाली छवि भी सहायक बनी।

चूंकि रिपब्लिकन पार्टी का अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत होगा, इसलिए यह तय है कि ट्रंप अपने मनमाफिक खुलकर काम करेंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अप्रत्याशित फैसले करने वाले बड़बोले नेता हैं। वह किस मसले पर कब क्या कह और कर दें, इसका ठिकाना नहीं। वह जलवायु परिवर्तन को समस्या नहीं मानते और अमेरिका के आर्थिक हितों के आगे वैश्विक हितों की परवाह नहीं करते। वैसे उनके पहले कार्यकाल में विश्व अपेक्षाकृत स्थिर था और इसमें उनका भी योगदान था। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारतीय हितों के लिए अच्छा माना जा रहा है और इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पिछले कार्यकाल में वह भारत के मित्र के रूप में उभरे थे, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वह भारत की उच्च आयात शुल्क दर की शिकायत करते रहते हैं। उन्हें यह भी रास नहीं आता कि दोनों देशों के बीच व्यापार का पलड़ा भारत के पक्ष में झुका है। भारत को व्यापार नीति के साथ एच-वन बी वीजा पर उनके रवैये से भी सतर्क रहना होगा।

पशुओं की चिकित्सा

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाए गए, लेकिन पशुओं की चिकित्सा पर अब तक उतना ध्यान नहीं दिया जा सका, जितना दिया जाना चाहिए था। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो जानवरों के उपचार का अत्यंत ही बुरा हाल है। अब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। पशुपालन और परापशुचिकित्सा (पैरा वेटनरी) के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नीति बड़ी पहल है और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। पशुओं में कई तरह के रोग पाए जाते हैं जिनमें कुछ संक्रामक भी होते हैं और इससे मनुष्यों को भी खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसके अलावा, राज्य की सड़कों पर घूम रहे निराश्रित पशु भी बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं और उपचार की व्यवस्था न होने से उनकी असमय मौत हो जाती है। पशु चाहे पालतू हों या फिर बेसहारा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना मानव समाज का धर्म है। उनके हर रोग के उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी से जानवरों को होने वाले गलाघोंटू, थनैला, प्लीहा, मुंहपका आदि रोगों का इलाज भी नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों में चिकित्सकों और उनके सहायकों की भी भारी कमी है। राज्य में 8,193 पशु चिकित्सक हैं और उन पर ही जानवरों के उपचार की जिम्मेदारी है। नई नीति में निजी क्षेत्र भी पशुपालन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित कर सकेंगे, जिससे युवकों को रोजगार के अवसर हासिल होंगे। हालांकि इसके साथ राज्य सरकार को पशु अस्पतालों में संसाधन भी जुटाने होंगे। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि अस्पतालों में टीकाकरण, घावों की पट्टी, प्राथमिक उपचार की सुविधा अवश्य मिले।

डोनाल्ड ट्रंप ने रचा नया इतिहास

हर्ष वी. पंत

ट्रंप की प्रचंड विजय शेष विश्व के साथ अमेरिका की सहभागिता में व्यापक बदलाव के सूत्रपात का भी संकेत है

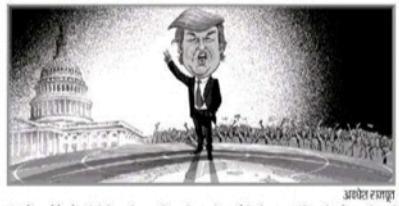

अवधेश राजपूत

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार ऐतिहासिक जीत बहुत कुछ कहती है। यह दर्शाती है कि चुनाव में जिस कटि की टक्कर का अनुमान लगाया गया, वैसा असमंजस में कुछ नहीं था। ट्रंप ने 2020 के अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया जबकि डेमोक्रेट उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पिछले चुनाव में बाइडन के प्रदर्शन की बराबरी भी नहीं कर पाईं। ट्रंप ने जबरदस्त राजनीतिक वापसी करते हुए दूसरे कार्यकाल की राह सुनिश्चित की। ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे तभी खुलने लग गए थे, जब जार्जिया के उस किले को उन्होंने फिर से जीत लिया, जो 2020 में उन्होंने मामूली अंतर से गंवा दिया था। नार्थ कैरोलिना में उनकी जीत ने कमला हैरिस की हार को पटकथा लिख दी। पेंसिलवेनिया, एरिजोना, मिशिगन, विस्कान्सिन और नेवादा जैसे कड़े मुकाबले वाले राज्यों में भी हैरिस कुछ खास नहीं कर पाईं, जो उनकी जीत के लिहाज से बेहद अहम थे। अपनी 2016 की जीत के उलट इस बार ट्रंप पापुलर वोट्स के मामले में भी बाजी जीतने में सफल रहे। रिपब्लिकन पार्टी 1992 के बाद चुनाव में यह उपलब्धि दर्ज कर पाई है। ट्रंप ने विजयी भाषण में समर्थकों से कहा, 'अमेरिका ने एक अभूतपूर्व एवं दमदार जनादेश दिया है।'

चार साल पहले ट्रंप को वाशिंगटन से विदाई लेनी पड़ी थी। 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद वह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चार साल के अंतराल के बाद फिर से चुनकर आए हैं। इस लिहाज से भी उन्होंने इतिहास रचा है। तमाम कानूनी मुश्किलों में फंसे व अपने पहले कार्यकाल में दो बार महाभियोग का सामना करने और करीब 40 प्रतिशत की रेटिंग से कम पर राष्ट्रपति पद से विदा होने वाले ट्रंप की वापसी किसी भी सूरत में कम करके नहीं आंकी जा सकती। यह बड़ी उपलब्धि है।

अमेरिकी इतिहास में यह एक बेहद असाधारण चुनाव था, जिसमें एक प्रत्याशी यानी ट्रंप पर दो बार जानलेवा हमले और एक आपराधिक ट्रायल भी देखने को मिला, जबकि डेमोक्रेट खेमे ने अंतिम दौर में बाइडन की जगह कमला हैरिस को प्रत्याशी बनाया। चुनाव अभियान में किमार्ए एवं छीटाकशी का निम्नतम स्तर देखने को मिला और राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर दिखा। इस परिदृश्य में भी रिपब्लिकन पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रही। उसने न केवल राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स को मात दी, बल्कि अमेरिकी सीनेट पर नियंत्रण के साथ ही प्रतिनिधि सभा में भी उसका दबदबा बने रहने के आसार हैं। इसका अर्थ होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे में कोई विधायी अवरोध भी नहीं आएगा। ट्रंप की जीत बहुत व्यापक है और उनके सहारे दोनों सदनों में कई रिपब्लिकनों की नैया पार लगी है। उन्होंने अपने दम पर पार्टी की छवि और उसके सितारों को नए सिरे से गढ़ा है। इस चुनाव में दोनों खेमों का दांव इतना ऊंचा लगा था कि उन्होंने मतदाताओं को लामबंद करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आधुनिक अमेरिकी इतिहास में यह सर्वाधिक मतदान वाला चुनाव रहा। इन चुनावों ने कई वर्जनाओं को भी तोड़ा है। जैसे माना जा रहा था कि हैरिस को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिलेगा, लेकिन वास्तविक तस्वीर ऐसी नहीं दिखी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार अधिकांश महिलाएं उनके पक्ष में रहीं, लेकिन वह 2020 में बाइडन को मिले महिलाओं के 57 प्रतिशत मतों की बराबरी भी नहीं कर पाईं। यह भी आश्चर्यजनक रहा कि अश्वेत, लैटिन और एशियाई समूहों में एक तिहाई अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रंप के लिए वोट किया, जबकि श्वेत मतदाताओं के बीच उनके प्रति समर्थन में मामूली सी गिरावट आई। यह मतदाताओं की पारंपरिक पसंद में परिवर्तन के साथ ही अमेरिकी जनसांख्यिकी से जुड़ी नई वास्तविकताओं से परिचित कराता है। इसके चलते दशकों बाद पहली बार अमेरिकी राजनीति की रंगत बदली है और दोनों पार्टियों के समर्थन आधार में भी यह प्रत्यक्ष दिख रहा है। जहां रिपब्लिकन पार्टी शहरीकरण श्रम से संबंधित कामगारों और निम्न आय वाले मतदाताओं में पैठ बढ़ा रही है तो डेमोक्रेट्स शिक्षित युवाओं और उच्च आमदनी वाले वर्गों पर हद से ज्यादा निर्भर होती जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी अब वैसे नहीं दिखती, जैसे उसकी पहचान रही है। इस चुनाव ने यह भी दर्शाया कि डेमोक्रेट्स ने अधिकांश अमेरिकियों की आवाज उठाना बंद कर दिया है और अपना दायरा बढ़ाने की उनके पास कोई योजना नहीं। कुल मिलाकर, वह हालीवुड सेलेब्रिटीज की ऐसी पार्टी बनकर रह गई, जिसका जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा। दूसरी ओर, ट्रंप का अभियान बहुत सुनियोजित रहा और उन्होंने बाइडन-हैरिस प्रशासन की कमियों को रेखांकित कर उन्हें बखूबी भुनाया।

ट्रंप ने बढ़ती महंगाई, दक्षिणी सीमा पर विदेशियों की बढ़ती आवक और वैश्विक अस्थिरता को मुद्दा बनाया। हैरिस ने बाइडन की असफलताओं से खुद को दूर रखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो सकीं। आव्रजन, व्यापार, सांस्कृतिक मुद्दों एवं विदेश नीति पर भी हैरिस और ट्रंप के विचार विपरीत थे, जहां अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रंप के पक्ष में अपना फैसला सुनना पसंद किया। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने आर्थिक एवं सामरिक, दोनों मोर्चों पर विश्व के साथ अमेरिकी की सक्रियता के समीकरण नाटकीय रूप से बदल दिए थे। हालिया एग्जिट पोल में भी यह झलका कि यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई के साथ-साथ व्यापक वैश्विक अस्थिरता के दौर में केवल चार प्रतिशत अमेरिकी मतदाता ही विदेश नीति को लेकर चिंतित थे। वैश्विक ढांचे के दृष्टिकोण से अमेरिका के अंतर्मुखी होने के गहरे निहितार्थ हैं। चूंकि इस मामले में भारत की स्थिति कहीं बेहतर है तो इसकी भरी-पूरी संभावनाएं हैं कि अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन के साथ नई दिल्ली कहीं बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने में सक्षम होगी। अमेरिका के साथ प्रगाढ़ साझेदारी समकालीन भारतीय विदेश नीति के मूल में है। भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। कहीं व्यापक जनादेश के साथ 2024 में ट्रंप की विजय यही दर्शाती है कि 2016 में उनकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। साथ ही यह शेष विश्व के साथ अमेरिका की सहभागिता में व्यापक बदलाव के सूत्रपात का भी संकेत है। ट्रंप की जीत अमेरिका के साथ-साथ विश्व पर भी असर डालेगी।

(लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

लोक संस्कृति को स्वर देने वालीं गायिका

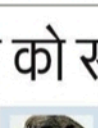

परिचय दास

शारदा सिन्हा का गायन मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक दायित्व को भी पूरा करता था

संस्कृति को सजोने वाली शारदा सिन्हा। एएनआइ

प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का गायन एक ऐसी सांस्कृतिक संपदा है, जिससे उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से की संस्कृति आत्मा अभिव्यक्त होती है। उनका गायन ग्रामीण भारत की मिट्टी की खुशबू से भरपूर था। उन्होंने अपने गायन के माध्यम से लोक संगीत की धरोहर को संरक्षित ही नहीं किया, बल्कि उसे देश-विदेश में स्थापित किया। उनका गायन विशिष्ट रूप से लोक संस्कृति का प्रतिबिंब था। उनके गीतों में जनजीवन की उन भावनाओं को देख जा सकता है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। उनके गीतों में प्रेम, विरह, सुख-दुख, त्योहार, जीवन के विविध रंग और ग्रामीण समाज की धड़कन महसूस की जा सकती है। उनके लोक गीत केवल संगीत के स्तर पर सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज की सामूहिक स्मृति और संस्कृति के वाहक बनते हैं। शारदा सिन्हा ने अपने गीतों में अपने सुरों से भावनाओं का ऐसा रंग भरा कि श्रोता अपने आपको उस संस्कृति के निकट पाते थे। उनका स्वर लोक गीतों के स्वरूप को संपूर्णता प्रदान करता था, जिसमें सिर्फ गायन नहीं, बल्कि उस संगीत के माध्यम से जीवन की कला और दर्शन भी उभर कर आता था।

त्योहारों के समय में विशेषकर छठ पर्व पर शारदा सिन्हा के गीत एक अलग ही महत्व रखते थे। उनके गीतों में छठ पर्व की आध्यात्मिकता, परिवार और समाज के प्रति समर्पण और आस्था की गहराई को महसूस किया जा सकता था। 'केलवा के पात पर' और 'पहिले पहल छठी मइया' जैसे गीतों में वह भक्ति भाव झलकता है, जो लोगों के दिलों को छूता है। उनके इन गीतों से त्योहारों का वातावरण जीवंत हो उठता है और श्रोताओं को एक तरह की संस्कृतिक एकता का अनुभव होता है। उनके गीत लोक जीवन के उन अनगिनत बिंबों को जीवंत करते हैं, जिनसे छठ जैसे पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान न रहकर सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन जाते हैं। शारदा सिन्हा का लोक गायन अन्य लोक गायकों से इस मायने में भिन्न था कि वह अपने गायन में पारंपरिक विधियों के साथ-साथ आधुनिक संगीत तत्वों को भी शामिल करती थीं। इसके बावजूद उनका संगीत अपनी मौलिकता नहीं खोता था। उनकी आवाज और गायन शैली में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, जो उन्हें लोक गायन की दुनिया में अद्वितीय बनाता था। शारदा सिन्हा ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर लोक संगीत को न केवल संजोया, बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया, जो युवा पीढ़ी को लोक संगीत के प्रति जागरूक और आकर्षित करता है। उनके गीतों में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय लोक संगीत को अद्वितीय स्वरूप में प्रस्तुत करता था।

शारदा सिन्हा की गायन शैली में जो खास बात देखने को मिलती थी, वह थी उनकी भाषा की सरलता और लोक शब्दों का सहज प्रयोग। उनके गीतों में मैथिली, भोजपुरी भाषा का प्रयोग इतनी खूबसूरती से होता था कि भाषा के प्रति प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता था। वह अपने गीतों के माध्यम से समाज के हर वर्ग से जुड़ जाती थीं, क्योंकि उनके गीतों में लोक जीवन के हर व्यक्ति की भावना को आवाज दी गई होती थी। वह शब्दों को इतने मार्मिक और सजीव रूप में प्रस्तुत करती थीं कि श्रोता उस संगीत में डूबकर खुद को उन भावनाओं के बीच महसूस करने लगते थे। उनके गायन में भाषा, संस्कृति और समाज के बीच का ऐसा जीवंत पुल बनता था, जो दिलों को जोड़ता था। उन्होंने अपने गायन में केवल प्रेम या भक्ति गीत ही नहीं गए, बल्कि सामाजिक समस्याओं पर भी अपने गायन के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए। उनके गीतों में एक सामाजिक जागरूकता की झलक भी मिलती थी, जो ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी करती है। चाहे वह सामाजिक बंधनों का मामला हो या महिलाओं की स्थिति का, उनके गीतों में इन मुद्दों का संवेदनशील चित्रण देखने को मिलता था। उनके द्वारा गए गए कई गीत महिलाओं के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी सामाजिक स्थितियों पर आधारित हैं। इन गीतों के माध्यम से वह समाज में एक नए सोच की आवश्यकता को भी उजागर करती थीं।

'बिहार कोकिला' कही जाने वालीं शारदा सिन्हा का गायन केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक संस्कृतिक और सामाजिक दायित्व को भी पूरा करता था। इसीलिए उनका जाना एक बड़ी क्षति है। उनकी गायकी में लोक धुनों का ऐसा प्रभाव दिखता है कि उनका हर गीत श्रोताओं को गहराई तक प्रभावित करता है। उनके गायन में जो मिठास और ऊर्जा है, वह सुनने वालों को उत्साहित करती है। लोक संगीत को उन्होंने जिस सजीवता और नवीनता के साथ प्रस्तुत किया, उससे वह भारतीय संगीत के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। उनके गीतों के माध्यम से उनका यह महत्वपूर्ण स्थान उनके जाने के बाद भी बना रहेगा। उनकी गायकी में शुद्धता और लोक गीतों की सादगी थी, जो लोक संगीत प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर है। उनका लोक गायन एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अमूल्य है। उन्होंने अपने गायन से बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ संपूर्ण भारतीय लोक संस्कृति को एक विशेष पहचान दी। उनके गीत समाज, संस्कृति और जनजीवन का एक संपूर्ण दर्पण भी हैं। उनके गायन से लोक संगीत को जो ऊंचाई प्राप्त हुई, वह लोक संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान का प्रमाण है। उनका संगीत समय के साथ और अधिक अमर होता जाएगा और वह भावी पीढ़ियों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। शारदा सिन्हा ने जिस तरह लोक संगीत को अपना स्वर दिया, वह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक अविस्मरणीय योगदान है।

(लेखक नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, नालंदा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविक सौंदर्य

सौंदर्य सदैव आकर्षण का एक आधार रहा है। सौंदर्य से आशय मात्र बाहरी आकर्षण से ही नहीं, अपितु यह आंतरिक गुणों एवं मानवीय संवेदनाओं का भी परिचायक है। सौंदर्य की परिभाषा व्यक्तियों, संस्कृतियों और समय के साथ बदलती रहती है। किसी के लिए सौंदर्य का अर्थ शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, जबकि किसी अन्य के लिए यह व्यक्तित्व, विचार, कला या किसी अन्य पहलू में निहित हो सकता है। प्लेटो ने कहा है, 'सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहराई है, जो सत्य की ओर ले जाती है।'

प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। पर्वत, नदियां, समुद्र और वन सभी अपनी विशेषता के साथ मन को मोह लेते हैं। इन प्राकृतिक दृश्यों की छवि मन में स्थायी छाप छोड़ती है। जब हम प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं तो हमें एक अनूठी शांति और संतोष का अनुभव होता है। सौंदर्य का एक और पहलू कला है। चित्र, संगीत, नृत्य और साहित्य आदि ने भी मानव जीवन में सौंदर्य का एक नया आयाम जोड़ा है। कला का सौंदर्य केवल देखने या सुनने में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी अनुभूति में भी है। इसमें हमारी भावनाओं को जगाने और विचारों को प्रेरित करने की क्षमता विद्यमान होती है।

भौतिकता से भरी जीवनशैली ने सौंदर्य के मानकों को प्रभावित किया है, जिससे वास्तविक सौंदर्य की पहचान करना कठिन हो गया है। हम बाहरी सौंदर्य के पीछे छिपे आंतरिक सौंदर्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। सौंदर्य एक अनुभव है, जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध करता है। सौंदर्य की खोज में हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर सकें। महात्मा गांधी ने कहा है, 'जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति हैं, वही सच्चे अर्थों में सुंदर है।'

नृपेंद्र अभिषेक नृप

जलवायु परिवर्तन के बीच छठ का महत्व

अमीत कुमार भानु

मानव जीवन और प्रकृति के बीच के संबंधों को दर्शाने वाला लोक आस्था का पर्व है छठ

ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से जूझ रही है, पुरातन परंपराओं पर गौर करना जरूरी हो गया है, जो पर्यावरण के साथ हमारे विशिष्ट संबंध का साक्षी रहा है। इस संदर्भ में उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक पर्व छठ पूजा, प्रकृति और मानव जीवन के मजबूत और अन्योन्याश्रय संबंध का उदाहरण बनकर सामने आता है। छठ पूजा भारतीय सभ्यता में गहरी जड़ें जमा चुकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के साथ ही पारंपरिक प्रथाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाने का एक सुसंगत माडल भी प्रदान करती है।

मानव केंद्रित पाश्चात्य दर्शन की परंपरा, प्रकृति में मौजूद हर चीज को मानव के उपभोग के लिए बनाई गई मानती है। इसके उलट भारतीय ज्ञान और चिंतन पर्यावरण को एक बहुत ही जीवंत प्रणाली के रूप में मानता रहा है। भारतीय दर्शन में पर्यावरण के साथ मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण संबंध को आवश्यक मान गया है। भारतीय समाज पौराणिक काल से ही उत्सवधर्मी रहा है। इसलिए त्योहारों और अनुष्ठानों में आमतौर पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश निहित होते हैं। छठ, प्रकृति पूजा, विशेष रूप से भगवान सूर्य को उपासना पूजा पर केंद्रित है। पूजा के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री, जैसे बांस की टोकरी, सूप, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, दूध, फल, चावल और गेहूं आदि सभी सीधे तौर पर प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग पर्यावरण को न के बराबर नुकसान पहुंचाते हुए उत्सवों के मनाने के तौर-तरीकों के लिए एक मानक स्थापित करता है।

आज भी छठ पूजा बाहरी आडंबर से दूर है। अध्यात्म के प्रति यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर्यावरण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर बल देते हुए मनुष्य को प्रकृति के साथ सौहार्द संबंध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार देता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूजा की पद्धति जनसामान्य के रिवाजों और कृषि आधारित ग्रामीण जीवन पर केंद्रित मालूम होता है।

सभ्यतागत लोकाचार में मजबूती से रथी-बसे छठ पूजा का महत्वपूर्ण पहलू इसकी सादगी व पवित्रता है। दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों के साथ, इस सदियों पुराने त्योहार ने वैश्विक पटल पर विविध संस्कृतियों और समुदायों के बीच अपनी पहचान बनाई है। छठ पूजा की अनूठी विशेषताओं जैसे स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, लोक परंपरा का संरक्षण, सामाजिक एकजुटता और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए सरकार को छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। लोक आस्था का यह पर्व हमें सतत विकास के पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

समय के साथ परिवर्तन आवश्यक

'वक्फ के नाम पर लूट की खुली छूट' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की नीति पर चिंता व्यक्त की है। वैसे तो भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद अस्तित्व में आ गया था, लेकिन स्वर्गीय सेम्युएल सरकार ने वोट के लालच में वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार देने का कार्य किया वह अब देश की जनता के लिए भारी मुसीबत का रूप ले चुका है। इन्हीं असीमित शक्तियों की बदौलत वक्फ बोर्ड अब श्मशान घाट से लेकर देश की बेशकीमती जमीनों पर अपना मालिकाना हक जता रहा है। लगभग 60 प्रतिशत दिल्ली तथा 43 प्रतिशत लखनऊ शहर को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा हुआ बताया जाने लगा है। वक्फ बोर्ड का यह दावा जितना आश्चर्यजनक है उतना ही देश के विपक्षी दलों का यह रवैया है, जो इस भयावहता को जानते-समझते हुए भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर अड़े हुए हैं। अब समय आ गया है वक्फ बोर्ड की इन असीमित शक्तियों पर लगाम लगाई जाए। यदि समय रहते देश न चेता तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए राजनीतिक दलों को जनहित में कोई सहमति बनानी चाहिए।

वेदप्रकाश पाण्डेय, अंबेडकर नगर, उप्र

वक्फ कानून में बदलाव जरूरी

कानूनविदों ने देश के विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए सटीक सवाल किया है कि यदि मौजूदा वक्फ कानून में कोई खामी नहीं, तो क्या विपक्ष को ऐसा ही कानून अन्य समुदायों के लिए भी मान्य होगा? वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून को जायज ठहराने के लिए सरकार द्वारा गठित जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने कई बार नोकझोंक भी की है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद 1995 में उसमें संशोधन हुआ। फिर 2013 में संशोधन से वक्फ बोर्ड के अधिकारों को और भी ताकत मिल गई। इससे बोर्ड किसी की संपत्ति को अपना बता सकता है और उसके निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही और भी अधिकारों को कम किए जाने पर जेपीसी की बैठक में विचार चल रहा है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

भारत के परिपेक्ष्य में 'ट्रंपकार्ड'

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड पूरी तरह चल गया। ट्रंप 2020 के मुकाबले इस बार प्रांरभ से ही पूरी सजगता के साथ चुनाव अभियान में जुट हुए थे। उनकी आर्थिक-औद्योगिक विकास, वैश्विक आतंकवाद, युद्ध व शांति सभी क्षेत्रों के लिए नीतियां पूर्णतया स्पष्ट व बेबाक रहीं। विगत दिनों बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा जबरदस्ती तख्तापलट व अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को ट्रंप ने सटीक समय पर मुखर हो उठाल समस्त हिंदुओं को अपने पाले में कर लिया। ट्रंप शुरू से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कायल रहे हैं। चाहे वह 2020 टैक्सस की विशाल रैली हो या मोदी द्वारा क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में विशाल जनमानस के साथ ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत हो। वर्तमान में इजरायल-फलस्तीन व रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर वैश्विक आतंकवाद, औद्योगिक व आर्थिक विकास को नए आयाम देना ट्रंप के लिए एक चुनौती रहेगी। अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन के प्रति ट्रंप का रुख हमेशा प्रतिकूल रहा है। इसका लाभ भी भारत को मिलेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का 'ट्रंप कार्ड' बखूबी चल ही गया, लेकिन अब विश्व शांति व विकास के नए आयाम बने ट्रंप से ऐसी आशा है।

जयप्रकाश अग्रवाल, सूरजमल विहार, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

34 बाघों की मौत हुई है पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। लगभग सप्ताह भर पहले बांधवगढ़ में जहरीला कोदो खाने से 10 हाथियों की मौत हो गई।

अमिय भूषण
अध्येता, भारतीय संस्कृति परंपरा

प्रयागराज महाकुंभ

राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका

प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। अगले वर्ष के आरंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का मुहूर्त है। इसके आरंभ को लेकर संतों के अखाड़ों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मेला क्षेत्र में इनके प्रवेश और शिविर हेतु भूमि पूजन की तिथियां भी निकट आ गई हैं। जूना अखाड़े के साधु-संन्यासी कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे-धीरे यहां और भी अखाड़ों के साधु-संत पहुंचना आरंभ करेंगे। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय जागरण में कुंभ की भूमिका इसकी महत्ता को और बढ़ा रही है

लगभग चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है प्रयागराज में अस्थायी कुंभ नगरी का निर्माण। फाइल

मकर संक्रांति से प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। यह पर्व मानव इतिहास के सर्वाधिक पुराने परंपराओं में से एक है। किसी बहती नदी और जीवंत संस्कृति से यह भी लगातार प्रवाहमान और जागृत है। इसके प्रमाण पुरातन वेद ग्रंथों में हैं। यही नहीं, यह भारतीय वांग्मय के ब्राह्मण एवं पुराण ग्रंथ में भी वर्णित है। रामायण और महाभारत में भी इससे संबंधित प्रसंग हैं। मान्यताएं यहां इन दिनों देवताओं का वास, दिव्य आत्माओं का स्थान वास और अगनित श्रद्धालुओं का कल्पवास मानती है। इस अवसर पर यहां के जलकणों में अमृत के अंश की पुरातन सनातन मान्यता है। यह सभी के मंगल एवं कल्याण के लिए आहूत एक दिव्य आयोजन है।

इस प्रयाग कुंभ का ध्येय वाक्य सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः अर्थात "सभी मनोरथ पूर्ण हों" का है। ऐसे में माघ महीने की संक्रांति के आगमन उपरांत तीरथराज के संगम क्षेत्र की छटा देखते ही बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में इसे लेकर तब यहां त्रिवेणी स्नान हेतु हर कोई आना चाहता है। इसी कुंभ के आगमन संदेश को जन जन तक ले जाने का सद्प्रयास भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है। इसके वैश्विक प्रचार हेतु केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं के नाते यह अब यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची का हिस्सा है। इसे 2017 में अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। इसके महत्व को समझते हुए वैश्विक तौर पर इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसके बाद से स्वाभाविक तौर पर दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। यह कुंभ पर्व चर्चा प्रसार का एक अवसर भी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने कुंभ 2025 के प्रचार हेतु एक अभियान प्रारंभ किया है। जिसकी प्राथमिकताओं में विश्व के तमाम देशों में बसे भारतीय मूल के लोग भी हैं। योग दिवस की तरह यह भी एक ऐसा उपक्रम है जो भारत विद्या के उपरांत एक भारतीय उत्सव को वैश्विक बनाने का सद्प्रयास है।

विदेशी श्रद्धालुओं का आगमन : विगत कुंभ आयोजनों में हुए सरकारी सद्प्रयासों का एक विस्तार वर्तमान कुंभ में दिखाई दे रहा है। वस्तुतः इस प्रयास में प्रयाग में हुए अर्द्धकुंभ 2019 संग हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में संपन्न हुए विगत के पूर्ण कुंभों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नासिक कुंभ 2015 के ध्वजारोहण में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की सहभागिता ने इसे संत समाज के बाहर चर्चा का एक मुद्दा बनाया था। तब समाज के एक बड़े वर्ग और मीडिया में इसे लेकर कौतूक एवं जिज्ञासाएं बनी थीं, क्योंकि लोगों के लिए ये ध्वजारोहण कुंभ पूर्व की महज एक परंपरा भर है। वहीं समान्यतः बड़े नेता कार्यक्रम पूर्व की तैयारी संबंधित गतिविधियों से स्वयं को दूर भी रखते हैं। उज्जैन कुंभ और हरिद्वार के कोरोन काल वाले 2021 के आयोजन में कई देशों के राजदूत खिंचे चले आए थे। वर्ष 2019 के प्रयाग अर्द्धकुंभ में 188 देशों के दो सौ से अधिक प्रबुद्धजनों का आगमन हुआ था। प्रयाग के इस कुंभ मेला आयोजन से संबंधित तैयारियों को देखने हेतु करीब 70 देशों के दूतावास प्रतिनिधि कुंभस्थल पहुंचे थे। इस कुंभ मेले में कई धर्मगुरुओं के शिविरों में बड़ी संख्या में विदेशी मूल के भक्तों का आना हुआ था। ऐसे में यह कहा जा सकता है कुंभ मेला विदेशियों को भी सनातन संस्कृति के समीप ला और लुभा रहा है।

सेवाभावना को विस्तार : परतंत्रता काल के कुंभ मेले राष्ट्रीय जागरण में महती भूमिका का निर्वहन करते थे। इन्हीं कुंभ मेलों में आकर स्वामी दयानंद सरस्वती और महामना मदन मोहन मालवीय अपने ओजस्वी वाणी एवं नवीन योजनाओं से हिंदू समाज को झंकृत तथा जागृत किया करते थे। ये कुंभ मेला महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद सरीखे राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी आत्म साक्षात्कार का एक पावन अवसर था। गांधी जी ने अपनी जीवनी में हरिद्वार मेला यात्रा का वृत्तांत लिखा है। किंतु कुंभ मेले के माध्यम से समग्रतापूर्ण आमूल परिवर्तनों के विषय में अगर किसी ने सोचा है तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पहले के कुंभ मेलों में आरएसएस की ओर से संतों से संवाद और जुड़ाव का प्रयास होता था। फिर विश्व हिंदू परिषद के उभार के साथ ही यह विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर संवाद के एक सशक्त अवसर में बदलता गया। राम मंदिर आंदोलन के चरों ने कुंभ मेले के धर्म संसद को सुर्खियों में ला दिया। विहिप द्वारा आयोजित यह सभा दुनिया भर में हिंदू धार्मिक मुद्दों की एक औपचारिक सभा के रूप में ख्याति प्राप्त है। अगर हालिया देढ़ दशक की बात करें तो संघ परिवार के उपस्थिति के तौर तरीकों मे काफी अंतर आया है। अब संघ परिवार के दर्जनों संगठनों के लिए कुंभ एक सुअवसर है। इसके माध्यम से ये अपने कार्यक्रम और सेवाकार्य को जनमानस में रखते हैं। यह अवसर इनके प्रचार और छवि निर्माण का भी है।

वर्ष 2016 के उज्जैन कुंभ में संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश से आनेवाले लोगों संग कई कार्यक्रम किए थे। इनमें से एक समरसता समागम स्नान है। इसमें विशेष तौर पर दलित वर्ग के साधु पुजारियों संग कुंभ स्नान का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हिंदुओं के सर्वाधिक सम्मानित संतों ने भी सहभागिता की थी। इस कुंभ के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन तथा जनजातीय समुदाय के लोगों संग विशेष स्नान किया था। इस अवसर पर इनके संगठन द्वारा सफाई कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम और जनजातीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। प्रयाग के अर्द्धकुंभ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुंभ मेला सफाईकर्मियों के पैर धोने की खबर सुर्खियों में थी। उस समय कुंभ के विश्व हिंदू परिषद शिविर में सौ से अधिक जनजातियों के लोग ठहरे थे। वनवासी कल्याण आश्रम और संस्कार भारती संगठन की प्राथमिकताओं में प्रधमतः सुदूर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदाय के लोग थे। वस्तुतः इन इलाकों को छोड़ कर देश के हर हिस्से से आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कुंभ मेले आते रहे हैं।

ऐसे में इन्होंने हिंदी से अपरिचित और ईसाई धर्म के सर्वाधिक प्रभाव वाले क्षेत्र के जनजातीय समुदायों को जुटाने का प्रयास किया था। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आहूत जनजातीय समागम में ऐसे कई हजार प्रतिनिधि जुटे थे। संघ से संबद्ध सांस्कृतिक संगठन, संस्कार भारती का पूरा शिविर ही पूर्वोत्तर भारत के रूपरंग एवं प्रसंग पर बना था। इन्होंने कुंभ में भारतीय इतिहास और कला शिल्प के दर्शनार्थ संस्कृति ग्राम बसाया जा रहा है। शासन द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिभाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उज्जैन से लेकर गत हरिद्वार कुंभ तक इसकी झलक देखने को मिली है। इन विशाल आयोजनों के माध्यम से कई विश्व कीर्तिमानों के बनने और टूटने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पिछले प्रयाग अर्द्धकुंभ ने संख्या संबंधी विश्व रिकार्ड तोड़ा और एक तय समय में एक विशाल कैनवास पर लोगों द्वारा किए गए हस्ताक्षर से भी यहां एक नया कीर्तिमान बना था। इस बार कई कीर्तिमान स्थापित करने की योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है। अस्थायी कुंभ नगरी का निर्माण चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है। यह अब तक के सर्वाधिक विस्तृत कुंभ नगरी की योजना है। यह इसके महत्व और शासकीय दृष्टिकोण का सूचक है।

(अमिय भूषण)

कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार

कुंभ जैसे पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वास्थ्य शिविर जैसी सेवाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। आगामी प्रयाग महाकुंभ की लेकर इनकी ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं। कुंभ पर्व के आगमन के साथ ही संघ का भी शताब्दी वर्ष आ रहा है। ऐसे में इस महाआयोजन में संघ परिवार अपनी सेवा संबंधित गतिविधि संग सनातन संस्कृति और पुरातन प्रकृति के रक्षार्थ दैनें कार्यक्रम करने वाला है। यह विहिप जैसे संगठनों से लेकर गंगा समग्र मंचों के माध्यम से आयोजित एवं संचालित होने वाले हैं।

बात अगर कुंभ मेलों में स्वच्छता और सुविधाओं की हो तो यह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अब हर आयोजन स्वच्छ हरित कुंभ के विचारों के साथ है। इसके साथ ही कुंभ दर कुंभ आधारभूत ढांचाओं का भी जबरदस्त विकास हो रहा है। रही सही कसर प्रदेश विशेष की सरकारों के सकारात्मक दृष्टिकोण के नाते यह और भी बेहतर होता जा रहा है। वर्ष 2013 के प्रयाग कुंभ उपरांत किसी भी आयोजन को लेकर सवाल खड़े नहीं हुए हैं। तब अव्यवस्था के नाते इसके तत्कालीन प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री पर कुप्रबंधन का आरोप लगा था। अब तो इस अवसर न केवल कुंभ नगरी का सौंदर्यीकरण कायाकल्प हो उठता है, बल्कि यात्री सुविधाओं के नाम पर पर्याप्त नव निर्माण भी होते हैं। सड़कों एवं पुलों के संजाल तथा रेल सेवाओं के पर्याप्त सुविधा विस्तार नाते कुंभ नगरी की यात्रा अत्यंत सुगम हो चली है। नई तकनीक के कारण अब गुमशुदा लोगों के लिए डिजिटल खोया पाया और एआइ तकनीक आधारित उच्च सुरक्षा प्रतिमानों पर शिविर ही पूर्वोत्तर भारत के सम्मुख लेकर आ रहा है। कुंभ सुचना एप से लेकर इसके डिजिटल म्यूजियम तक मूर्त रूप लेने को है।

आगामी प्रयाग कुंभ को लेकर धार्मिक कारिडोर निर्माण कार्य भी चल रहा है। पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतों से लोक कलाकारों को बुलाया था। कुंभ के पावन अवसर पर देश के हर हिस्से से सभी समुदायों के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। पूर्वोत्तर भारत से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इनमें ईसाई मतावलंबियों की संख्या भी बहुत रहती है, जो संघ परिवार के प्रयास से सनातन संस्कृति की और आकृष्ट हुए हैं। यह एक भारत-श्रेष्ठ भारत की एक सटीक तस्वीर भी प्रस्तुत करता है।

खरी-खरी

सुन सुन सुन.... प्रदूषण की धुन

केदार शर्मा

दीपावली के बाद उल्लू, मूषक और हंस तीनों एक सरोवर के किनारे बैठकर दीवाली की समीक्षा कर रहे थे। दीवाली पर लक्ष्मीजी ने उल्लू पर, भगवान गणेश ने मूषक पर और मां सरस्वती ने हंस पर सवार होकर भ्रमण किया था। मूषक ने कहा- हे उलूकराज! दीवाली की रात तो माता लक्ष्मीजी ने कई लोगों को धनसम्पदि के खूब वरदान दिए होंगे? उल्लू ने कहा- सभी जगह पटाखों का स्वर गूंज रहा था। तरह-तरह की आतिशबाजी परवान पर थी। अब जहां पहले से ही धन के इतने धमाके हो रहे हों, लक्ष्मी माता का वहां धन की वर्षा करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं था? धन की कमी होती तो अपने मेहनत से कमाए धन को कोई इस तरह से राख में बदलता है भला? माता लक्ष्मी प्रसन्न थीं कि लोगों के पास पहले से ही इतनी धन-संपत्ति है कि ये इसका अंतिम रूप से सदुपयोग करते हुए सम्मानजनक ढंग से उसकी अंतिम क्रिया कर रहे हैं।

मूषक यह सब देखकर हैरत था। राख में बदलने से पहले उनमें से रोशनी और धमाकों की आवाज निकलवाना मनुष्य के बुद्धि कौशल का प्रबल प्रमाण था। निपट-अनाड़ी या ठेठ गंवार होते तो सीधे नोटों को भी जला सकते थे। हर वर्ग का व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार इन विस्फोटक सामानों पर अपनी मेहनत से कमाया अतिरिक्त धन न्यौछावर कर रहा था। मूषक ने कहा कि वह इस पर रौंध करने की सोच रहा है कि यह मनुष्य इतने तेज धमाकों की आवाज सुनने और इतनी चकाचौंध भरी रोशनी देखने का इतना अधिक दीवाना क्यों है?

उल्लू बोलता रहा- इतना करने के बाद सब मिलकर आम आदमी से निबेदन कर रहे थे- अब तुम आतिशबाजी चलाना ही मत। देख! पर्यावरण को भारी खतरा है।

गलती आम आदमी की है कि उसने संयम क्यों नहीं रखा? नहीं रखा तो भुगते। हर साल भुगतता है वैसे ही इस साल भी भुगते। अगले साल भी भुगत लेगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा। इस तरह से किसी न किसी साल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ ही जाएगी। हे आम आदमी, सुन सुन सुन...., प्रदूषण की धुन।

पोस्ट

अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। वामपंथी विचारधारा, पुनावों को प्रभावित करने एवं मनमाफिक लोगों को सत्ता पर काबिज करने वाली शक्तियों को भारत के बाद एक और करारी हार।
मधु शर्मा@VedaRicha

डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बारूदीख की गहरी नजर होगी, क्योंकि शीर्ष अमेरिकी नेताओं में ट्रंप ही इकलौते थे, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें हिंदुओं के दमन पर टिप्पणी की थी।
सिद्धांत सिबाल@sidhant

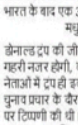

राष्ट्रपति चुनाव, वापुलर वोट्स से लेकर संसद के उच्च सदन सीनेट और निचले सदन प्रतिनिधि सभा, हर जगह ट्रंप की पार्टी का झंडा बुलंद रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 'मोरल विक्ट्री' की भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची।
शुभंगी शर्मा@ItsShubhangi

कमला हैरिस बार-बार कह रही थी कि इस चुनाव में लोकतंत्र खतरे पर है, डोनाल्ड ट्रंप जीते तो अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। हालांकि अमेरिका ने कमला के प्रचार को नकार दिया और ट्रंप को गद्दी सौंप दी। लोकतंत्र पर खतरे वाला प्रचार भारत की तरह अमेरिका में भी नहीं चला।
अमितभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या निजी संपत्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला संपत्ति के पुनर्वितरण की मांग करने वालों के लिए प्रेरणा है?

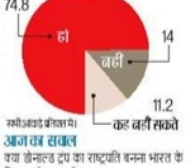

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिहाज से अच्छा है?

परिणाम जागरण डॉट नेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जलवा दादा ट्रम्प का देखा फिर इक बार,
जीत हुई उनकी गजब अरु हैरिस की हार।
अरु हैरिस की हार धार इससे और दिखेगी,
नया एक अध्याय ट्रम्प सरकार लिखेगी।
ट्रम्प समर्थक आल बाँटेंगे जमकर हलवा,
देखेगा अब विश्व ट्रम्प दादा का जलवा।
- ओमप्रकाश तिवारी

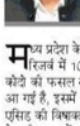

धनंजय प्रताप सिंह
रुग्ण शूरो ब्रुख,
मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

प्रशासनिक लापरवाही है हाथियों की मौत

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत में कोदो की फसल खाने की वजह सामने आ गई है, इसमें साइकलीपियाजोनिक एसिड की विषाक्तता पाई गई है। हाथियों ने बड़ी मात्रा में कोदो की फसल खाई थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) बरेली उत्तर प्रदेश की इस रिपोर्ट ने भले ही हाथियों की मौत के लिए कोदो की फसल को जिम्मेदार माना है, लेकिन इसमें प्रशासनिक लापरवाही को माफ नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक लापरवाही इसलिए है, क्योंकि हाथियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी तैनात हैं। यदि कोदो की फसल हाथियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी तो टाइगर रिजर्व का अमला क्या कर रहा था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बाघों की बड़ी संख्या में मौत और अवैध शिकार के मामले में बांधवगढ़ का वन्य प्राणी प्रबंधन कटघरे में है।

दरअसल, यहां वन विभाग के अमले के अलावा कई एनजीओ भी हाथियों के संरक्षण और जागरूकता के काम में लगे हुए हैं, इसलिए यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है कि आखिर हाथी रात भर खेतों में कोदो की फसल चरते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यह भी बताया है कि जब उन्होंने हाथियों को बेहोश देखा तो वन विभाग को सूचना दी। लेकिन कर्मचारी देर से पहुंचे और अधिकारी तो तब पहुंचे जब हाथियों की सांस टूट चुकी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमार और मौत से जूझ रहे हाथियों को इलाज कब और कितनी देर बाद मिला होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि मंगलवार को मृत हाथियों की विसरा सैंपल की विषाक्तता रिपोर्ट आइवीआरआइ से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मृत हाथियों के विसरा में साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाया गया है। नमूनों में पाए गए इस एसिड की विषाक्तता की वास्तविक गणना और आगे की जा रही है।

हाथियों के उन्मुक्त जीवन की राह में कई बाधाएं है, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। फाइल

बांधवगढ़ में हाथियों की मौत में गैर जिम्मेदारी का यह पहला विषय नहीं है। कुछ ही समय पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की बड़ी संख्या में मौत का मामला देशभर में चर्चा में आया था। तीन वर्ष में 34 बाघों की मौत पर जब जांच कराई गई तो रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं। बांधवगढ़ में वर्ष 2021 में 12, वर्ष 2022 में नौ और वर्ष 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक बाघों की मौत मनपुर बफर जोन में हुई। जांच रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक को पोस्टमार्टम न करने का दोषी बताया गया है, लेकिन वहां अलग-अलग समय में पदस्थ रहे फील्ड डायरेक्टरों से लेकर वन अमले और काम करने वाले एनजीओ की भूमिका की जांच नहीं की गई। टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत सामान्य न होकर शिकार किए जाने की आशंका भी जताई गई है।

बाघों की मौत की यह चर्चा इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हाथियों की मौत ने एक बार फिर पार्क प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जाता है कुने में पदस्थ सरकार के एक चहेते अधिकारी को यहां उप संचालक बनाकर भेजा गया है। सरकार ने अवकाश पर गए संचालक को तो निलंबित कर दिया, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी बच गया है।

यह बात भी सही है कि मध्य प्रदेश कभी भी हाथियों का ठिकाना नहीं रहा है। पहला अवसर है जब छह वर्ष से हाथी यहां बस गए हैं। पहले भी वे आते थे और लौट जाते थे। पर छह वर्ष का समय कम नहीं होता है, इतने दिनों में तो वन विभाग अपने कर्मचारियों को हाथी वाले राज्यों में भेजकर प्रशिक्षित कर सकता था।

यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि यह मुद्दा वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार से भी जुड़ा है। पिछले कुछ दशकों में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भयावह तरीके से बढ़ा है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के बारे में तो कहा जाता है कि वे हजारों करोड़ के असामी हैं। यह अलग विषय है। पर हाथियों की मौत ने एक बार फिर एमपी के सुशासन पर सवाल खड़ा किया है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों का पब्लिक आडिट भी कराया जाना चाहिए कि अखिर वे वन्य प्राणियों का संरक्षण किस तरह कर रहे हैं। राज्य वन्यप्राणी सलाहकार बोर्ड को भी देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई। कभी उन्होंने वन्यप्राणी प्रबंधन में हो रही लापरवाही का विषय उठाया या नहीं। एक तरफ यहां सर्वाधिक बाघ हैं, तेंदुए हैं, चीते भी केवल यहीं हैं। ऐसे प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन कैसा है, यह गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह चिंता केवल एमपी सरकार की ही नहीं है, बल्कि भारत सरकार को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए।

छठ पूजा

प्रकृति से जोड़ने वाला महापर्व

छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। संध्या समय में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। प्रकृति की उपासना का यह पर्व हम सभी को अपनी धरा और संस्कृति से जोड़ता है

नीरजा माधव
साहित्यकार

छठ मैया के गीतों में रची बसीं विश्वव्यापी ख्याति अर्जित करने वाली लोक सुर साधिका शारदा सिन्हा का छठ पर्व के दिन ही महाप्रयाण प्रकृति के उस रहस्य की ओर संकेत करता है जिसे जानने की जिज्ञासा मानव मात्र में है। मुझे याद आ रहा है, मैं उस समय आकाशवाणी वाराणसी में प्रोग्राम अफिसर थी। किसी कार्यक्रम के सिलसिले में शरदा सिन्हा जी काशी पधारी थीं। आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाकर मैंने उनका साक्षात्कार लिया था। उस समय उनका यह गीत बहुत चर्चा में था- कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा....। इस गीत के साथ ही उन्होंने छठ के उस गीत की भी पंक्तियां गुनगुनाई थीं- कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय...। कच्चे बांस की लचक जैसे स्वर लहरी आज भी कानों में वैसे ही गूंज रही है। हर घाट, नदी, सरोवर, तालाब के किनारे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से बज रहा है और उस कच्चे बांस की लचकती हुई स्वर लहरी दूर कहीं अनंत में विलीन हो रही है।

लोक आस्था : छठ का पर्व है। हर नदी, तालाब, सरोवर के किनारे एक मेले जैसा दृश्य है। घाट पर बंधी जंजीरों से आगे न जाएं, पानी गहरा है, बच्चों का हाथ न छोड़ें, जैसे अनेक हैदायतें बीच-बीच में प्रसारित होते हुए। पुलिसकर्मी इधर-उधर व्यवस्था में तत्पर। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के परिजन और पर्व का आनंद लेने आए लोगों का विशाल जनसमूह। अधिकांश व्रती महिलाओं की नाक से प्रारंभ होकर सिंदूर की चटक नारंगी आधा मांग के बीच तक फैली है। सूर्य की उष्ण प्रत्यूषा की लाली को मात देते हुए। यह सब छटा देखते ही बनती है।

अस्ताचलगामी सूर्य : उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, पर भारत का यह लोक पर्व अस्त होते सूर्य को भी उतना ही स्तुत्य मानता है। शायद विश्व को सनातन दर्शन का संदेश देता है कि अस्त होना और उगना सृष्टि की प्रक्रिया है और इस प्रकार इस प्रकृति में आवागमन की भी। यह कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। मैं भी इस भीड़ में अकेली चुपचाप बैठी देख रही हूं आस्था के इस महापर्व को। हल्की सी ठंड है। अरघ के गीत गाती महिलाएं हाथ में दीप और नैवेद्य से भरा सूप लिए धीरे-धीरे जल में उतर कर खड़ी हो रही हैं। साथ ही, उतर रही है लोक की आस्था भी। जल की तरह ही पारदर्शी।

चार दिवसीय पर्व : कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होता हुआ यह व्रत चौथे दिन सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। यानी इस बार यह पर्व मंगलवार से आरंभ हुआ है जिसका समापन शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। इस पर्व की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें श्रद्धालु के रूप में पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की होती है। व्रत व्रती स्त्रियों की आस्था, विश्वास। बिना किसी मंत्रोच्चार के मौन आत्म निवेदन। क्या हमारे वेद भी इसीलिए नेति नेति कहते हुए अंत में मौन हो जाते हैं। मैं सोचने लगती हूं, किसी लौकिक या वैदिक मंत्रोच्चार के बिना ही घुटनों भर जल में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य को निहारते हुए अर्घ्य देना, छठी मैया के निमित्त धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में प्रकृति के विभिन्न फूलों-फलों को अर्पित करना, गन्ने के मंडप के नीचे वेदी सजाकर प्रकृति के विराट स्वरूप के सम्मुख लोक का नतमस्तक होना क्या यूं ही अकारण होगा? कुंभ एक विशेष स्थान पर लगता है। परंतु सूर्य उपासना का यह पर्व हर तालाब, नदी के किनारे लगता है, जहां हजारों लाखों व्रती महिलाएं, बच्चे पुरुष सभी इकट्ठा होते हैं। शहरों में जिन घरों के आसपास तालाब या नदी नहीं है, वे लोग छतों के ऊपर किसी टब या बड़े पात्र में जल एकत्रित करके उसमें खड़े होते हैं और अर्घ्य देते हैं।

लोक जीवन की महत्ता : मैं आश्चर्य से भर उठती हूं लोक की इन परंपराओं की आपसी संयुक्तता पर और कथाओं पर। सूर्य आरोग्यता के देवता हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन के कारण भी सूर्य की उपासना के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और षष्ठी का संबंध भाई-बहन का है। मैं मुग्ध भाव से निहारती हूं लोक के इस अनसंवरे सौंदर्य को। एक व्रती स्त्री ने धीरे से उठकर मेरे भी नाक से प्रारंभ कर बालों के बीचो-बीच तक सिंदूर की एक चौड़ी रेखा बना दी है। वातावरण में लोकगीत तैर रहा है- छठी मइया देइ ना अशीष...। स्वर में कच्चे बांस की लचक है। सूर्य की प्रतीक्षा है। शक्ति का सान्निध्य है, और छठी मइया का आशीष भी। मैं मुस्कुरा उठी हूं लोक जीवन की इस सहज भव्यता पर।

शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं हैं। परंतु छठ पूजा के गाए उनके गीत हमारे साथ हैं। उनके गीतों से छठ पर्व की आभा निरंतर बिखरती रही।

आधुनिक होती जीवनशैली के बीच कायम है छठ पर्व में प्राकृतिक कणों की महत्ता। फाइल

****

कल्पमेधा

किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे न पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। ऐसा इसलिए कि सही सम्मान योग्यता में है, न कि उसे किसी से पाने में।

- मार्क ट्वेन

अमेरिका की सत्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाजी अपने नाम कर ली है। उन्होंने बहुमत के जरूरी आंकड़े से कहीं अधिक मत हासिल कर लिए हैं। सर्वेक्षणों में नतीजे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पक्ष में जाते दिख रहे थे। मगर मतदान के आखिरी दिन कांटे की टक्कर नजर आने लगी। ट्रंप को उन सात राज्यों में भी बढ़त हासिल हुई, जो पलटी मारने वाले राज्य यानी 'स्विंग स्टेट' माने जाते हैं। हालांकि ये नतीजे हैरान करने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उसी वक्त कमजोर पड़ने लगी थी, जब ट्रंप के आक्रामक चुनाव प्रचार के सामने राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी अस्वस्थता के चलते शिथिल नजर आने लगे थे। उसके बाद कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया। मगर पार्टी के भीतर ही उथल-पुथल शुरू हो गई थी। इस तरह कमला हैरिस को समय कम मिल पाया। हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी और महिला मतदाताओं को लुभाने में कामयाब भी रहीं। मगर ट्रंप ने कमजोर अर्थव्यवस्था, महंगाई और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बाइडेन सरकार पर निशाना साधा, और उसका असर वहां के मतदाताओं पर पड़ा। हालांकि इन मसलों पर ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत आक्रामक ढंग से काम किया था। उसी का प्रभाव था कि इस बार के चुनाव प्रचार में वहां के कई बड़े उद्योगपति भी उनके साथ मंच पर उतरे थे।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था हालांकि अब भी बहुत खराब नहीं है, मगर पहले की तुलना में उसकी रफ्तार धीमी जरूर पड़ गई है। उस पर मंदी की मार है। महंगाई अब तक के पचास वर्षों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने वादा किया कि वे एक करोड़ अवैध प्रवासियों को देश से निकाल बाहर करेंगे, उन पर करोड़ों डालर खर्च हो रहा है, तो वहां के युवाओं में नए अवसर की उम्मीद जगी। पिछले कार्यकाल में भी उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन हासिल था। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप आक्रामक ढंग से प्रशासन चलाने में विश्वास करते हैं और आर्थिक नीति तथा विदेश नीति को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। वे रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उसे रुकवा देंगे। इस तरह उन पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह कई बार राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ीं, उसकी भरपाई वे कभी नहीं कर पाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे तो शायद वे पार पा लें, मगर विदेश नीति को लेकर उन्हें सदा संदेह की नजर से देखा जाता रहा है। चीन के प्रति उनका रुख बहुत सख्त है। इस वक्त दुनिया में जिस तरह के समीकरण हैं, उसमें वैश्विक दक्षिण की अहमियत बढ़ी है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कोई तनाव नहीं है, मगर चीन और रूस के साथ अमेरिकी रिश्ते तल्ख होंगे तो भारत के साथ भी समीकरण गड़बड़ होने का खतरा हो सकता है। सबसे अहम बात कि अगर ट्रंप आव्रजन नीति में बदलाव करते हैं, तो वहां रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर, दुनिया में बढ़ रहे जलवायु संकट को लेकर ट्रंप संजीदा नहीं रहे हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठते रहे। अगर इस बार भी उनका वही रुख रहेगा, तो उनका विवादों से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

वादे का निर्वाह

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पास होना एक तरह से सत्तारूढ़ दल का अपने वादे का निर्वाह करना ही है। इस बार वहां के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली प्रमुख मुद्दा था। इसे नैशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने वादों में शामिल किया था। दरअसल, अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा स्वतः समाप्त हो गया था। फिलहाल जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है। इसलिए वहां शासन संबंधी बहुत सारी शक्तियां उपराज्यपाल में निहित हैं। जबकि वहां की सरकार का वादा है कि वह लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा तभी संभव होगा जब उसका विशेष राज्य का दर्जा बहाल हो। प्रस्ताव में भी कहा गया है कि विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करती है। इनसे जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। हम इसे एकतरफा हटाए जाने से चिंतित हैं। विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करे और एक संवैधानिक रास्ता निकाले।

प्रस्ताव में कहीं भी अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं कही गई है। यानी जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस मसले को तूल देने के बजाय विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। उधर, जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने पूर्ण राज्य के दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र को पहले ही भेज दिया था। केंद्र सरकार भी कहती आ रही है कि बहुत जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। मगर असल अड़चन इसी मसले पर आ सकती है कि उसके विशेष राज्य के दर्जे को किस रूप में सुरक्षित रखा जाए। जिस कश्मीरियत की बात की जाती रही है, उसे इसी के जरिए सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया जा सकता है। इस संवैधानिक पहलू पर केंद्र और राज्य सरकार किस तरह तालमेल बिठा पाती हैं, देखने की बात है।

आभासी गिरफ्त में वास्तविक लोग

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर लुटेरों के हाथ लगा कितना बड़ा हथियार है, इसे इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2024 की पहली तिमाही में पूरे देश से साइबर ठगी की करीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं।

अभिषेक कुमार सिंह

तकनीक और विज्ञान के लिए यह उक्ति नई नहीं है कि वरदान के साथ इसके कुछ अभिशाप भी हैं, जो हमें झेलने पड़ सकते हैं। मगर कोई तकनीक महामारी का रूप धर ले, तो इससे जुड़ी चिंता काफी बढ़ी हो जाती है। मौजूदा वक्त में हमारे देश के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' एक ऐसा ही संकट है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हाल में अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में किया। देश की जनता को इसके खतरे से आगाह करते हुए उन्होंने अपील की कि लोग सतर्क और जागरूक रह कर इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री को इस आह्वान की जरूरत क्यों पड़ी। क्या साइबर धोखाधड़ी रोकने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं या फिर आम लोगों की इस बारे में जागरूकता इतनी कम है कि वे साइबर फर्जीवाड़ा करने वालों की चाल में फंस जाते हैं।

जबसे देश में नकद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान की व्यवस्था बनी है और लोगों का उसमें रुझान बढ़ा है, साइबर धोखेबाजों ने इस रास्ते आम जनता को ठगने के लिए अनेक कारगुजारियां की हैं। हालत यह है कि सरकार और उसकी एजंसियां साइबर ठगी से लोगों को बचाने के जो इंतजाम करती हैं, वे जल्द ही इस किस्म की धोखाधड़ी करने वालों के आगे नाकाफी साबित होने लगते हैं। आम जनता को कहा जाता है कि मोबाइल से बैंकिंग लेनदेन के वक्त पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी से साझा न करें, तो साइबर ठग कोई विश्वसनीय दिखने वाला लिंक भेज कर लोगों के फोन ही हैक कर लेते हैं। ऐसे में सारे पिन और ओटीपी ठगों के वांछित फोन पर जाने लगते हैं और देखते ही देखते लोगों के बैंक खातों में जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है। इस पर लगाम लगती, इससे पहले 'डिजिटल अरेस्ट' के रूप में की जाने वाली लूट सामने आने लगी।

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर लुटेरों के हाथ लगा कितना बड़ा हथियार है, इसे इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2024 की पहली तिमाही में पूरे देश से साइबर ठगी की करीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं। उनमें से 120.3 करोड़ रुपए की चपत आम लोगों को आभासी गिरफ्तारी का डर दिखा कर लगाई गई है। बीते एक वर्ष में आम जनता साइबर ठगी के जरिए 1776 करोड़ रुपए की रकम गंवा चुकी है। हालांकि इसमें 1420 करोड़ रुपए सीधे-सीधे शेयर बाजार की लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर, 222.58 करोड़ रुपए निवेश की अन्य फर्जी योजनाओं में फंसा कर और करीब सवा तेरह करोड़ रुपए रोमांस से जुड़ी 'डेटिंग साइट' में उलझा कर ठगों ने लोगों से वसूले हैं। लेकिन इधर जो चिंता देश के आर्थिक पटल पर सबसे अहम खतरे के रूप में उभरी है, वह है 'डिजिटल अरेस्ट'।

आखिर 'डिजिटल अरेस्ट' नामक फर्जीवाड़ा क्या है और यह दूसरे किस्म की साइबर धोखाधड़ी से कैसे अलग है। असल में, अभी जो आनलाइन धोखाधड़ी साइबर ठग कर रहे हैं, उनमें लोगों के बैंकिंग विवरण (जैसे पिन, पासवर्ड, ओटीपी) जान कर खातों से रकम उड़ाना

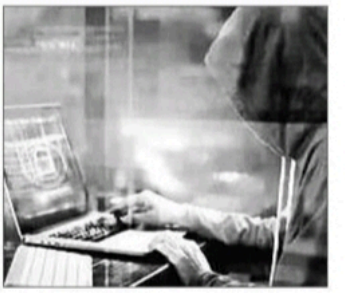

प्रमुख है। लोगों को उनके मोबाइल फोन पर ठग कोई लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करने और मामूली रकम का बैंकिंग लेनदेन करने पर साइबर ठगों को उस व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं। इसके बाद ये धोखेबाज लोगों के खातों में जमा रकम निकाल लेते हैं, जिसका पता काफी समय बाद लग पाता है। ठगे गए लोग साइबर थानों में समय पर शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते हैं।

> **बीते एक वर्ष में आम जनता साइबर ठगी के जरिए 1776 करोड़ रुपए की रकम गंवा चुकी है। हालांकि इसमें 1420 करोड़ रुपए सीधे-सीधे शेयर बाजार की लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर, 222.58 करोड़ रुपए निवेश की अन्य फर्जी योजनाओं में फंसा कर और करीब सवा तेरह करोड़ रुपए रोमांस से जुड़ी 'डेटिंग साइट' में उलझा कर ठगों ने लोगों से वसूले हैं। लेकिन इधर जो चिंता देश के आर्थिक पटल पर सबसे अहम खतरे के रूप में उभरी है, वह है 'डिजिटल अरेस्ट'।**

ज्यादातर मामलों में ये ठग खातों से सारी रकम निकाल कर रफू-चक्कर हो जाते हैं। तब पुलिस या अन्य एजंसियां किसी तरह इन तक पहुंच भी जाएं, तो रकम की वसूली आसान नहीं होती। हालांकि जागरूकता अभियानों के कारण लोग कुछ सतर्क हुए हैं, लेकिन ऐसा होते देख साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका 'डिजिटल अरेस्ट' के रूप में निकाल लिया है।

इसमें असली पुलिस या जांच एजंसियों के वास्तविक अधिकारियों के वेश में ठग लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखा कर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें किसी शख्स को मोबाइल फोन पर वीडियो या सामान्य काल करते हुए गिरफ्तारी या सीबीआइ अथवा आयकर जांच का भय दिखाया जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है, तो वह इनके आगे खुद को निरुपाय महसूस करने लगता है। तब ये साइबर ठग उस व्यक्ति को अपनी सारी जमा-पूंजी बताए गए बैंक खातों में खुद ही भेजने को मजबूर कर देते हैं। देखा गया है कि 'डिजिटल गिरफ्तारी' वाले ज्यादातर मामलों में सबसे पहले एक अनजान खोत से काल आती है। इसमें फोन करने वाला व्यक्ति खुद को सामान डिलीवरी करने वाली कूरियर सेवा का प्रतिनिधि होने का नाटक करता है। वह दांव फेंकता है कि आपके द्वारा भेजा गया एक कूरियर किसी बंदरगाह या एअरपोर्ट पर जांच में फंस गया है, क्योंकि उसमें गैरकानूनी मादक पदार्थों की खेप मिली है। इस प्रकार झांसे में आए व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय तस्करी के गिरोह का सदस्य बता कर उसकी बात पुलिस समेत अन्य जांच एजंसियों के नकली अधिकारियों से कराई जाती है। फर्जी एफआइआर, गिरफ्तारी का वारंट और अन्य नकली दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं, जिनमें पीड़ित का नाम दर्शाया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह भयभीत हो जाता है।

'डिजिटल गिरफ्तारी' वाले मामले सिर्फ कूरियर कंपनी के झांसों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें लोगों के बेटे या बेटी के किसी मामले में फंसे होने, यौन शोषण के आरोपी होने, किसी आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल होने जैसे तमाम मामलों का हवाला असली दिखने वाले फर्जी सबूतों के आधार पर करते हैं। ऐसे मामलों में वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वीडियो काल पर किसी थाने में बैठे हुए पुलिसिया भाषा में बात करते दिखाया जाता है। पीड़ित को जब गिरफ्तारी की आशंका सच में बदलते हुए प्रतीत होती है, तो वह बिना देर किए, ठगों के संकेत पर मांगी गई रकम भेजने में ही अपनी भलाई समझता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सजग रहे, रुपए-पैसे के लेनदेन से जुड़ी अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचे और आभासी गिरफ्तारी के डर पर काबू पा ले, तो साइबर लुटेरों के मनसूबे पूरे नहीं हो सकते। इसमें पहली शर्त यही है कि अनजान नंबरों से आए फोन को सुना ही न जाए। अगर कोई फोन काल सुनना जरूरी हो जाए, तो बिना डरे और निजी जानकारियां साझा किए, बात की जाए। देश में फर्जी आधार कार्ड, नकली पहचान पत्र और पते-ठिकाने से जुड़े फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खातों के खोले जाने से समस्या और बढ़ी है। ऐसे में पकड़ में आए साइबर ठगों के नाम, फोटो और पते को सार्वजनिक करते हुए कड़ी सजा देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो सिर्फ गाल बजाते रहने भर से साइबर फर्जीवाड़े हरगिज नहीं रुकेंगे।

सोचना बनाम करना

लोकेंद्रसिंह कोट

दुनिया मेरे आगे

आम आदमी इन दिनों बहुत कुछ सोचने लगा है। आजादी से पहले के दिनों में आम जिंदगी की जरूरतों से इतर या उसके समांतर सोचने का एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य में आजादी सबसे प्राथमिक थी। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सामने कुछ स्पष्ट मार्ग थे और साथ थे महान मार्गदर्शक, संस्कार और उसूल। इसके अलावा भी बहुत कुछ, जिससे अपने वजूद का बेहतरीन अहसास होता था। एक नई आत्मसंतुष्टि का भी आभास होता था। कई लोग तो हंसते-हंसते खुद को बलिदान कर देते थे। अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे। आज यकीन नहीं होता कि हम उन्हीं बलिदानियों के बाद की पीढ़ी के हैं। कई बार यह सोच कर शर्मिंदगी होती है कि ऐसे लोग भी हैं यहां कि सिर्फ एक कागज को इधर से उधर करने के लिए अलग से कुछ पैसे सामने वाले से हथिया लेते हैं। वरना उनका काम रुक जाता है। हजारों योजनाओं के हजारों लाख रुपए कहां चले जाते हैं, पता नहीं चलता। हम ही असमानता से बिखरने लगे थे, लेकिन पैसों का केंद्रीकरण सिर्फ कुछ लोगों के पास हो गया।

इन दिनों खुद पर पड़ने वाली नजरें भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम कुछ लोलुप नजरों में महज 'वोट' बनकर रह गए हैं, जहां हम उपभोग में लाए जाते हैं स्वार्थवश। हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए उन्ही संबंधों की भावनाओं को लेकर उनके पास वोट मांगने जाते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। हमारी उन लोगों के प्रति प्रतिबद्धताएं ज्यादा हैं और लगभग रोज उन्ही से टकराना है। ऐसे में हम उन्हें बड़े नेताओं की तरह बहला-फुसला नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ की नजरों में हम उन बड़ी-बड़ी कंपनियों के लुभावने दावों से प्रभावित होने वाले 'ग्राहक' भर हैं, जो अपना सामान बेचने के लिए तमाम भावनाएं लूट लेते हैं। 'मुफ्त वाले माल' को नकारने वाले आदर्श को अपनाते-अपनाते हम 'एक के साथ दो मुफ्त' वाले आदर्श अपना बैठे हैं। अपने ऊपर से बोझ हल्का करने के लिए हम यह भी सोचते हैं कि 'तह के अंदर भी हाल वही है, जो तह के ऊपर हाल, मछली बचकर जाए कहां जब जल ही सारा जाल।'

हम बाबा खड़गसिंह की उस कहानी के बारे में भी सोचते हैं, जहां से विश्वास का संकट शुरू हुआ था। अब हमारे मध्य विश्वास इतना पुराना हो चला है कि उसे हाशिये पर करने के लिए हमने उसके लिए 'वृद्धाश्रम' खोल दिए हैं और उन्हीं में वह अपना निर्वासित जीवन जी रहा है। हम सोचते हैं उस निरीह आदमी के बारे में जो हमारी आंखों के सामने अविश्वास का शिकार होकर खाली हाथ लौट जाता है, जो हो सकता है विश्वास करने योग्य हो। धर्म से लेकर कर्म क्षेत्र और परिवार से लेकर बाजार, सभी तरफ संदेह के आगोश में लिपटकर अविश्वास हमारी भावनाओं की बहुमंजिला इमारतों में बने फ्लैटों में रहने लगा है। विश्वास का संकट गांव में भी बढ़ा है, लेकिन सुरम्य और संपन्न शहर की तुलना में आज भी गांव लाख दर्जे अच्छे हैं। गांव का कोई व्यक्ति यह कहता हुआ मिल जा सकता है कि विश्वास आपस में कम हुआ है, लेकिन शहरी आदमी पर विश्वास सहजता से कर पाना मुश्किल हो गया है। जबकि गांव के लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वाकये गांव वालों के साथ अक्सर देखे जा सकते हैं, जिनमें शहरियों ने उन्हें धोखा दिया। पंचायत के ज्यादातर काम-काज विश्वास पर ही होते हैं।

सोचने का मसला यह भी है कि जिस आदमी को शासक बनना था, वह इधर-उधर की खाक छान रहा है। जिसे वास्तव में वैज्ञानिक होना था, वह मजदूरी कर रहा है। जिसे वास्तव में इंजीनियर बनना था, वह कहीं बैठा दिहाड़ी पर 'वेल्डिंग' कर रहा होता है। जिसे मौका मिलना था आगे बढ़ने का, वह बेरोजगारी का शिकार होकर हाथ बांधे बैठा है। हजारों युवाओं को देश के रचनात्मक आंदोलन में हिस्सेदार होना था, वे सब बेरोजगार बैठे हैं या फिर गलत व्यसनों-व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। प्रतिभाओं का मूल्यांकन और उन्हें मंच मिलना सिर्फ शहर तक सीमित रह गया है, जबकि गांव में भी विभिन्न खेलों से लेकर अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में ग्रामीण प्रतिभाएं कमतर नहीं हैं।

> **हम सिर्फ सोचते ज्यादा रहे हैं। सपनों में ही ज्यादा खोते रहे हैं। इसलिए शायद हकीकत का धरातल उथला रह गया। हम हर चीज तोड़ते-फोड़ते रहे, शासकीय संपत्ति को बेगाना समझते रहे। प्रतिफल यह रहा कि हम आवरण से देश प्रेम के गीत, बातें तो करते रहे, पर हम यह नहीं सोच पाए कि हमें सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है।**

समाज के प्रतिष्ठित और प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स से समाज के प्रति प्रतिबद्धता की आशा की जाती है, क्योंकि वे अपने अनुजों के लिए 'आदर्श' होते हैं। लेकिन अफसोस कि उनमें से अधिकतर बिखरे हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं।

हम इस बारे में भी सोच लेते हैं कि सिर्फ स्कूल-कालेज जाने से ही 'शिक्षा' प्राप्त हो जाती है। जबकि तमाम डिग्रियों से लदे लोग भी आज ऐसे कार्य करते हैं कि उनकी शिक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है। किसी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति से संबंधित विषय के बारे में पूछने पर निराशा हाथ लग सकती है। जो शिक्षा हमें सतही ज्ञान भर दे जाती है और तनावों, विचलनों पर विजय पाना नहीं सिखाती है, उस पर हम गर्व करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अक्सर 'गंवई' करार दिया जाता है। दरअसल, हम 'एसी' की ठंडक में बैठे यह सोच लेते हैं कि 'अ' से 'द' तक के गरीबों को फलां समस्या है और 'ई' से 'फ' तक के किसानों को फलां समस्या है। जबकि आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से को सिर्फ एक वक्त का भोजन नसीब होता है।

देखा जाए तो हम सिर्फ सोचते ज्यादा रहे हैं। सपनों में ही ज्यादा खोते रहे हैं। इसलिए शायद हकीकत का धरातल उथला रह गया। हम हर चीज तोड़ते-फोड़ते रहे, शासकीय संपत्ति को बेगाना समझते रहे। प्रतिफल यह रहा कि हम आवरण से देश प्रेम के गीत, बातें तो करते रहे, पर हम यह नहीं सोच पाए कि हमें सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है।

लापरवाही का नतीजा

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में न केवल चालकों की, बल्कि सड़कों की देखरेख करने वाली एजंसियों की लापरवाही के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। जब भी किसी राज्य में इस तरह की घटना होती है, तब संबंधित राज्य सरकार इन घटनाओं की जांच के आदेश दे देती है। विभिन्न जांच समितियां भी बनाई जाती हैं और वह खामियों को दूर करने की सिफारिश भी करती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर किसी हादसे की खबर आ जाती है। जाहिर है, यह हादसा लापरवाही का नतीजा होता है। राज्यों में निजी वाहन भी यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। दुसरी ओर, कहीं पर बस खाई में गिरती है, तो कहीं पर पहाड़ी घुमावदार होने के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे इस तरह के अवरोधक लगाने होंगे कि कोई वाहन फिसल कर खाई में न गिरे। ऐसे स्थान को चिह्नित करना होगा। पुलिस को भी कर्तव्य का पालन करना होगा ताकि किसी भी परिवार का कोई चिराग न बुझे।

- मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

पर्दे के पीछे

टकराव की हद (संपादकीय 5 नवंबर) से रुपए है कि कनाडा सरकार वोट की राजनीति कर रही है। जिस खालिस्तान का नामो-निशान भारत से मिट चुका है, उसकी फसल काटते हुए ट्रूडो राजनयिक आचार संहिता को भी लहूलुहान करने पर आमादा हैं। मंदिरों पर लगातार हमले पर ट्रूडो के दिखावे के बयान और खालिस्तानियों को उकसाने की मानसिकता जगजाहिर हो चुकी है। सवाल है कि ट्रूडो को भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की शक्ति आखिर कहां से मिल रही है। विश्व की कुछ महाशक्तियां एक ओर भारत से दोस्ती की बात करती हैं, वहीं कनाडा को भारत के विरुद्ध अपना समर्थन देकर अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन भी कर रही हैं। ऐसे में भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि कनाडा में पोषित अतिवादियों द्वारा भविष्य में भारतीयों और उनके धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाई जा सकती है।

- अशोक कुमार पटना, बिहार

घाटी की सच्चाई

जम्मू-कश्मीर में चुनाव नतीजे आते ही जिस तरह आतंकियों ने अपनी हरकतें शोहराई हैं, उससे साफ है कि जम्मू-कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उचित तो यही था कि अभी चुनाव न करा कर, जम्मू-कश्मीर को कम से कम दो वर्षों तक राष्ट्रपति शासन के अधीन ही रखा जाता। पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि आतंकियों को अपने इरादे पूरे करने में कौन-कौन सहायक हो सकते हैं? उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही आतंकियों की मानो मुराद पूरी हो गई हो। ऐसा नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं के बयानों से स्पष्ट भी है। फारूख अब्दुल्ला और राशिद अल्वी ने कहा है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़ कर पूछताछ करनी चाहिए। आतंकियों ने सेना, पुलिस और बाहरी लोगों को पिछले दिनों जिस तरह निशाना बनाया, उससे जाहिर है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति अभी पूर्ण राज्य के लिए अनुकूल नहीं है।

- नरेंद्र टोकि, मेरठ

कूड़े के पहाड़

आज दिल्ली में कई जगह पहाड़ जैसे कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। आखिर यह टनों कूड़ा आता कहां से है? प्रतिदिन लाखों वस्त्र बिकते हैं। इनकी पैकिंग में फोम और कागज का इस्तेमाल होता है। वस्त्र के वजन से ज्यादा पैकिंग का वजन होता है। वस्त्र इस्तेमाल होने के बाद अलमारी में रखे दिए जाते हैं और फोम सड़कों के पर फेंक दिया जाता है। इसी तरह पहले शीतल पेय कांच की बोतल में आते थे, जिसे पीने के बाद बोतल वापस कंपनी में चली जाती थी और फिर धुल कर इस्तेमाल हो जाती थी, लेकिन अब प्लास्टिक की बोतल में शीतल पेय आता है, जिससे पेय पेट के अंदर और बोतल सड़क पर पहुंच जाती है, जो गंदगी का कारण बनती है। इस पर न कंपनियां सोच रही हैं, न सरकार और न ही आम आदमी आवाज उठा रहा है। कचरा कम हो, इसके उपाय होने चाहिए।

- धरमजीत अरोड़ा, मरेला, दिल्ली

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 7 नवंबर 2024

निष्पक्षता का फ़ायदा

डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। पिछले चुनावों में जब बाइडन से ट्रंप हार गए थे, तब अमेरिका में मोदी ट्रंप के राजनीतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इससे तब आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने निष्पक्ष रवैया अपनाए रखा, जो मुनासिब था और यह नीति सही भी है।

दोस्ती का हवाला | 2016 से 2020 के दौरान जब डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो मोदी के साथ उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री अक्सर चर्चा में रहती थी। इन चुनावों के दौरान भी एक से अधिक मौकों पर ट्रंप ने मोदी के साथ अपनी अच्छी दोस्ती का हवाला दिया। हाल ही में जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए तो ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी उनके एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

US चुनाव में संतुलित रहा भारत

निश्चित दूरी | भारत की तरफ से इन बातों की पुष्टि नहीं की गई, न मोदी उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय हित को देखते हुए भारत ने इन चुनावों में दोनों पक्षों से निश्चित दूरी बनाए रखी। जब डेमोक्रेट बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत के लिए कुछ जरूरी टेक्नॉलजी का रास्ता खोला। इस दौरान भारत और अमेरिका में रणनीतिक सहयोग भी बढ़ा है।

परमाणु ऊर्जा करार | जब डॉ. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उनकी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की करीबी की भी काफी चर्चा होती थी। दरअसल, भारत और अमेरिका के रिश्ते दो दशक से लगातार मजबूत हुए हैं। रिपब्लिकन लीडर जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहने के दौरान भारत के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ था, जिसे मील का पत्थर माना जाता है।

निष्पक्ष और संतुलित | अमेरिका से अच्छे रिश्तों के बावजूद भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता की नीति बनाए रखी। यूक्रेन और फलस्तीन-इस्राइल युद्ध इसकी हालिया मिसालें हैं। भारत को रूस का करीबी माना जाता है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की उससे मध्यस्थता की अपील कर चुके हैं। 'यह युद्ध का दौर नहीं है', मोदी ने यह बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के सामने ही कही थी। अभी तक इस निष्पक्षता का भारत को फायदा ही मिला है। आज ग्लोबल साउथ भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक स्तर पर भारत की यह निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

साड्डी दिल्ली

बदलेगा ITO

विवेक शुक्ला

आप जब इंद्रप्रस्थ एस्टेट यानी ITO स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हाउस में जाते हैं, तो आपको एक शिलापट्ट दिखाई देता है। इस पर लिखा है कि IMA हाउस की आधारशिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 19 सितंबर, 1958 को रखी थी। अब IMA हाउस खाली कर दिया गया है। कुछ समय के बाद देश के डॉक्टरों की पसंदीदा इमारत जमींदोज हो जाएगी। पुरानी बिल्डिंग की जगह IMA की नई बिल्डिंग 2027 तक बनेगी। IMA हाउस के पुनर्विकास के साथ अब यह तय लग रहा है कि आने वाले समय में ITO स्थित अन्य इमारतों को भी री-डिवेलप किया जाएगा। इनकम टैक्स, CPWD, AGCR और UGC इमारतें सभी पुरानी हैं। ये सभी 1950 के दशक के अंत या 1960 के दशक के शुरू में बनी थीं। यहां सबसे नई इमारत हबीब रहमान द्वारा डिजाइन की गई विकास मीनार है। यह 1976 में बनी थी। यह 23 मंजिला इमारत है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण का दफ्तर है। आपको राजधानी के पुराने लोग बताएंगे कि जब विकास मीनार का उद्घाटन हुआ था, तो इसे राजधानी की सबसे ऊंची इमारत माना जाता था। यह कुतुब मीनार से भी ऊंची थी। IMA हाउस की दीवार पर डॉ. बिधान चंद्र रॉय का एक भित्ति चित्र बना हुआ है। वह पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और डॉक्टर भी थे। IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल कहते हैं कि IMA हाउस से भारत का हरेक डॉक्टर भावनात्मक रूप से जुड़ा है। हमने नई अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि IMA हाउस की हालत लगातार खराब हो रही थी।

1949 से पहले IMA का मुख्यालय कोलकाता में था। फिर तय हुआ कि यह देश की राजधानी में होना चाहिए। जब IMA दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तब आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल (1922), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (1914), AIIMS (1956), सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल (1885), LNJP (1930) दिल्ली वालों की सेवा कर रहे थे। IMA की नई बिल्डिंग का निर्माण नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) करेगी। यह 7 मंजिला इमारत होगी। हबीब रहमान ने ITO में AGCR, UGC और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भवनों को भी डिजाइन किया था। जब WHO बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, तो अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया के बहुत से जानकारों ने इसे गलत फैसला बताया था। उनका तर्क था कि यह एक उत्कृष्ट इमारत थी और इसे ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या IMA हाउस को लेकर भी सवाल खड़े होंगे? वैसे यह तय है कि ITO की सूरत बदलने जा रही।

एकदा

सुधार ली ग़लती

लखनऊ से मिर्जा रजब अली बेग 'सुरूर' दिल्ली आए हुए थे। मिर्जा रजब अली बेग वही हैं, जिन्होंने फसाना-ए-अजायब लिखा था। दिल्ली में वह गालिब से मिलने पहुंचे। दोनों में बातचीत होने लगी। रजब अली ने गालिब से पूछा, 'किस किताब की उर्दू सबसे उम्दा है?' मिर्जा गालिब बोले, 'चार दरवेश की उर्दू सबसे अच्छी है।' अब रजब अली ने पूछा, 'और फसाना-ए-अजायब की उर्दू कैसी है?' गालिब बेसाख्ता कह उठे, 'लाहौल विला कुवत। उसमें लुफ्त-ए-जुबान कहां है? बस एक तुकबंदी ही है उसमें।' तब तक मिर्जा गालिब को यह नहीं पता था कि 'सुरूर' ही उस किताब के लेखक थे। जब चले गए तो पता चला। गालिब ने बहुत अफसोस किया।

Shital Verma

दूसरे दिन गालिब गौस अली शाह कलंदर के घर पहुंचे और यह किस्सा सुनाया। बोले, 'हजरत, यह गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। आइए आज उनके घर चलें और कल की हरकत की तलाफी करें।' दोनों जब मियां रजब अली बेग के घर पहुंचे तो मिर्जा ने उनके लिखने के अंदाज का जिक्र छेड़ा। फिर बोले, 'जनाब, रात मैंने फसाना-ए-अजायब को गौर से देखा। उसकी खूबी-ए-इबारत और रंगीनी का क्या बयान करूं। निहायत ही उम्दा इबारत है। मेरे कयास में तो ऐसी उम्दा चीज ना पहले हुई, और ना आगे होगी। और कैसे हो और क्यों हो? उसका जो लेखक है, वो अपना जवाब नहीं रखता।' गर्ज यह कि अपनी खाकसारी और उनकी तारीफ करके इस किस्म की बहुत सी बातें बनाईं। दूसरे दिन उन्हें दावत भी दी। मिर्जा गालिब का मानना था कि किसी का दिल दुखाना बड़ा गुनाह है। और हकीकत में यह खयाल सच भी है।

संकलन : जमील गुलरेज

ट्रंप की वापसी से कैसे बदलेगी दुनिया

युद्ध रुकवाने का वादा पूरा करने की चुनौती, भारत से अच्छे रहेंगे रिश्ते

चंद्रभूषण

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का इतनी बेसब्री से इंतजार पहले शायद ही कभी हुआ हो, और इसकी अकेली वजह यह कि इतने लंबे समय तक दो बड़ी लड़ाइयों का बोझ बर्दाश्त करना दुनिया के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। डॉनल्ड ट्रंप की छवि एक शांतिप्रिय राजनेता जैसी कभी नहीं रही लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध जल्दी रुकवा देने के उनके चुनावी बयान से यह उम्मीद जरूर बनी कि नैटो पक्ष की ओर से इस दिशा में कुछ बात तो शुरू होगी।

क्या युद्ध रुकवाएंगे ट्रंप | दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अपने बयान से मुकर भी सकते हैं। कथनी और करनी को जोड़कर चलने की बाध्यता उन्होंने आजतक नहीं महसूस की है। लेकिन उनका जनाधार यूक्रेन के मोर्चे पर मामला ठंडा करने के पक्ष में है। विवेक रामास्वामी से लेकर इलॉन मस्क तक, कई महत्वपूर्ण रिपब्लिकन नेता और समर्थक इसकी जोरदार वकालत करते रहे हैं। लिहाजा संभावना यही है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ इस दिशा में कुछ हरकत होने लगेगी।

इस्राइल को छूट | ऐसी कोई बात दूसरी लड़ाई, यानी फलस्तीनी इलाकों और लेबनान में जारी इस्राइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर नहीं कही जा सकती। डॉनल्ड ट्रंप की नीति शुरू से इस्राइल को फलस्तीनी अरब बस्तियों पर हमले की खुली छूट देने की रही है। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने इस्राइल स्थित अमेरिकी दूतावास को वहां की राजधानी तेल अवीव से येरुशलम ले जाने का फैसला किया था, जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र के फैसले को खारिज करते हुए इस प्राचीन शहर पर पूरी तरह से इस्राइल का कब्जा घोषित करने जैसा था।

ईरान की मुश्किल | ट्रंप की वापसी का इस्राइल-फलस्तीन युद्ध पर इतना ही असर हो सकता है कि पिछले कई दिनों से ईरान की ओर से इस्राइल पर जवाबी हमले की तैयारियों की जो खबरें आ रही हैं, वे शायद गलत साबित हों और ईरान अपने इस इरादे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दे। उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़े अमेरिकी दखल के लिए तैयार रहना होगा। यूं भी ट्रंप का रुख ईरान पर अधिक सख्ती बरतने का रहा है और उनकी वापसी से इस देश को भारी समस्या हो सकती है।

चीन पर रुख | चीन से होने वाले आयात पर टैक्स की दरें बढ़ाकर उसके खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत डॉनल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दूसरे साल से ही कर दी थी। हाल के अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने इस मामले में और ज्यादा सख्ती दिखाने के संकेत दिए हैं। लेकिन चीन के प्रति जोसफ बाइडन की नीति भी ट्रंप से निरंतरता बरतने की ही रही है, लिहाजा किसी नाटकीय बदलाव की कल्पना करना कठिन है।

ट्रंप की दुविधा | चीन द्वारा अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक झटके में कोई बड़ी कटौती करने पर अमेरिका में महंगाई का मुद्दा बहुत तीखा हो जाएगा। कई चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका में बनाने पर चीनी आयात की तुलना में कई गुना महंगी हो जाती हैं। इसके बावजूद, ट्रंप को अमेरिकी बाजारों में चीन का दखल घटाना है तो इसके लिए बयानों से आगे बढ़कर उन्हें लंबी तैयारी करनी पड़ेगी।

यूरोप से टकराव | पिछले कार्यकाल में ट्रंप का सबसे तीखा टकराव यूरोप की सरकारों द्वारा रक्षा के मद में बहुत कम खर्च किए जाने को लेकर था। दरअसल, कई दशकों से वे यह मानकर चल रही थीं कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर अमेरिका पर है, जिसकी एटमी मिसाइलों और राडारों के लिए जगह मुहैया करा देने के बाद उन्हें कुछ विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान उनकी यह सोच अचानक उनके गले पड़ गई है।

भारत से रिश्ते | रही बात ट्रंप के नए कार्यकाल में भारत और अमेरिका के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों की, तो ऊपर से इसमें कोई समस्या नहीं लगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डॉनल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे निजी संबंध रहे हैं। लेकिन बाइडन ने जैसे रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत को उससे तेल आयात करने और उसका शोधन करके पेट्रो पदार्थ यूरोप और अफ्रीका को बेचकर भरपूर फायदा कमाने की छूट दी थी, उस राह पर चलने की कोई बाध्यता ट्रंप के सामने नहीं होगी।

वया पर उम्मीदें-आशंकाएं
- इस्राइल को मिल सकती है खुली छूट
- ईरान पर और कस सकता है अमेरिकी शिकंजा
- दुनिया में कम हो सकती है डॉलर की चमक

मोदी की नीति | भारत की रणनीतिक दिशा पिछले कुछ सालों से तलवार की धार पर चलते हुए विरोधी खेमों को साधे रहने की रही है। ट्रंप का मुंहफट राजनय अगले कुछ महीनों में ही इसमें कई मुश्किल उलटफेर जरूरी बना सकता है। ऐसा एक बड़ा मामला डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के प्रभुत्व से हटकर एक समानांतर ग्लोबल वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली के निर्माण का है।

डॉलर की मुश्किल | ब्रिक्स की तरफ से कुछ शुरुआती कदम इस दिशा में उठाए जा चुके हैं और अगले साल ब्राजील में इनके और जोर पकड़ने की उम्मीद है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान डॉलर से दूर जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी दी थी। लेकिन दुनिया भर में अगर डी-डॉलराइजेशन की ललक देखी जा रही है तो इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत अब विश्व-अर्थव्यवस्था की अकेली धुरी जैसी नहीं रह गई है।

आमने-सामने

AI Image

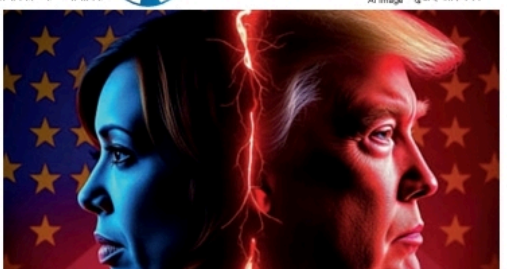

बाइडन सरकार से खफा | जो बाइडन ने पिछले चुनाव में इन 7 में से 6 राज्यों में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार पेंसिल्वेनिया में यहूदी डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर रहे, जबकि मिशिगन में 'इस्राइल-फलस्तीन युद्ध' में बाइडन प्रशासन से खफा फलस्तीनी समुदाय ने कमला हैरिस का विरोध किया। श्वेत राज्यों जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलाइना और एरिजोना में ट्रंप सहजता से जीत गए। डेमोक्रेट प्रभावित विस्कॉन्सिन में ट्रंप की जीत हैरान करने वाली रही।

भारतीयों का कैंपेन | चुनाव से कुछ रोज पहले ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। उनके बयान से अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय को बहुत सुकून मिला था। उस सुकून ने ट्रंप को कितना फायदा पहुंचाया, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वैसे जानकार बताते हैं कि अमेरिका में भले ही 1-1.5% ही भारतीय मतदाता हैं, लेकिन वे स्विंग स्टेट में उलटफेर की क्षमता रखते आए हैं। भारतीय डायस्पोरा ने शनिवार और रविवार को टोलियों में घर-घर जाकर प्रचार किया था। साथ में, टेलिफोन के जरिये भी कैंपेन चलाया गया था। परिणाम से लग रहा है कि ट्रंप का बयान काम कर गया।

ट्रंप से नाराजगी | यह अमेरिकी चुनाव नाटकीयता से भरपूर रहा। उम्र ने जो बाइडन को पीछे हटने पर मजबूर किया तो कमला हैरिस आगे आईं। ट्रंप ने हैरिस के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे यह धारणा बनी कि वह राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं। यहां तक कि ट्रंप के समर्थक परंपरावादी श्वेत समुदाय को भी उनकी नस्ल विरोधी टिप्पणी रास नहीं आई थी। कम्युनिटी ने अगले ही दिन यह नसीहत दे डाली कि ट्रंप अपनी नीतियों तक सीमित रहें।

गलत रहे सर्वे | कमला हैरिस से भी मतदाता कोई खास खुश नहीं थे। 'ए बी सी' टीवी की तीन दिन पहले जारी रिपोर्ट में कहा गया कि तीन चौथाई देशवासी ट्रंप ही नहीं, कमला हैरिस को भी राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते। हालांकि हैरिस को कड़े संघर्ष में 49-46 की बढ़त दिखाई जा रही थी। इसी तरह, न्यू यॉर्क टाइम्स और सिएना पोल सर्वे में कमला को 49-48 से बढ़त मिल रही थी। लेकिन, सट्टा मार्केट में ट्रंप आगे थे। वहां उनके पक्ष में 57 से लेकर 60% तक भाव लगा हुआ था।

हैरिस के खिलाफ एकजुटता | इसमें शक नहीं कि हैरिस के खिलाफ कंजर्वेटिव इवेंजलिस्ट और कैथोलिक ईसाई समाज एकजुट हो गया। इस कंजर्वेटिव समाज के धनाढ्य पुरुष वर्ग ने हैरिस के उन्मुक्त समाज की परिकल्पना, महिलाओं के प्रति 'ग्लास सीलिंग' और नस्लवाद के विरुद्ध डेमोक्रेटिक नजरिए को मुखरित नहीं होने दिया। हैरिस यह बखूबी जानती हैं कि उनके पक्ष में अश्वेत, लैटिन अमेरिकी, एशियन और इस्लामिक वर्ल्ड के तीन चौथाई मतों की जुटान रही। साथ ही, ग्रामीण श्वेत वोटर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चुनाव की खास बातें
- आक्रामक बयानों से ट्रंप को फायदा
- पारंपरिक समाज रहा ट्रंप के साथ
- ग्रामीण श्वेत वोटर्स के वोट अहम रहे

भारत को फायदा | ट्रंप की जीत को भारतीय नजरिये से देखें तो उनके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। दोनों की दोस्ती के आगे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को बेहद संभलकर चलना होगा। टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क पहले से ही भारत में बड़े निवेश की बात कर रहे हैं। ट्रंप के आने से मस्क के रिपब्लिकन मित्र उद्यमियों को भारत आने का मौका मिलेगा। इससे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी।

कड़ा संदेश | फ्री ट्रेड और इमिग्रेशन पर ट्रंप का कड़ा संदेश बांग्लादेश और म्यांमार तक जाएगा। ग्लोबल ऑर्डर और क्षेत्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर बात करें तो यहां भी बड़ा टकराव है। इसी वजह से अमेरिकी चुनाव पर दुनियाभर की नजर थी। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो मजबूती से अपने पांव पर खड़ा रहा है। भारत के संबंध रूस से भी उतने ही प्रगाढ़ हैं, जितने अमेरिका से। मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण भारत इस स्थिति में है।

चीन पर दबाव | अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप के चीन के साथ संबंध बहुत तनाव भरे थे। इस समय भी चीन ने ताइवान स्ट्रेट में आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। ट्रंप की वापसी जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को राहत देगी, जो चीन से पीड़ित हैं। वहीं, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देशों को कष्ट हुआ होगा। उम्मीद यह भी है कि इस्राइल-हमास जंग अब खत्म होने की ओर बढ़े। उधर, यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने में भी ट्रंप मददगार साबित हो सकते हैं।

लोकगीतों की महकती पुरवाई शारदा सिन्हा

ओमा उपाध्याय

'जगदंबा घर में दीयना बार ऐली हो', जग तारण घर में दीयना बार ऐली हो।' शायद दो-तीन साल की उम्र में किसी नवरात्रि में मैंने आकाशवाणी पर यह गीत सुना। एक मीठी खराश लिए हुए ममतामई आवाज, जिसमें देवी को ऐसे पुकारा था कि मैं हनुमान भक्त से देवी भक्त होने लगा। मेरे घर कराची से आया एक बड़ा सा रेडियो था। उसे सब पाकिस्तानी रेडियो कहते थे।

कुछ वर्षों में उस रेडियो की तकनीक समझने की नाकाम कोशिश में मैंने उसे खराब कर दिया और उसमें अपने खिलौने सजा दिए। तब तक पाकिस्तान मेरा दुश्मन भी बन चुका था। रेडियो की जगह घर में 'टू इन वन टेप रिकॉर्डर' आ गया था। पापा तब थोड़े से ही कैसेट ले आए थे (कैसेट तब महंगे होते थे)। 'आंखें, आंधी, आसपास, याराना, दोस्ताना, सिलसिला' जैसी फिल्मों के कैसेट, मुकेश का गाया 'तुलसी रामायण' का सेट, हरिओम शरण के भजन। एक भोजपुरी भजनों का कैसेट भी था, जिसकी गायिका वही थी, जिन्हें मैंने बचपन में सुना था- शारदा सिन्हा।

1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिला के 'हुलास गांव' में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। वह शुरू से मेधावी थीं। पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने में होशियार। लेकिन उनका असली आनंद तो सुरों में बसा था। रह-रह कर वह कोई न कोई गीत गुनगुनाती रहतीं। हारमोनियम पर सुर लगाती और गाती रहतीं। तब लता मंगेशकर की आवाज और अंदाज का जादू सारी दुनिया पर छा रहा था। शारदा भी उनकी दीवानी थीं। वह उनके गाने के एहसास पकड़ कर गातीं, मगर आवाज तो उनकी अपनी थी। समय के साथ साथ शारदा ने संगीत में बाकायदा अध्ययन प्रारंभ किया और लोक संगीत (भोजपुरी और मैथिली) पर शोध करके उसे संरक्षित और प्रचारित करने का संकल्प लिया।

Shital Verma
रीयर व्यू मिरर

शारदा सिन्हा का पहला सफल गीत संकलन 1976 में रिलीज हुआ। उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। उनके गीत शादी, जन्मोत्सव और दूसरे संस्कारों पर बजने लगे। उन्होंने 'नदिया के पार' जैसी सुपरहिट फिल्म के लिए गीत गाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता तो उन्हें 'मैंने प्यार किया' फिल्म के एक गीत *'कहे तोसे सजना'* से मिली। उस फिल्म में लता जी के अलावा किसी दूसरी गायिका का गाया यह अकेला गीत था। इसके बाद उन्होंने 'हम आपके हैं कौन' में बेहतरीन विदाई गीत गाया। फिर एक लंबे अंतराल के पश्चात उनकी आवाज 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के सुपरहिट गीत *'तार बिजली से पतले हमारे पिया'* में सुनाई पड़ी।

शारदा सिन्हा को भारत सरकार के कई सम्मान पद्मभूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले। इसके अलावा राज्य स्तर के और सामाजिक संस्थाओं के पुरस्कारों की तो गिनती ही नहीं। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था जनता का अगाध प्रेम और सम्मान, जो उन्हें ताउम्र मिलता रहा। भोजपुरी के फूहड़ होते दौर में शारदा सिन्हा की आवाज और गायन किसी महकती पुरवाई की भांति चलता रहा। यूं तो शारदा सिन्हा ने सभी रंगों के गीत गाए, किंतु 'सूर्य षष्ठी' के अवसर पर गाए जाने वाले 'छठी मैया' के भजनों ने उन्हें आकाश पर बिठा दिया। वास्तव में वह छठ पर्व की स्वर राजदूत बन गईं। शारदा सिन्हा की अगाध श्रद्धा छठी माता पर रही। और माता तो बच्चों की हल्की सी बिलख से जाग जाती है। फिर इस बार तो उनकी प्यारी बेटी कैंसर के दर्द से कराह रही थी। माता ने बेटी की कराह सुनी तो अपना पहला पैर धरती पर रखते ही बिटिया को गोद में उठा लिया और अंक में भर प्यार करते हुए बोलीं, 'चलो!'। शारदा सिन्हा सूर्य के पार उस संसार में चली गईं जिसके लिए कभी उन्होंने कहा था - *'भोला के देखेला बेकल भईल जीयरा'*।

वही बातें सुनें, वही कहें जो सबको सुकून देने वाली हो

निर्मल जैन

शतरंज के खेल में खिलाड़ी बोलते नहीं हैं। जब बोलते हैं तो बस 'चेकमेट' कहने के लिए। यानी जब जरूरत महसूस होती है, तब खिलाड़ी समझने भर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जीवन भी शतरंज जैसा ही खेल है। चुपचाप काम करते जाएं, अपने इरादों का खुलासा दूसरों के सामने न करें। बस अपना काम करते रहें और उपलब्धियां हासिल करते रहें। यही कामयाबी की कुंजी है। दुनिया के अन्य जीवों में मनुष्य सबसे अलग और खास है। मनुष्य के पास विचार, वचन और व्यवहार है, जो अन्य जीवों में नहीं। प्रकृति से मिले यही तीन विशेष उपहार मनुष्य की अलग पहचान बनाते हैं। वाणी की मधुरता हृदय का द्वार खोलती है। लेकिन, यही वाणी कभी-कभी संबंधों की मधुरता में जहर घोल देती है।

स्वामी विवेकानंद एक सत्संग में भगवान के नाम का महत्व बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, 'शब्दों में क्या रखा है, उन्हें रटने से क्या लाभ?' स्वामीजी ने उसकी बात सुनी और अचानक उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए अपशब्द कहने लगे। वह व्यक्ति आगबबूला हो गया और बोला, 'आप जैसे संन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, मुझे बहुत ठेस पहुंची है।' स्वामीजी ने हंसते हुए कहा, 'भाई, तुमने ही तो कहा था कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने कोई पत्थर तो मारा नहीं, जो बोला वे शब्द मात्र थे।'

इस तरह शब्द जब क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, तो प्रेम भी जगा सकते हैं। शब्द का इस्तेमाल मरहम की तरह कर सकते हैं और जख्म भी दे सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल आप किस तरह करना चाहते हैं। इसलिए जो भी बोलें, सोच-विचार कर।

झूठ और सच बोलना आपके हाथ में है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि झूठ से भी बुरा होता है आधा सच। जब तक सच को जान न लें, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। मौन वह प्रभाव छोड़ता है, जो शब्द नहीं छोड़ सकते। इसलिए शब्द भी वही सुनने लायक होते हैं, जो मौन में ले जाएं। कड़वे बोल हर कोई नहीं बोल सकता। कड़वे बोल वही बोलते हैं, जिनके वश में अपनी बोली नहीं होती है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

संसार में हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ न कुछ तो हर कोई जरूर जानता है। इसलिए सबको सुनना भी एक कला है। जो सुनना जानता है, उसी में सीखने के भी गुण होते हैं। झूठी प्रशंसा हमें राह से भटका देती है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। दूसरी ओर, आलोचना हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे ही हम प्रशंसा में छिपा झूठ और आलोचना में छिपा सच जान लेंगे, समझ लो कि अच्छे और बुरे को पहचानने की काबिलियत आ गई। सुन लेने से कितने सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर वही उलझ जाते हैं। वाणी ही एक ऐसा जरिया है, जिससे मनुष्य अपने आप को संसार से जोड़कर रखता है। लेकिन वह संसार में जितना खोता जाता है, स्वयं से दूर हटता जाता है। वाणी को विराम देकर वह स्वयं के करीब पहुंचने लगता है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अच्छे संबंध बने रहेंगे

यह पत्र 6 नवंबर को प्रकाशित लेख 'राष्ट्रपति कोई बने भारत को रहना होगा सचेत' से संबंधित है। इस बीच डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने का समाचार आ गया है। अब दुविधा के सभी बादल छंट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मेरे दोस्त के जीतने पर बधाई। ट्रंप का जीतना भारत के लिए सभी दृष्टिकोण से ठीक है। रहा सवाल आर्थिक नीतियों और आउटसोर्सिंग का, तो कोई भी राष्ट्रपति पहले अपने राष्ट्र का भला चाहेगा। ट्रंप भी यही चाहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भारत को अमेरिका से अपने संबंध और मजबूत करने में दिक्कत नहीं आएगी।

सुभाष, ईमेल से

■ हार से मिला सबक

5 नवंबर का संपादकीय 'भूलना होगा हार को' पढ़ा। खेल के मैदान में कभी हार, तो कभी जीत होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मिली हार का दुख तो है। लेकिन ऐसी हार फिर से तैयार होने के लिए मौका देती है। भारतीय टीम को अपनी कमियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। अनुभवी खिलाड़ियों को ऐसा माहौल बनाए रखना होगा कि 20-20 के चक्कर में असली खेल न भूल जाएं। भरोसा है, भारतीय टेस्ट टीम फिर से नए रूप में तैयार होगी।

मीना धानिया, सिरसपुर

■ विश्वास नहीं हुआ

मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं, इस खबर पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा। हर साल की तरह इस साल भी चारों तरफ छठ के उनके गीत बज रहे हैं। गंभीर हालत में दिल्ली के AIIMS में भर्ती होने के बाद भी उन्हें चिंता थी कि इस बार कैसे वह छठी माई को अपने गीतों का प्रसाद चढ़ा सकेंगी। शारदा सिन्हा इस त्योहार में प्रार्थना का प्रमुख स्वर बन चुकी थीं। इस स्वर कोकिला को नमन।

कल्याण कुमार, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
10 लाख नौकरियां, I.N.D.I.A. की झारखंड में गारंटी - खबर - गारंटी कितने साल की होगी, यह भी बता देते!
महेंद्र प्रधान

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 110020 में मालिकों, मुद्रक, चिकित्सा अनुज्ञप्ति के बिना संपादक व अधिपत्र पुरुषोत्तम पुरुष, प्रोपराइटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए राजीव रंजन झा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **मुद्रक अमित प्रिंटिंग लि०, भाड़ा रा०, औद्योगिक क्षेत्र नरोलाकलां** और ग्रेटर नोएडा। स्थान : 2-4, सेक्टर 24-11, ग्रेटर्स 24-11, इंडस्ट्रियल एरिया लालकुआं, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मुद्रित। फोन : 2412-2222 फैक्स : 2412-2221, मोबाइल कम्युनिकेशन : 7227027 नोएडा फोन नंबर मुद्रक : 0 से 99 अंकों में। रिकार्ड के मुद्रक : परिकल्पना से परिवहन : मेसर्स 4 क, 4 एक्सेल। मेसर्स 4 क.

संपादक (रिजनल एडीशंस) : अजीत मोहंती (इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के लिए वही उत्तरदायी हैं) पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत प्रकाशित।

चिंतन

अनुच्छेद 370 की वापसी से क्या दिखाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला

जिसका डर था वही हुआ। जम्मू-कश्मीर की नई नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जिस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआई (एम) के सदस्यों ने भी ध्वनिमत के दौरान प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। प्रस्ताव पारित होने के बाद सत्तारूढ़ एनसी ने कहा कि उसने अपने घोषणापत्र के वादों में से एक को पूरा किया है। हालांकि भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दीं। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। असल में 5 अगस्त 2019 से ही नेशनल कांफ्रेंस समेत अनेक राजनीति दल धारा 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। जबकि सरकार का कहना था कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था। कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना जरूरी था। सरकार की मानें तो अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा था और राज्य के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने में मुश्किलें आ रही थी। यह 370 का ही प्रभाव था कि बाकी राज्यों से अलग जम्मू-कश्मीर के लिए संसद को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। वहीं यहां संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास इस राज्य को लेकर कोई अधिकार नहीं रह गया था। संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इस विशेष अधिकार के चलते ही देश के अन्य राज्य का कोई नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। सरकार को लगता था कि ऐसा होने के कारण देश का यह उतरी राज्य विकास की गति में पिछड़ रहा है। इसके अलावा आतंकवाद की जड़ में भी यही विशेष अधिकार है। रोजगार के साधन न बढ़ पाने के कारण प्रदेश के युवा देश विरोधी तत्वों के बहकावे में आ रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते 5 अगस्त 2019 को संसद ने धारा 370 और ए 35 को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले का असर भी हुआ। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर पहले से काफी बदल चुका है। कश्मीर में अब अमन-शांति है। सेना पर पत्थरबाजी की घटना इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है। बाहरी लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना आसान हो गया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं अनुच्छेद 370 के समर्थकों का कहना है कि यह कश्मीर की स्वायत्तता की रक्षा करता था और राज्य के विशेष दर्जे को बनाए रखने में मदद करता था। अनुच्छेद 370 के हटने से केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसे नेशनल कांफ्रेंस ने चुनावी मुद्दा बनाया और सफलता मिलने के बाद विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर दिया। प्रश्न यह उठता है कि क्या सत्ता पाने के लिए किसी राज्य को देश से अलग करने वाले अनुच्छेद को वापस लाना जरूरी है। वैसे तो केंद्र की सहमति के बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं है फिर भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बार फिर दफन हो चुके अलगाव के बीज को कुरेद तो दिया ही है। राजनीतिक दलों को ऐसे वादों से दूर रहना चाहिए जो देश की अखंडता के लिए खतरा हों।

अमेरिकी चुनाव
विकेश कुमार बडोला

एक सदी में पुनर्निर्वाचित प्रथम व्यक्ति ट्रंप

वामपंथ के आधिपत्य वाले अधिसंख्य मीडिया संस्थानों द्वारा ट्रंप को पहली बढ़त मिलने तक भी उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के पक्ष में विजयी हवा उड़ाई जा रही थी। किंतु अंततः ट्रंप ही विजेता सिद्ध हुए। उन्होंने अपने विजयी संबोधन में ही युद्ध बंद कराने, अमेरिका में घुसपैठ पर रोक लगाने और मिलकर अमेरिका को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिये हैं। उन्हें चुनाव-पूर्व के अपने प्रचार अभियानों में लोगों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ था। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न तथा सीनेट उच्च सदन है। इस बार प्रतिनिधि सभा के लिये 435 और सीनेट के लिये 34 सीटों पर मतदान हुआ था और इन दोनों ही सदनों में बैठने के लिए रिपब्लिकन दल को बहुमत प्राप्त हुआ है।

पांच नवंबर को 119वीं कांग्रेस के गठन के लिए अमेरिका में चुनाव संपन्न हुआ और छह नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम में रिपब्लिकन प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए। अमेरिका में गत एक सदी में यह पहली बार होगा कि कोई दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहा है। यदि वैश्विक दृष्टिकोण से आकलन किया जाए तो रिपब्लिकन पार्टी का सत्तारूढ़ होना अधिक उपयोगी है। ट्रंप पर 2016 में रिपब्लिकन के राष्ट्रपति नामांकित होने से लेकर अब तक जितने भी आरोपण, दोषारोपण और अन्य लांछन लगे वे सभी विरोधियों की राजनीति से दुष्प्रेरित थे। किंतु अब वे पुनः राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका कार्यकारी संतुलन प्रशंसनीय है। आशा है कि दोनों नेता अमेरिका-भारत के संबंधों को तो प्रगाढ़ व सुदृढ़ करेंगे ही, साथ ही विश्व में शांति की स्थापना हेतु भी एकीकृत दिशादृष्टि साधकर कार्य करेंगे।

वामपंथ के आधिपत्य वाले अधिसंख्य मीडिया संस्थानों द्वारा ट्रंप को पहली बढ़त मिलने तक भी उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के पक्ष में विजयी हवा उड़ाई जा रही थी। किंतु अंततः ट्रंप ही विजेता सिद्ध हुए। उन्होंने अपने विजयी संबोधन में ही युद्ध बंद कराने, अमेरिका में घुसपैठ पर रोक लगाने और मिलकर अमेरिका को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिये हैं। उन्हें चुनाव-पूर्व के अपने प्रचार अभियानों में लोगों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ था। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न तथा सीनेट उच्च सदन है। इस बार प्रतिनिधि सभा के लिये 435 और सीनेट के लिये 34 सीटों पर मतदान हुआ था और इन दोनों ही सदनों में बैठने के लिए रिपब्लिकन दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। मतदान की समयावधि में ही अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने एक वक्तव्य द्वारा अमेरिकी लोकतंत्र और चुनाव की पारदर्शिता व उपयुक्तता के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े कर दिये थे। उनके अनुसार, यदि रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप चुनाव में विजयी नहीं हुए तो यह अमेरिका का अंतिम चुनाव होगा। एलन मस्क साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हताशा-निराशा से युक्त उनका यह कथन अमेरिकी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में डेमोक्रेटिक दल की अनुचित तथा अमेरिका व विश्वविरोधी शासकीय-प्रशासकीय क्रियाकलापों की ओर ही संकेत करता है। इससे ज्ञात होता है कि डेमोक्रेट्स की दलगत नीतियां वास्तव में अमेरिकियों और अमेरिका के व्यापक हित में न होकर अपने नेताओं के अस्त्रों के व्यापार-व्यवसाय के लिए दुनिया को युद्धक्षेत्र में बदलने पर अधिक केंद्रित रही हैं। यदि ऐसा न होता तो 2020 में सत्तारूढ़ होते ही डेमोक्रेटिक नेताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों और भूभागों को परस्पर युद्ध में लिप्त करने की कूटनीतियां न बनाई होतीं। इनका दुष्परिणाम, एक ओर रूस और यूक्रेन के मध्य तो दूसरी ओर इजरायल और फिलीस्तीन व अन्य मध्य पूर्वी मुस्लिम देशों के मध्य दो-ढाई वर्षों से निरंतर हो रहे युद्धों के रूप में सम्मुख है। इतना ही नहीं दुनिया में डीप स्टेट अर्थात गुप्त क्रूर शासकों द्वारा जो भी विद्रोहजन्य, विध्वंशजनित एवं हिंसाजन्य हस्तक्षेप किया जाता रहा है वह डेमोक्रेट्स जैसे शासकों के साथ मिलकर ही किया जाता रहा है।

डेमोक्रेटिक की विगत चार वर्षीय शासनगत गतिविधियों की तुलना यदि रिपब्लिकन के 2016-2020

के कार्यकाल से करें तो तुलनापरक अध्ययन में आश्चर्यचकित करनेवाले अंतर दिखाई देंगे। संपूर्ण विश्व में राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक संतुलन बनाये रखने के विषय में ट्रंप का शासनकाल अत्यधिक उपयोगी रहा था। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में चार वर्षों से भी कम समयावधि में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की ओर से अनेक सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अराजकता व आतंकग्रस्तता के नियंत्रण में सैन्यव्यवस्त अपनी सेना को वहां से वापस बुलाने का निर्णय लिया, जो अमेरिकी सैन्यकर्मियों के लिए बड़ा राहत भरा निर्णय था। उनके द्वारा उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के नाभिकीय-आण्विक अस्त्रों के अवैध व घातक परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से उसके साथ दो-दो शांतिवार्तायें करना अप्रत्याशित घटनायें थीं। चीन के साथ चहुंदिशा पारस्परिक संबंधों के शक्तिवंधन के लिए उनका चीन की आधिकारिक यात्रा करना भी तात्कालिक वैश्विक परिदृश्य में अद्वितीय कार्य था। अमेरिका और भारत में अनेक अवसरों पर द्विपक्षीय संबंधों को सच्चे अर्थों में प्रगाढ़ करने हेतु पारंपरिक ऊर्जस्वित होकर पारस्परिक और वैश्विक विषयों पर सार्थक वार्ता करना भी ट्रंप के विशिष्ट निर्णयों में से एक था। उन्होंने उसी इजरायल और फिलीस्तीन व अन्य मध्य पूर्वी मुस्लिम देशों के मध्य शांति वार्ता करने की युक्तियां भी कीं, जो गत दो-ढाई वर्षों से पारस्परिक युद्ध में खपे हुए हैं। उन्होंने अरब क्षेत्र के मुस्लिम देशों और मध्यपूर्वी दूसरे मुस्लिम देशों के मध्य भी शांति स्थापनार्थ अनेक नवीन नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिसके प्रभाव में वैश्विक स्तर पर किन्हीं दो देशों के मध्य संभावित युद्ध होने की आशंकायें समाप्त होती गईं।

हालांकि, अमेरिका और विश्व में स्थित ट्रंप के विरोधियों को दुनिया की इन उपलब्धियों को स्वीकार करने में अत्यंत कष्ट हो रहा था। वास्तव में, विरोधियों के भेष में अमेरिका से लेकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए ऐसे चरमपंथियों, वामपंथियों और मानवता के शत्रुओं को ट्रंप की शांति योजनायें, अशांति फैलाकर धन-संसाधन अर्जित करने के अपने-अपने अभियानों में बड़ा रोड़ा प्रतीत हो रही थीं उन्हें ट्रंप के राष्ट्रपति रहते-रहते अमेरिका के नेतृत्व में निरस्त्रीकरण की एक आचरण सम्मत पहल होती दिखने लगी थी, जो उनके अस्त्र निर्माण उद्योगों के समक्ष अप्रत्याशित चुनौती बन गई थी। आज अमेरिका सहित विश्व के लोकतांत्रिक देशों में जो भी लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां हैं- चाहे वे आतंकवाद, अस्त्रीकरण, अलगाववाद, अवैध व्यापार, मादक पदार्थों के अवैध गुप्त धंधों, देशों की भौगोलिक सीमाओं के अनुचित अतिक्रमण के रूप में हों- सभी पर अपेक्षित कार्यकारी क्षमताओं के साथ प्रभावी प्रतिबंध लगाने में ट्रंप ने श्रेष्ठ भूमिका निभायी थी। इसीलिये वे अमेरिका सहित विश्व के बड़े-बड़े माफियाओं (डीप स्टेट्स) को बुरी तरह खटक रहे थे और अंततः अमेरिका स्थित उनके राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर माफियाओं ने उन्हें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में षड्यंत्रपूर्वक पराजित करवाने में कोई अवसर नहीं गंवाया। ट्रंप पराजित हुए और जो. बाइडेन राष्ट्रपति बन गये, जो अस्त्र निर्माताओं और उद्योगपतियों के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि कोरोना महामारी के सिमटने के बाद इन निर्माताओं और उद्योगपतियों के अस्त्र इजरायल-फिलीस्तीन तथा रूस-यूक्रेन के उन युद्धों में काम आ रहे हैं जो षड्यंत्रपूर्वक अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने ही नियोजित किए हैं। अमेरिका में चुनाव के प्राथमिक और जनरुचि के विषयों में अमेरिकी नागरिक होने की स्वायत्तता, राष्ट्र की स्वायत्तता की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मूल अमेरिकियों के हितों के दृष्टिगत संरक्षा जैसे विषय सम्मिलित थे।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

कूटनीति

डॉ. एन.के. सोमानी

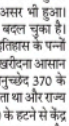

ट्रंप के सामने अर्थव्यवस्था सुधारने की होगी चुनौती

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे प्राचीन लोकतंत्र अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की बागडोर अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 131 साल के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी पूर्व राष्ट्रपति ने एक बार चुनाव हारने के बाद फिर से सत्ता में वापसी की है। इससे पहले 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड ऐसे पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ट्रंप को जानने वालों का कहना है कि ट्रंप जीतने के लिए ही मैदान में उतरे थे और अतंतः वे जीते भी। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में जब वे चुनाव मैदान में उतरे थे तो बहुत कम लोगों को यह अनुमान था कि वे बाइडन की पार्टी को सत्ता से रुखसत करने में सफल हो सकेंगे। अर्थव्यवस्था में सुधार का वादा, आव्रजन नीति, यूक्रेन युद्ध, इजरायल संघर्ष, ट्रेडवॉर आदि मुद्दों ने ट्रंप के लिए बढ़त का काम किया। अर्थव्यवस्था और आव्रजन के मुद्दे पर 'स्विंग स्टेटस' के मतदाताओं ने ट्रंप पर भरोसा जताया और खुलकर उनके पक्ष में वोट दिए। हालांकि, कमला ने गर्भपात अधिकार और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा वादा किया था। अमेरिकी लोकतंत्र का भविष्य भी इस दफा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। सर्वेक्षण में आधे से ज्यादा मतदाताओं का मानना था कि ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन तमाम धारणाओं के बावजूद ट्रंप दूसरी दफा व्हाइट पहुंचने में सफल रहे। चुनाव में धर्म की एंट्री भी हुई। ट्रंप ने बड़ी चतुराई से बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर भारतीय वोटरों को साधने की कोशिश की। हिन्दू हितों वाला उनका बयान काफी असरकार सिद्ध हुआ। चुनाव में ट्रंप का यह सबसे बड़ा सियासी दांव साबित हुआ। हालांकि, कमला ने भी भारतीय मूल के लोगों को लुभाने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अप्रवासियों के लिए आसान नीतियां बनाने, भारतीय कामगारों और विद्यार्थियों के लिए अमरीकी दरवाजे खोलने व वीजा नियमों को आसान बनाने का वादा किया। सवाल यह है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दुनिया के प्रति अमेरिका का नजरिया क्या रहेगा। जिस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात दुनिया के अलग-अलग कोनों में की जा रही है, क्या उसके स्वरूप में कोई बदलाव आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पूर्ववर्ती रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों द्वारा स्थापित परंपरा पर ही आगे बढ़ते हुए दिखें। सवाल भारत को लेकर भी है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बेहतर कैमिस्ट्री है। वह अक्सर मोदी के साथ अपनी मित्रता की चर्चा करते हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान भी भारत-अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। पर ध्यान रहे कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। वह हमेशा अपने राष्ट्रहितों को ध्यान में रखता है। ऐसे में भारत को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हिंद प्रशांत और उसके बाहर चीन के सैन्य और आर्थिक विस्तार को रोकना अमेरिका का घोषित लक्ष्य है। ट्रंप भारत को तभी तक महत्व देंगे, जब तक उन्हें लगता है कि एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक 'बड़ी जरूरत' साबित हो सकता है। इसलिए जब तक चीन के साथ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा रहेगी, तब तक ट्रंप ही नहीं कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ संबंध कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन ट्रंप की व्यापार संतुलन व आव्रजन की नीति भारत को परेशान कर सकती है। अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रंप ऐसी व्यापार नीतियों को लागू करना चाहेंगे जो साफतौर पर अमेरिका केंद्रित होंगी। वे भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डाल सकते हैं। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। आयात शुल्क के मामले में वह भारत को दोहन करने वाला राष्ट्र बता चुके हैं। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। वहीं, भारत ने अमेरिका में तकरीबन 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर दबाव बनाएंगे। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी व्यापार और करों को लेकर भारत-अमेरिकी संबंधों में टकराव की स्थिति बनी थी। सच तो यह है कि आज भारत-अमेरिकी रिश्ते जिस मुकाम पर हैं, वहां राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी भारत-अमेरिकी संबंधों को नकारना आसान नहीं होगा।

(लेखक शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हमें वैराग लेकर भगवान को नहीं पाना है

संकलित
दर्शन

परिवार में कोई बीमार हो तो दूसरे व्यक्ति के शरीर पर भी असर होता है। अगर बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, अच्छा लड़का या लड़की नहीं मिली है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए हैं तो इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हमें वैराग लेकर भगवान को नहीं पाना है। बल्कि हम जहां हैं, वहां रहकर भगवान के ऊपर से नीचे उतारना है। भगवान उतरते हैं। दशरथ के घर उतरे हैं, वासुदेव की जेल में उतरे हैं। हम वैराग लेकर उन्हें ऊपर खोजने जाएं, यह भी एक गति है, लेकिन क्यों न हम एक एक पारिवारिक दायित्व पूरा करते-करते उन्हें नीचे बुला लें। हम नरसिंह मेहता नहीं है। हम मीरा और भर्तृहरि नहीं हैं। मनु और शतरूपा ने वैराग का पथ लिया तो भी परिवारिक दायित्व को पूरा किया। भजन का मतलब यह नहीं कि आप सबको नजरअंदाज करें, सबकी उपेक्षा करें। भजन में पारिवारिक स्वास्थ्य आवश्यक है। आत्मा की तंदुरुस्ती के विषय में मैं खुलासा कर दूं कि आत्मा बीमार नही है। मन बीमार हो सकता है, आत्मा कहां बीमार होती है। जैसे सूरज तंदुरुस्त है, लेकिन बादल से आवृत्त होने पर सूरज दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही स्थिति हमारी आत्मा की है। जैन परंपरा कहती है कि आत्मा पर कई तरह के कशाय के बादल छा जाते हैं। इसी रूप में आत्मा अस्वस्थ नहीं हो सकती। आत्मा बूढ़ी नहीं हो सकती। शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। ये तो सीधी-सी बात है।

क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे?

संकलित
प्रेरणा

आठ साल का एक बच्चा एक रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहाः क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे?दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा! लेकिन, उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल चालीस दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछाः तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दियाः इस दुनिया में मां के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी मां दिनभर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अब अस्पताल में हैं। अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा ? डाक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदारः हां, मिलेंगे! कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चाः सिर्फ एक रुपए। बच्चे की मां का अप्रिशन हुआ। और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठीं। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहाः टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी, उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है.. मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं।

अंतर्मन

आज की पाती

स्वदेशी को बढ़ावा देशहित में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर दिखते हैं, जोकि देश के कारोबारियों के लिए भी अच्छे दिनों के लिए शुभ संकेत है। मेक इन इंडिया सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया होता था, लेकिन पहले इसे मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने देश की धन-संपत्ति को विदेशों में ले गए। हमारे विदेशी वस्तुओं के मोह के कारण देश आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ाने की बात कहते हैं। इससे यह उम्मीद की किरण नजर आई कि हमारे देश में इससे विदेशी मुद्रा आएगी, जो देश की आर्थिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। देश के लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमारे देश के उत्पाद विदेशी मंडियों की शान बनकर विदेशियों तक पहुंच रहे हैं।

– जगदीश साहू, बलौदाबाजार

ट्रेंड

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

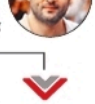

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हुए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से 22 लाख से अधिक छात्रों को अब शीर्ष संस्थानों के लिए सार्वजनिक-सुलभ, वस्तुतः-सुलभ शिक्षा ऋण तक पहुंच प्राप्त होगी।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम उप्र

गायिका शारदा को नमन

अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुःखद है। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

प्रगतिशील नीति

वह समय परमाणु ऊर्जा था है। हमें हर समय स्वच्छ ऊर्जा के लिए इंतजार आवश्यकता है। सरकार एक प्रगतिशील नीति की घोषणा कर सकता है जो निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी।

-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

न्यूकमर की एक्साइटमेंट

40 साल फिल्मों में काम करने के बाद भी अगर एक्साइटमेंट एक न्यूकमर की हो तो इसका मतलब है आपके अंदर का छोटे शहर का लड़का अभी जिंदा है। लगा आ नया ग्रुप बीच पर आपने आने वाली फिल्म डिनर 69 का बड़ा बैनर देखाकर।

-अनुपम खेर, अभिनेता

करंट अफेयर

लाहौर में वायु प्रदूषण से हजारों लोग बीमार पड़े

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण हजारों लोगों को अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने आगाह किया है कि अगर लोगों ने मास्क लगाने समेत अन्य निर्देशों का पालन नहीं किया तो पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यह चेतावनी तब दी गई जब लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते नजर आए। डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादातर लोगों को खांसी तथा आंखों में जलन की शिकायत है। पाक मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सलमान काज़मी ने कहा, "पिछले एक हफ्ते में श्वास संबंधी परेशानी से जूझ रहे हजारों लोगों का अस्पतालों और क्लीनिक में इलाज किया गया। उन्होंने कहा, आप लोगों को खांसते देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वे मास्क नहीं लगाते हैं। बुधवार सुबह लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक 1,100 के आंकड़े को पार कर गया। 300 से ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। जहरीले 'स्मोग' ने पिछले महीने से शहर को अपनी चपेट में लिया हुआ है। पंजाब प्रांत की वरिष्ठ मंत्री मरयम औरंगजेब ने शहर में पूर्ण लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है।

ऑफ बीट

आनुवांशिक जानकारी से जान सकते हैं बहुत कुछ

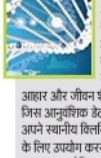

कई वैज्ञानिक शोध अध्ययन एक विशिष्ट शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा एकत्र करते है। उदाहरण के लिए, मधुमेह की आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए, शोधकर्ता आनुवंशिक डेटा के अलावा आपके रक्तचाप और लिपिड स्तर पर डेटा एकत्र कर सकते हैं। वैज्ञानिक बायोबैंक में रखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र कर रहे हैं – ऐसे भंडार जो आनुवंशिक डेटा और रक्त, मूत्र या टूथ्रूस ऊतक जैसे अन्य जैव नमूनों को भविष्य के अध्ययनों की एक विस्तृत संख्या में उपयोग करने के लिए संग्रहीत करते हैं। कुछ बायोबैंक, जैसे यूके बायोबैंक, बायोस्पेसिमेन डेटा को अन्य एकत्रित डेटा, जैसे यौन व्यवहार, चिकित्सा इतिहास, वजन, आहार और जीवन शैली से जोड़ते हैं। ये अवसर आश्चर्यचकित होते हैं कि जिस आनुवंशिक डेटा को उन्होंने डीएनए परीक्षण किट का उपयोग करके या अपने स्थानीय क्लिनिक का दौरा करते समय एक निजी कंपनी में अनुसंधान के लिए उपयोग करने की सहमति दी थी, उसका उपयोग समलैंगिक यौन व्यवहार या जोखिम के आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। बायोबैंक डेटा के साथ जो शोध किया जा सकता है वह डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

सम्पादकीय

इंटरनेट की दुनिया का श्रम तथ्य के रूप में प्रयोग करने पर लग सकते हैं चोरी के आरोप

इंटरनेट का चलन शुरू होने के बाद ज्ञान और विमर्श की दुनिया काफी सहज और विस्तृत हो गई थी। कहा गया कि यह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय के रूप में काम करेगा। यहां तमाम सूचनाएं, अध्ययन, विचार-विमर्श, ज्ञानात्मक सामग्री एक बटन दबाने भर से उपलब्ध हो जाएंगे। निस्संदेह ऐसा हुआ भी। मगर जिस तरह सूचनाओं का आदान-प्रदान एक बड़े व्यवसाय के रूप में आकार लेता गया, उसमें नकल और चोरी बढ़नी शुरू हो गई। भ्रामक, आधी-अधूरी, भड़काऊ, उत्तेजना पैदा करने वाली जानकारियों की भरमार होती गई। इंटरनेट पर विकिपीडिया नामक मंच इसी मकसद से शुरू किया गया था कि वहां व्यक्तियों, घटनाओं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों आदि से संबंधित तमाम जानकारियां एक जगह उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस मकसद में यह मंच काफी सफल भी हुआ।

मगर चूंकि इसे एक खुले मंच के तौर पर विकसित किया गया है, कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ कर वहां उपलब्ध सामग्री को संपादित कर सकता है। उसके गलत तथ्यों को दुरुस्त कर या नए तथ्य जोड़ सकता है, इसमें मनमानी के अवसर अधिक हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारधारात्मक दुराग्रहों के चलते तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उन्हें तोड़-मरोड़ कर या भ्रामक ढंग से पेश कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। चूंकि बहुत सारे लोग पुस्तकालयों की खाक छानने, मूल पुस्तकों या दस्तावेजों को खंगालने के बजाय विकिपीडिया जैसे इंटरनेट माध्यमों को सुगम मानने लगे हैं, वे वहां मौजूद भ्रामक और गलत जानकारियों को सही मान कर तथ्य रूप में पेश करते देखे जाते हैं। इससे कई बार विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष वकीलों को स्पष्ट हिदायत दी थी कि वे कानूनों का हवाला देने के मामले में विकिपीडिया पर निर्भर न रहें, मूल स्रोतों का ही उपयोग करें। तब भी विकिपीडिया की जवाबदेही रेखांकित हुई थी। अब केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया को पत्र लिख कर पूछा है कि आपको क्यों न सूचना प्रदाता मंच के बजाय एक प्रकाशक माना जाए। देखना है, विकिपीडिया इस पर क्या जवाब देता है। पर हकीकत यही है कि विकिपीडिया अपने स्वरूप में एक प्रकाशक की तरह ही काम करता है। प्रकाशक को सूचना और बौद्धिक संपदा से जुड़े कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस तरह वह अपने किसी भी प्रकाशन के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह होता है। विकिपीडिया उन जवाबदेहियों से मुक्त है। कोई भी ऐसा मंच, जो ज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करता है, उसे इस तरह मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता कि वह तथ्यों का मनमाना उपयोग करे। विकिपीडिया का सर्वाधिक उपयोग विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध संस्थानों आदि से संबद्ध लोग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए विकिपीडिया एक संदर्भ कोश की तरह उपलब्ध है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर लोग गलत तथ्यों का उपयोग करते होंगे तो आने वाली कितनी पीढ़ियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता होगा।

अमेरिका चुनावी महासंग्राम : आम जनता द्वारा इलेक्टर्स को मतदान की प्रक्रिया, पूरी 17 दिसंबर को 538 इलेक्टर्स चुनेंगे राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया को समझने की करें तो,अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही कई क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग पूरी होने पर पॉपुलर वोट (जनता केवोट) के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पाने वालाउम्मीदवार राष्ट्रपति बने। असल में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव पॉपुलर वोट के बजाय इलेक्टोरलकॉलेज द्वारा तय होता है। इसके अलावा, यह भी संभव है कि किसी राज्य में विजेता का अनुमान लगाया जा रहा हो, जबकि दूसरे राज्यों में अभी वोटिंग जारी हो।

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर कई महीनों से पूरी दुनियाँ की नज़रें 5 नवंबर 2024 को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लगी हुई थी जो मतदान प्रक्रिया भारतीय समय अनुसार बुधवार दिनांक 6 नवंबर 2024 को सुबह 6 पूरी हुई जिसमें मतदाताओं द्वारा प्रक्रिया अनुसार 50 राज्यों व कोलंबिया के 538 इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को जनता ने मतदान किया।अब गेंद इन इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के पाले में आ गई है कि ट्रंप को चुनना है या कमला हैरिस को जीत का सहारा पहनना है, जो दुनियाँ के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछली बार ट्रंप को इस वोटिंग में 28 लाख वोट कम मिले थे फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज में उसे 270 से अधिक वोट मिलने के कारण हिलेरी क्लिंटन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।यानें बता दें कि 2016 में, हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से करीब 28 लाख अधिक डायरेक्ट पापुलर वोट हासिल किए थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2000 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल गोर को हराया। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार गोर ने पांच लाख से अधिक मतों से पापुलर वोट जीता था। राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए इलेक्टर्स दिसंबर के मध्य में अपने- अपने राज्यों में बैठक करते हैं। यह बैठक दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद पहले मंगलवार को होती है, जो इस साल 17 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। यह भी दिलचस्प है कि अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है जो निर्वाचकों को उसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए बाध्य करेजिसके प्रति वो वचनबद्ध हैं। इन्हें फेथफुल इलेक्टर कहा जाता है और माना जाता है ये उसी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे जिसके लिए उन्होंने शपथ ली है। इन निर्वाचकों का चयन पार्टियां ही करती हैं, अब वोटो की गिनती जारी है जिसका रिजल्ट शीघ्र आएगा परंतु चूँकि आम जनता में वोट कर दिया है, अब 17 दिसंबर 2024 कोइलेक्टोरल कॉलेज से जिनको 270 पार वोट मिलेंगे वही अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,डोनाल्ड ट्रंप व कमला हैरिस में कांटे की टक्कर 538 सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज करेगा फैसला।

इस प्रक्रिया के चलते सटीक नतीजे आने में एक-दो दिन का समय लग सकता है।दिसंबर में इलेक्टर्स की वोटिंग के बाद 25 दिसंबर तक सभी इलेक्टोरल सर्टिफिकेट सीनेट के प्रेसिडेंट को सौंप दिए जाएंगे,इसके बाद, 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टर्स के वोटों की गिनती होगी। उसी दिन, उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस सदन में आधिकारिक रूप से विजेता के नाम की घोषणा करेंगी।अभी 538 चुनावी प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ हैं वह 538 लोग मिलकर के राष्ट्रपति चुनाव का निर्धारण करेंगे 270 वोट जिसको मिलेंगे वह राष्ट्रपति बनेगा।5 नवंबर को यानें भारतीय समय अनुसार बुधवार दिनांक 6 नवंबर 2024 सुबह 6 बजे तक हुए मतदान के बाद नतीजों में कुछ दिन का समय लग सकता है।यूएस में चुनाव पहले हो जाता है जबकि विजेता उम्मीदवार चार्ज जनवरी 2025 से ही संभालेगा।नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा,यह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सबसे जटिल चरण है इलेक्टोरल कॉलेज दरअसल वह निकाय है,जोराष्ट्रपति को चुनता है, इसे आसान भाषा में कुछ यूं समझिए कि आम जनता राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे लोगों को वोट देती है जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम वोट देना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना है।नवंबर के पहले सप्ताह में मंगलवार को वोटिंग उन मतदाताओं के लिए हुई है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ये लोग इलेक्टर्स कहलाते हैं, ये इलेक्टर्स निर्वाचित होने के बाद 17 दिसंबर को अपने-अपने राज्य में एक जगह इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, यानें जो अमेरिकी जनता में जो वोट किया है वो सीधे तौर पर स्वयं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव नहीं कर रहा। ठीक ऐसा ही नियम उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है।जो इलेक्ट्रोल सभी 50 राज्यों और कोलंबिया जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य में तीन से 54 के बीच चुनावी वोट हैं। किसी भी राज्य के निर्वाचकों की संख्या उसके अमेरिकीसीनेटरों और अमेरिकी प्रतिनिधियों की कुल संख्या को जोड़कर निर्धारित की जाती है।अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जिसमें सभी राज्यों के नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ सदस्यों के लिए वोट करते हैं। इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है, ये इलेक्टर्स इसके बाद प्रत्यक्ष वोट डालते हैं जिन्हें इलेक्टोरल वोट कहा जाता है।डीसी से अलग इन 535 इलेक्टोरल वोट को समझें तो अमेरिकी संसद की कुल सीटों संख्या 535 है जिनमें से 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (एचओआर) और 100 सीनेट के सदस्य हैं। भारत के उदाहरण से समझें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य निचले सदन लोकसभा के सांसद जबकि उच्च सदन सीनेट के सदस्य या सीनेटर राज्यसभा सांसद हुए। नियमों के मुताबिक, हर राज्य में कम से कम एक या अधिक से अधिक आबादी के अनुसार एचओआर होंगे, जबकि सीनेटर हर राज्य से दो ही होंगे। यानी चुनाव में हर राज्य से कम से कम तीन इलेक्टोरल वोट तो होंगे ही। वोट देने के लिए बाध्य करें जिसके प्रति वो वचनबद्ध हैं। इन्हें फेथफुल इलेक्टर कहा जाता है और माना जाता है ये उसी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे जिसके लिए उन्होंने शपथ ली है। इन निर्वाचकों का चयन पार्टियां ही करती हैं।

साथियों बात अगर हम 7 स्विंग स्टेट्स को समझने की करें तो,क्या होते हैं स्विंग स्टेट्स?जो बदल देते हैंअमेरिकी चुनावके समीकरणअमेरिकी चुनाव में अधिकतर राज्य किसी एक पार्टी या के उम्मीदवार की ओर झुके हैं, लेकिन यहां ऐसे करीब सात राज्य हैं जहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है, यानी इन राज्यों में इस बात काअंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि चुनाव में कौन बाजी मारेगा, अमेरिका में ऐसे राज्यों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। राजनीतिक चाणक्यों की मानें तो ये राज्य चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में अमेरिका स्विंग स्टेट्स काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दरअसल 7 राज्यों में कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं. इन स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया (19 इलेक्टोरल कॉलेज), नॉर्थ कैरोलिना (16 इलेक्टोरल कॉलेज), जॉर्जिया (16 इलेक्टोरल कॉलेज), मिशिगन (15 इलेक्टोरल कॉलेज), एरिजोना (11 इलेक्टोरल कॉलेज), विस्कॉन्सिन (10 इलेक्टोरल कॉलेज) और नेवादा (6 इलेक्टोरल कॉलेज) शामिल हैं। साथियों बात अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 की बड़ी बातों को समझने की करें तो,अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आज वोट डाले गए अमेरिका के 26 करोड़ मतदाता नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे।अमेरिका का राष्ट्रपति7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर कर चुके हैं। प्री-पोल मतदान 26 लाख भारतीय मूल के वोटर्स भी वोटिंग किया कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिलाकमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे है।

आज का राशिफल

सबसे अनुकूली व्यक्तियों की टीम के अनुसार आज कई विशिष्ट लक्षणों को पूरा करेंगे। तय आज एक सकता पाएंगे है कि आपके जीवन के ऐसे सौभाग्ये क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरों तरफ, आपको रिश्ता बनाने में लाभकारी साबित पाएंगे। हल ने सिंहों तरफों दखल में और अर्जित पूर्ण को सुगमता पाया लाभकारक अंकों को समझना होगे, क्योंकि पारमार्थिक संकेतों में भी, जहां तक लाभकारक सही सलाह और कार्यों में तथा प्रदान होगे

मेष
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। खट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी।

वृष
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा।

मिथुन
यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी प्रावधानों व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। झंझटों में न पड़ें। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

कर्क
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें। लेन-देन में लापरवाही न करें।

सिंह
विवाद से क्लेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे।

कन्या
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी। शारीरिक कष्ट संभव है।

तुला
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

वृश्चिक
दुश्मन हानि पहुंचा सकते हैं। झंझटों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

धनु
आय में निश्चितता रहेगी। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

मकर
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

कुंभ
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा।

मीन
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। फालतू बातों पर ध्यान न दें।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री ओपी सहारण साहब। 29 जनवरी सन 1970 में हनुमानगढ़ जिले में जन्में सहारण आज अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली ;कोटपूतली-बहरोड़ के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ में अपनी सेवाए दे चुके हैं। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़, जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण अलवर।अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर।उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर।उपखण्ड अधिकारी थोरीमन्ना बाड़मेर।उपखण्ड अधिकारी चाकसू जयपुर,।उपखण्ड अधिकारी पीलपुर।उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला बीकानेर।उपखण्ड अधिकारी रायसिंह नगर श्रीगंगानगर।उप रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग, जयपुर। उप रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग,आमेर जयपुर।उप रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग, जयपुर,उप रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग, जयपुर। तहसीलदार किशनगढ़बास, मुंडावर, अलवर,तहसीलदार अलवर,तहसीलदार जेडीए जयपुर, तहसीलदार जयपुर नागम निगम जयपुर।नायब तहसीलदार अलवर, नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ में अपनी सेवाए दे चुके हैं। बेहद संवेदनशील अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। सबसे मिलकर चलना इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

ओम प्रकाश सहारण
(एडीएम कोटपूतली बहरोड़)

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

7 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मौत।
- बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में बंगाल के कांतल पाड़ा नामक गाँव में वन्दे मातरम् गीत की रचना की थी।
- फ्रैंक्लिन डी रूज़वेल्ट 1944 में चौथी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए।
- जार्डन में 1951 में संविधान पारित किया गया।
- तत्कालीन सोवियत संघ ने 1968 में परमाणु परीक्षण किया।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की।
- राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने 2003 में श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा वापस ली।
- भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फ़ंड बनाने पर 2006 में सहमत हुए।
- बिहार के जनतादल (यूनाइटेड) के लोकसभा सदस्यों ने 2008 में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
- कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ग्वाटेमाला में 2012 में आये भूकंप से, 52 की मौत।

7 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता पंडित विश्वंभर नाथ का जन्म 1832 में हुआ।
- अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 को हुआ था।
- विख्यात भौतिकविद और रसायनशास्त्री मेरी क्यूरी का जन्म 1867 को हुआ था।
- वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 1888 को हुआ था।
- प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद एन.जी. रंगा का जन्म 1900 को हुआ था।
- प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 को हुआ था।
- दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के सुपर स्टार भारतीय अभिनेता कमल हसन का जन्म 1954 को हुआ था।

7 नवंबर को हुए निधन

- मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का 1862 में निधन।
- भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भक्त अश्विनी कुमार दत्त का 1923 में निधन।
- भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक जीवराज मेहता का 1978 में निधन।
- भारत में हरित क्रांति के जनक सी. सुब्रह्मण्यम का 2000 में निधन।
- पद्म भूषण से सम्मानित भारत की समाज सेविका तारा चेरियन का 2000 में निधन।

विशेष आलेख

निजी सम्पत्ति अधिग्रहण पर राह दिखाने वाला फैसला

ललित गर्ग।

सुप्रीम कोर्ट ने हर निजी सम्पत्ति पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती वाला राह दिखाने वाला फैसला देकर जहां निजी सम्पत्ति धारकों के अधिकारों की रक्षा की है, वहीं आर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति देने के धरातल को मजबूत बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जाहिर किया है कि निजी संपत्ति के भी अपने अधिकार हैं, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। अब सरकारों यानी नीति निर्माताओं को भूमि अधिग्रहण और अन्य निजी संपत्ति अधिग्रहण करने के लिए अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी रूपरेखा बनानी होगी। नया फैसला अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और आदर्श शासन एवं न्याय व्यवस्था का द्योतक है। यह फैसला केवल इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि यह नौ सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से दिया गया, बल्कि इसलिए भी अनूठा है, क्योंकि इसने उस समाजवादी विचार को आईना दिखाया, जिसे सरकारों की नीति-नीति का अनिवार्य अंग बनाने का दबाव रहता था। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन समाजवादी और बाबाओं सीध वालों के लिए भी झटका है, जो यह महीन बनाने में लगे हुए थे कि देश में गरीबी और असमानता तभी दूर हो सकती है, जब सरकार संपत्ति का पुनर्वितरण करने में सक्षम हो और उसे यह अधिकार मिले कि वह किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ताजा फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोर्ट ने कहा कि किसी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के योग्य मानने के पहले उसे कुछ कठोर परीक्षणों को पूरा करना होगा। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत आने वाले संसाधन के बारे में जांच कुछ विशेष चीजों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें संसाधनों की प्रकृति, विशेषतएं, समुदाय की भलाई पर संसाधन का प्रभाव, संसाधनों की कमी तथा ऐसे संसाधनों के निजी हाथों में केंद्रित होने के परिणाम जैसे कारक हो सकते हैं। इसके लिये पहचान एवं परीक्षण आपेक्षित होगी। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत भी उन संसाधनों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में आते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत में भूमि अधिग्रहण अक्सर विवादास्पद रहा है, जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर अधिग्रहण से महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे मामलों ने सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ भूमि मालिकों और किसानों के प्रतिरोध को उजागर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी संपत्ति का अधिकार एक मानवाधिकार माना जाता है। इसलिये राज्य के लिये किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट कर न केवल जनहित की रक्षा की है बल्कि कानून की एक बड़ी कमी को सुधारा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह इस फैसले पर एकमत थे, वहीं जस्टिस बी वी नागरत्ना फैसले से आंशिक रूप से सहमत थे जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जताई। विद्वान जजों ने निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन मानने हुए राज्य द्वारा कब्जा करके या अधिग्रहण करके सार्वजनिक भलाई के लिए वितरित करने के अधिकार पर रोक लगाते हुए कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार एक हद तक ही निजी सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह भी रेखांकित कर दिया कि आपातकाल के समय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के साथ समाजवाद शब्द जोड़कर भारतीय शासन व्यवस्था में समाजवादी तौर-तरीके अपनाने का जो काम किया गया था, वह निरर्थक एवं औचित्यपूर्ण नहीं था। अच्छा हो कि इस निरर्थकता को वे लोग भी समझें, जो संपत्ति के सृजन से अधिक आग्रहित उसका पुनर्वितरण करने पर देते हैं। यह देश को समृद्धि की ओर ले जाने का रास्ता नहीं है। ही भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर का अनुभव यही बताता है कि जिन देशों ने अपने लोगों की भलाई के नाम पर अतिवादी समाजवादी तौर-तरीके अपनाए, वे आर्थिक रूप से कठिनाइयों से ही घिरे। आज जबकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उसे अधिक तीव्र गति मिल सकेगी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। अर्थ-व्यवस्था एवं बाजार को तीव्र गति देने के लिये निजी क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने महाराष्ट्र के एक मामले में संविधान पीठ को भेजे गए कानूनी सवालों का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीतियां तय करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोगों ने सरकार को वोट दिया है। लेकिन यदि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जाएगा, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन है, इसलिये इसे रोकना कानून के दायरे में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि 1990 के बाद से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है और अब बाजार उन्मुख आर्थिक मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिये राष्ट्रवादी सोच जरूरी है। संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जस्टिस अय्यर का दृष्टिकोण समाजवादी थीम पर आधारित था और इससे सहमति नहीं जताई जा सकती। 1977 में कर्नाटक बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले में जस्टिस अय्यर ने निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन बताया था। 1982 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने जस्टिस अय्यर के फैसले से सहमति जताई थी। लेकिन अब उन फैसलों की भावना एवं लक्ष्य को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिक उपयुक्त एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया है। यह फैसला सरकारों की इस दिशा में मनमानी को रोकता है। इस तरह निजी संपत्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने करीब चार दशक पुराने उस फैसले को खारिज करने का काम किया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करने की आवश्यकता भी समझी कि उक्त फैसला एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी पता चल रहा है कि देश को किसी विशेष प्रकार के आर्थिक दर्शन के दायरे में रखना ठीक नहीं है और आर्थिक तौर-तरीके ऐसे होने चाहिए, जिनसे एक विकासशील देश के रूप में भारत उभरती चुनौतियों का सामना कर सके। देश का आर्थिक मॉडल बदल चुका है और इसमें निजी क्षेत्र का बहुत महत्व है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीपट्टा रोड़ खण्डवा,जिवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बाईपास जिवाई, रोक फोन नं.01432